Status of implementation of the recommendations contained in the 145th and 153rd Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I rise to lay the statement regarding Status of implementation of the recommendations contained in the 145th and 153rd Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 4) of the Ministry of Ayush.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIRMAN

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there are about 46 more speakers on the Discussion on Motion of Thanks on the President's Address. If the House so agrees, we may skip the lunch recess today and continue the discussion so as to enable the hon. Members to participate in the discussion. Do I have the leave of the House to dispense with lunch hour today?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, there will be no lunch recess today.

#MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS — *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Further Discussion on the Motion moved by Shri Sudhanshu Trivedi on 28th June, 2024. On 1st July, 2024, Shri Birendra Prasad Baishya had not concluded his speech while participating in the discussion. He may continue now. Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, six communities of Assam, including Tai-Ahom, Moran, Matak and Koch-Rajbongshi, have been demanding the Scheduled Tribe community status. I hope the Government will take appropriate action to recognise those communities as tribal communities immediately.

Further discussion continued on a motion moved on 28th June, 2024.

Assamese culture and Assamese identity is under threat today due to the illegal influx of Bangladeshis in Assam. I urge upon the Government to make necessary arrangements in order to give the constitutional safeguards to the people of Assam, especially the indigenous people of Assam.

Then, flood and erosion is the biggest problem of our State. Before independence, the per capita income of the Assamese people was higher than that of the people living in any other part of the country, but due to the flood situation, our economy has gone down. So, I request the Government to declare Assam's flood and erosion problem as a national problem and do justice to the people of Assam. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ashokrao Shankarrao Chavan. It is his maiden speech. Shri Chavan has been the Chief Minister of Maharashtra twice, Member of Lok Sabha twice, four-time MLA and also MLC.

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्र): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने संक्षेप में मेरे बॉयोडेटा का जिक्र किया। मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस से ही चुनकर आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। महोदय, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया था, उस प्रस्ताव के समर्थन में अपने चंद विचार यहां प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले इस सभागृह में जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, उन पर रोशनी डालने की मेरी मनोकामना है और मैं यहां पर कुछ बोलना चाहूंगा। महोदय, आपने परसों इस सभागृह में एक बहुत जरूरी बात कही थी। हर चीज़, जो इस सभागृह में, इस हाउस में कही जाती है, उसके authentication के बारे में आपने जिक्र किया था कि यहां जो भी बातें होती हैं, वे जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में और पूरे विश्व में इसको देखा जाता है और इस सभागृह में जो बातें होती हैं, आम आदमी उनके बारे में बड़ी संजीदगी से सोचता है कि यहां जो भी बोला जाता है, उसमें authenticity या सच्चाई है। हमें इस हाउस में प्रोटेक्शन मिलता है। हम जो भी कहें, उसकी कहीं पर सच्चाई के authentication की backing होनी चाहिए। यह बहुत अहम बात आपने यहां पर कही थी। सर, आप जानते हैं कि आजकल narrative का जमाना है। चाहे वह narrative सच हो या गलत हो। सर, काम का, विकास का और constituency के वोटर्स का कुछ संबंध रहा है या नहीं रहा है, तो हर मेम्बर यहां देखता है कि उनका क्या अनुभव रहा है, लेकिन बात तो यह है कि एक बार एक narrative सैट हो जाए, चाहे वह सच हो या गलत हो, उस narrative के हिसाब से ही बातें आगे चलती हैं और उसमें फिर कभी सक्सेस मिलती है, तो कभी आदमी हार जाता है। मैं यह बयान करना चाहूंगा कि इस चुनाव में संविधान के बारे में जो बातें हुई हैं, वे सरासर गलत हैं और इस देश में गलत narrative सैट किया गया कि भाजपा इस संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए देश में बहुमत की मांग हो रही है। इस बात का पूरे देश में narrative सैट हो गया था। महोदय, कई मेम्बर्स ने यहां पर बताया कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। पोलिटिकल भाषण तो जरूर हुए हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि 1973 के Kesavananda

Bharati case में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर कुछ चीजें कही थीं। Kesavananda Bharati case में 13 जजेज का जजमेंट है, जिसमें बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "The basic structure doctrine of the Constitution, which holds that certain fundamental features of the Constitution, such as democracy, secularism, federalism, and the rule of law cannot be amended by Parliament. The significance of the Kesavananda Bharati case lies in the fact that it established the doctrine of basic structure of the Indian Constitution. The basic structure doctrine holds that certain fundamental features of the Constitution, such as the supremacy of the Constitution, the rule of law, and the independence of the judiciary, cannot be amended or abrogated by the Parliament through a constitutional amendment." महोदय, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। इस बात से जो narrative सैट होता है, इसकी कुछ मालूमात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इलैक्शन के दौरान प्रधान मंत्री जी ने इस पर काफी चर्चा की और सच्चाई, सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एक narrative बन गया था, जिसके तहत देश में अलग-अलग मत प्रवाह बन गए थे। हमें लगता है कि कानून के दायरे में कुछ चीज़ें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिसका जिक्र हुआ है, वह सच्चाई भी लोगों के सामने आनी जरूरी है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि कल इस हाउस में हमारे संसद परिसर में स्थित महापुरुषों की मूर्तियां हटाने की बात पर काफी बवाल हो गया था। आप सब जानते हैं कि चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मां जिजाऊ हों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी हों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी हों या अहिल्याबाई होल्कर जी हों - सभी संत महंतों के बारे में हमारे देश में सर्वोच्च विचार हैं। इनके नाम आदर से लिए जाते हैं और इनके विचारों पर चलने वाला हमारा देश है। Across party lines इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इधर कुछ और सोचते हैं, उधर कुछ और सोचते हैं। यह बात ही नहीं है। महोदय, सबसे important बात यह है कि इस हाउस में संसदीय कार्य मंत्री जी ने बयान दिया है कि ये मूर्तियां हटाई नहीं जाएंगी, बल्कि एक अलग सुंदर स्थल बनाकर उनको हम लोग लगाएंगे। ताकि हर व्यक्ति इन महापुरुषों के सामने नमन करके हाउस में जा सकता है। इस स्थल पर, वहां पर कार्य चल रहा है। ...(**व्यवधान**)... देखिए, ऐसा है कि ...(**व्यवधान**)... सर, आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए कि मैं अपने विचार यहां पर रख सकूं। मेरा कहना यह है कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nasir, can you give up this habit? *..(Interruptions)..* What is this? *..(Interruptions)..*

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण : सभापति महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। जब इस हाउस में संसदीय कार्य मंत्री जी एक बयान देते हैं, तो वह रिकॉर्ड पर चला जाता है। आपने खुद भी इस चीज़ को देखा है। सवाल यह है कि हाउस में दिया हुआ, जो हाउस में स्टेटमेंट दी गई है, उसका बहुत महत्व है और वह रिकॉर्ड पर है। जो बातें हाउस में कही जाती हैं, उसके बाहर जाकर सरकार नहीं कर सकती है। It is a commitment to the House. इस पर प्रिविलेज मोशन हो

सकता है। सभापति महोदय, इस प्रकार की बातें हाउस में करके जब लोगों को * करने की बात होती है, तो हमें बड़ा दुख होता है। यह पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स का मामला है, इस बात को जरूर हाउस में दोहराना चाहिए कि इस पर इम्पलिमेंटेशन जरूर होगा।

सभापति महोदय, नीट के बारे में हाउस में काफी चर्चा हुई है। संसद के दोनों सदनों में, इसके बारे में किसी के दो मत नहीं हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, चाहे वह नीट की परीक्षा हो या और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उनकी परीक्षाओं के बारे में सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं यहां पर देवेगौड़ा साहब का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने समर्थन में कहा कि जब तक सीबीआई इन्क्वायरी की पूरी मालूमात नहीं आ जाती है, तब तक इसमें कोई अलग से भूमिका लेना जरूरी नहीं है। इस समय इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो इस तरह का चित्र निर्मित किया जा रहा है कि जैसे सरकार इसका समर्थन कर रही है - वह सरासर गलत है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो culprits हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, इसमें किसी की अलग से भूमिका नहीं है।

सभापति महोदय, यह भी सच है कि ऐसे इंसिडेंट्स कई राज्यों में हो रहे हैं, इससे जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं और उनके जो पैरेंट्स हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव बढ़ता है। यदि आप नीट या जेईई की परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो जीवन व्यर्थ है, इस तरीके की एक भावना स्टूडेंट्स में निर्मित हुई है, इससे मानसिक संतुलन खोने की बातें होती हैं। सभापति महोदय, इस पर सदन में बहुत गहराई से चर्चा होने की जरूरत है और इसके ऊपर सरकार कोई ठोस कदम उठाए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। सरकारी भर्ती तथा शिक्षण संस्थानों की परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं को रोकने के बारे में, सख्त कानून बनाने के बारे में मैनिफेस्टों में बीजेपी ने इसका जिक्र किया है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है और निश्चित तौर पर यह जरूरी है और यह अहम सवाल आज लोगों के सामने है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण दिया है, इसमें केंद्र के पिछले दस सालों का लेखा-जोखा संसद में रखा है और आने वाले समय के रोड मैप का भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से जो संकल्प लिया है, उसको अचीव करने के बारे में क्या बातें उनके दिमाग में हैं और सरकार क्या करने जा रही है।

सभापति महोदय, हमारे देश में सबसे बड़ा चुनाव हुआ है। अगर दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहीं है, तो वह भारतवर्ष में है। भारतवर्ष की इस डेमोक्रेसी के चुनाव को बड़े नज़दीक से, करीब से लोग देख रहे हैं। इसका जो चैलेंजिंग टास्क था, हमारे सामने और पूरी दुनिया के सामने उत्सुकता थी कि देश का चुनाव किस तरीके से सम्पन्न होगा। इस चुनाव में 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने सहभाग लिया है। लोकतंत्र के सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग यहां पर 64 करोड़ लोगों ने किया है। देश भर में तकरीबन 66 प्रतिशत लोगों ने वोटिंग की है। मैं समझता हूं कि 66 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग की आवश्यकता थी, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो आम चुनाव का शैड्यूल सात चरणों का किया था, उसमें वीकएंड्स बड़े पैमाने पर थे, इसलिए

* Expunged as ordered by the Chair.

वीकएंड्स पर कुछ लोग छुट्टियां मनाने चले गए, कोई अपने काम के लिए निकल गया। इसमें यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि जब इलेक्शन होता है, तब उसमें वर्किंग डेज़ होने चाहिए, तभी वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो सकता है। सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर के इलेक्शन के बारे में जिक्र हुआ। जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड मेकिंग वोटिंग हुई है। वहाँ 5 लोक सभा सीटों के लिए 58 प्रतिशत वोटिंग हुई है। यह पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है कि वहाँ लगभग 58 प्रतिशत वोटिंग हुई है। 2019 के लोक सभा चुनाव में वहाँ 44 परसेंट वोटिंग हुई थी। मैं समझता हूं कि यह जो 14 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है और कश्मीर के विकास में मोदी सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, उसका यह प्रमाण है, जो बताता है कि लोग आज खुलकर वोटिंग के लिए निकल पड़े हैं। इसका रिज़ल्ट कुछ भी आया हो, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ लोग वोटिंग के लिए बाहर निकले हैं।

सभापति महोदय, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुईं। रोड, रेलवेज़, एयर कनेक्टिविटी आदि के बारे में लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी बातें कही हैं और मैं समझता हूं कि यह प्रशंसनीय है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी शेप ले रहा है। इसमें चाहे रोड की अचीवमेंट हो, रेलवेज़ की कनेक्टिविटी हो, बुलेट ट्रेन की बातें भी हो रही हैं, परंतु हमारी अपेक्षा यही है कि राज्य के पिछड़े हुए हिस्सों में भी यह कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें निश्चित तौर पर बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है। इसमें एयर कनेक्टिविटी की सुविधा, जो 'उड़ान स्कीम' के तहत आजकल देश के हर जिले में मिल रही है, वह ऐसे पिछड़े जिलों को भी मिले, ताकि उन्हें भी राज्यों की कैपिटल से जोड़ा जाए। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, जिसके कई जिले अभी भी मुंबई से जुड़ने बाकी हैं, लेकिन उन्हें मुंबई में स्लॉट नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है और जगह नहीं मिलने के कारण मुंबई जैसे शहर से इन राज्यों की कनेक्टिविटी जुड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

सभापति महोदय, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल करने की मंशा रखी है। मैं समझता हूं कि जो 'नमो ड्रोन दीदी योजना' बनाई गई है, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर, खास कर के महिलाओं को निश्चित तौर पर रोज़गार देने की बातें इसमें कही गई हैं।

सभापति महोदय, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार ने एनाउंस किया है, वह भी निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम उठाया गया है। यदि मैं आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कहूं, तो किसानों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की आ रही है। आज किसान इस समस्या से बहुत परेशान हैं। उनकी उपज के दाम कम, ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो एमएसपी है, उसमें पिछले दस सालों में 65 से 185 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। महोदय, मैं यह बात खास तौर पर रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, किसानों की अन्य शिकायतें भी हैं। किसानों के द्वारा अभी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एमएसपी का एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि ऐसे कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, 'प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना' के तहत जो मकान मिलने वाले हैं, उसमें आम आदमी को, गरीब आदमी को इस ऊर्जा के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इस सोलर हाउसिंग व्यवस्था के ज़रिए मुफ्त में मकान की बिजली की सुविधा प्राप्त हुई है।

सभापति महोदय, वक्त की कमी के कारण मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी यहाँ जो भी बातें कही गई हैं - कल हमारे कुछ सदस्य यहाँ पर ज़िक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के हमारे एक सदस्य ने यहाँ पर ज़िक्र किया कि यहाँ हार हुई है, वहाँ हार हुई है आदि-आदि, हमारे एक सदस्य ने कहा कि नांदेड़ में भी हार हुई है। महोदय, उन्होंने इसका ज़िक्र किया है। मुझे पता है कि हमारे नांदेड़ में रुचि रखने वाले काफी लोग हैं, इसका यहाँ ज़िक्र हुआ है, इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब-जब महाराष्ट्र में कहीं पर भी सीटें नहीं आई थीं, उस वक्त नांदेड़ की भी सीट आई थी और हिंगोली की भी सीट आई थी। कांग्रेस की सीट आई थी और वह सीट लाने में मेरा छोटा-सा योगदान जरूर होगा - मैं यह विनम्रता से कहना चाहूंगा। महोदय, हम जहाँ भी थे, हमने वहाँ पर ईमानदारी से काम किया है और सीटें भी लेकर आए हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ सदस्य हैं, जिनके जिलों में अभी भी वहाँ से पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर नहीं आ सके हैं। यह स्थिति हर किसी जिले में दिखाई देती है। मुझे इस पर व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस बात का ज़िक्र हुआ है, इसलिए मैं यहाँ इसकी सफाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि,

'जीत पर कभी अहंकार नहीं किया
किसी हार पर कभी रोया नहीं।
लेकिन हर हार के बाद मैं
चैन से कभी बैठा नहीं।'

सभापति जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त थोड़ा कम था, पर आपने बोलने की इजाज़त दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we have set a good example.

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): मैं आपका आभारी हूँ... ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Have I called your name? ...(*Interruptions*)... तो बैठिए। ...(**व्यवधान**)... We have set a good example that Shri Ashokrao Shankarrao Chavan was heard with rapt attention. Shri Pramod Tiwari and all other speakers are required to be heard with rapt attention. It is not a place where we sit on armchair and shout. Now, Shri Pramod Tiwari. Please give patient hearing.

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) : मैं आभारी हूँ अपने नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मौका दिया।

मान्यवर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मैंने कई बार देख डाला। ऐसा लग रहा है कि...

श्री सभापति: देखा या पढ़ा? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारीः सर, देखकर पढ़ा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः अच्छा, ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी : सर, ऐसे ही नहीं पढ़ लिया, देखकर पढ़ा। ...(**व्यवधान**)... राष्ट्रपति जी का पूरा अभिभाषण एक थका हुआ, हारा हुआ, पहले से कम हुआ, एक निराश सरकार का आईना लग रहा था, जो अभी हार से उबर नहीं पाई है। ...(**व्यवधान**)... फिर भी... ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ...(**व्यवधान**)... नीरज जी, नहीं, नहीं। ...(**व्यवधान**)... I will not withstand anyone disturbing any speaker. Please bear with me. You please continue.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल की कमरतोड़ महंगाई का समाधान निकालने की कोई कंक्रीट योजना मुझे इसमें नहीं दिखाई पड़ी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Can you please keep quiet?

श्री प्रमोद तिवारी : 40 साल इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ...(**व्यवधान**)... 40 साल की बिगेस्ट महंगाई, मतलब 40 साल में ऐसी महंगाई कभी नहीं हुई है। ...(**व्यवधान**)... आपके तो दस साल ही हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब जीत-हार की बात हो, तो इसी सदन में आखिरी दिन नारा लगा था - अबकी बार 400 पार, जबकि रह गए 240 पर, बहुमत के लिए चाहिए 272, तो अब बैसाखी के सहारे या अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनाई जाए और आप खुश हैं, तो कोई बात नहीं, पर 400 का क्या हुआ, इसका जवाब मैं चाहूँगा और क्यों हुआ, इस पर आप विचार करिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यह बैसाखी पर चलने वाली सरकार है और इनकी भविष्यवाणी गलत हुई है। मान्यवर, इसी तरह से, 38 ईअर्स की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज देश झेल रहा है और मुझे इसमें इसका समाधान निकालने की कोई भी योजना नहीं दिखाई पड़ी। अगर है, तो बता देंगे। मान्यवर, अगर हृदय होगा, जिन लोगों ने देखा होगा - एक महिला के साथ सड़क पर बलात्कार और उसके बेटे को उसी के सामने गोली मार देना! मैं मणिपुर का जिक्र कर रहा हूँ। मणिपुर के बारे में पूरी खामोशी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक संवेदनशील राज्य, जो सीमा पर है, उसके बारे में कोई... ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Have you not understood what I have said? I will not accept this side or that side interrupting any speaker. Both sides, please have it from me that if anyone creates some kind of a disturbance or disruption, he will be forcing my hands. You do not have to make your presence felt when someone else is speaking from this side or that side. Bear this in mind.

श्री प्रमोद तिवारी : धन्यवाद। मान्यवर, इसमें इसका भी जिक्र नहीं है। बहुत दृढ़ता से कहता हूँ और मजबूती से कहता हूँ कि * अध्याय है। हमारे 21 सैनिकों को लद्दाख में शहीद कर दिया गया। उसे हम कैसे वापस लेंगे, इसका कोई तसकरा, कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है।

मान्वयर, मैं चाहता हूँ कि अपनी बात कहने के लिए कुछ बीती हुई बातें याद दिला दूँ। जो वायदे थे, अब उनके लिए तो मैं कहूँगा कि * हैं। अगर अच्छा न लगे, तो * मान लीजिएगा और आपको वह भी अच्छा न लगे, तो* मान लीजिएगा, जो भारत की जनता के साथ इस सरकार ने किया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You will have your turn. ...*(Interruptions)*... I am here to take note of it. ...*(Interruptions)*... Their leader would speak. After some time, your leader would speak. Do you want this chaos? Why don't you get the message loud and clear? ...*(Interruptions)*... Please! Both sides have to help me. I will take a very strong view, either side. ...*(Interruptions)*... Again! Look at Shri Jairam Ramesh. Incorrigible! There is something wrong with him. ...*(Interruptions)*... There is a problem with you. ...*(Interruptions)*... It is a chronic ailment for which diagnosis is needed. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी: मान्यवर, पिछले 10 साल में मोदी सरकार में जनता के साथ जो वायदे किए गए थे, उनको तो याद कर लें और बिना उनको याद किए मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। इस देश की जनता के साथ पहला वायदा था कि पिछली सरकारों में जितना काला धन विदेशों में जमा है, मैं उसे ले आऊंगा और सबको 15-15 लाख रुपये दूंगा। यह इनका पहला वायदा था। ...(**व्यवधान**)... मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मुझे तो नहीं मिला है और इधर बैठे लोगों को नहीं मिला है। अब उनको मिल गया हो, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यह एक वायदा था, जो जनता से किया गया था और * हुआ है, यह वायदा पूरा नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)... * शब्द पूरी तरह पार्लियामेंटरी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक स्पेशल एसआईटी बनी थी, पर इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है कि उस एसआईटी की क्या रिपोर्ट है। इसके बारे में आज तक नहीं बताया गया। मान्यवर, दूसरा इनका जनता के साथ सबसे बड़ा वायदा था, * था, खास तौर से बेरोजगार नौजवानों के साथ, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगीं। सच्चाई यह है कि पिछले 7 सालों में मैनुफैक्चरिंग में 54 लाख नौकरियां कम हुई हैं। 10 सालों में 2.5 करोड़ एमएसएमई बंद हुए हैं, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग थे। इनका तीसरा वायदा था कि मैं पैट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा। इसमें भी जनता को * गया, * किया गया। सच्चाई तो यह है कि पैट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और दुनिया के बाजार में कच्चे तेल का दाम कम हुआ है, उसके बाद भी ये दाम बढ़ाते चले गए। इसमें कुछ मजबूरी थी #...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Delete it. ...*(Interruptions)*... It is objectionable. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... प्रमोद जी, जो आप कह रहे हैं, आप खुद चिंतन कीजिए कि कितना गलत कह रहे हैं। This will not go on record. ...*(Interruptions)*... If you have proof, if you have fact.....*(Interruptions)*... The senior leadership is here. ...*(Interruptions)*... I think, you should replace.....*(Interruptions)*... One minute, Mr. Jairam Ramesh. ...*(Interruptions)*... You are so intelligent, so gifted, so talented, you should immediately come and take seat in place of Mr. Kharge because by and large you are doing his job, insulting him. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मेरे टाइम का ध्यान रखिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: खरगे जी, आप सोचिए। ...(**व्यवधान**)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Don't divide. Don't bring that *varna,* Sir. ...*(Interruptions)*... That *varna* system is there still in your mind. That's why you are calling Mr. Ramesh very intelligent, very this and that and I am dull, so that he could replace. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... One minute. ...*(Interruptions)*... खरगे जी, बैठिए। ...(**व्यवधान**).... एक बात सुनिए। खरगे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए दिल को टटोलकर करेंगे, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है, मैंने यह कहा है ...(**व्यवधान**)... आप सुन तो लीजिए। जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर श्री जयराम रमेश टीका-टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)... अभी देखिए, ...(**व्यवधान**)... अभी देखिए, ...(**व्यवधान**)... अभी देखिए, एक problem है, जिसको आपको solve करना है। आपसे मैंने बहुत अनुरोध किया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, आप क्यों ऐसी बात करते हैं? मुझे बनाने वाली यहाँ बैठी हैं - श्रीमती सोनिया गांधी जी। न रमेश बना सकते हैं, न आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया है।

श्री सभापति: खरगे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ...(**व्यवधान**)... मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, सुनिए, सुनिए। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, बैठिए, बैठिए। You cannot run down the Chair every time. You cannot show disrespect to the Chair every time. ...*(Interruptions)*... आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... Never in the history of this country.... ...*(Interruptions)*... Never, Khargeji, in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such

disregard of the Chair as from you. ...*(Interruptions)*... You are forcing me. ...*(Interruptions)*... And, I have said so on a number of occasions. ...*(Interruptions)*... You take it in a manner which is wrong. ...*(Interruptions)*... It is time for you to reflect. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, मुझमें बहुत patience है, बहुत सहनशक्ति है। मैं खून के घूँट पी सकता हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैंने क्या-क्या बरदाश्त किया है, कितना बरदाश्त किया है और आप झट खड़े होकर कह देते हैं। ...(**व्यवधान**)... खरगे जी, आपको किन्होंने बनाया है, यह आप अपने आप जानें, मैंने एक छोटा मुद्दा उठाया। Chidambaram*ji*, please don't do it. ...*(Interruptions)*... मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने twist किया, आप अंदाजा लगाइए। ...(**व्यवधान**)... मुझे भी पीड़ा होती है। ...(**व्यवधान**)... इतनी सी। ...(**व्यवधान**)... No; no. ...*(Interruptions)*... Again, there is a 24X7 functional person. ...*(Interruptions*)... खरगे जी, ऐसा नहीं है, इतने मौके आए हैं, जब आपकी प्रतिष्ठा को पीछे से कितना बड़ा धक्का लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे ही लांछित कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... कल का दिन कितना भयानक था। आपने regret express कर दिया, अच्छा था। आप ऐसा मत कीजिए। मैं simple आदमी हूँ, झुक कर चलता हूँ, जितना झुक सकता हूँ, झुकना चाहता हूँ। कोई कहे कि मैं ज्यादा झुकता हूँ, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। Please, Pramod*ji*, continue and I would appreciate, you conform to facts. Please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी: मैं बहुत ही विनम्रता के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें जो समय चला गया, उसका ध्यान रखिएगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Can you please sit down? ...*(Interruptions)*... Let him complete. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी : मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि चौथा * गंगा मैया के साथ किया गया। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह आग्रह करूँगा कि जब वाराणसी गए थे, तो कहा था कि मैं न आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

मान्यवर, नमामि गंगे परियोजना मई, 2014 में घोषित हुई। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। प्लीज़ बीच में न बोलें। जया जी आप बड़ी सीनियर मेम्बर हैं, प्लीज़। माननीय तिवारी जी, आप बोलें, आपका समय जा रहा है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रमोद तिवारी: गंगा, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। ...(**व्यवधान**)... यह मैंने नहीं, मोदी जी ने कहा है।

श्री उपसभापति: आप इधर देखें। आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जा रही है, किसी और की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

श्री प्रमोद तिवारी: ठीक है। मान्यवर, नमामि गंगे परियोजना की घोषणा मई, 2014 में की गई थी, उसमें 2019 का टारगेट था, अभी 2024 चल रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक सिर्फ 33 परसेंट sewage treatment हुआ है।

मान्यवर, पाँचवाँ * infrastructure के projects को जल्द-से-जल्द जमीन पर उतारना। आज भी कई central sector projects में 831 projects देरी से चल रहे हैं। इनमें 5 लाख 70 हजार करोड़ की cost over-run हुई है। छठा * देश की जनता के साथ यह किया गया कि अगर मैं आ गया तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)... यह 2016 में कहा था कि हम 2022 में करेंगे। 6 साल बाद भी इसके बारे में बात नहीं हुई। सच्चाई यह है कि पिछले 10 सालों में किसानों की आय वास्तव में बढ़ी नहीं, बल्कि घट गई। Input ज्यादा हो गया है और उसकी जो काश्त है, जो फसल होती है, वह कम हो गई है।

मान्यवर, सातवाँ सबसे बड़ा * देश की जनता के साथ यह किया गया कि जब नोटबंदी हुई थी, तो गोवा में बोलते हुए मोदी जी ने कहा था कि "मित्रो, मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए, तो आप जिस चौराहे पर कहोगे, मैं वहाँ खड़ा होकर, देश जो सजा देगा, उसको स्वीकार करूँगा।" 50 दिन तो छोड़िए, आज 8 साल बीत गए हैं। नोटबंदी में जो फैसला लिया था, जो वादा किया था, न वह पूरा हुआ, न काला धन सामने आया, न भ्रष्टाचार और न आतंकवाद पर ही रोक लगी है। सच्चाई तो यह है कि जो काला धन था, उसे white कर दिया गया, कुछ खास लोगों का।

आठवाँ * जो हुआ, वह बुलेट ट्रेन का हुआ कि वह अहमदाबाद से मुम्बई के बीच चलेगी। मान्यवर, वह आज भी सपना है और पूरा नहीं होने जा रहा है।

नौवाँ * जिसे मैं * कहूँगा, कि सभी किसानों को पीएम किसान फंड मिलेगा। किसी को किसान फंड नहीं दिया गया है। अभी बहुत बड़ी संख्या में ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखरः सर,...(**व्यवधान**)... यह क्या है? ...(**व्यवधान**)... कुछ भी बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... पीएम सम्मान निधि ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री प्रमोद तिवारी : उपसभापति जी, जो पीएम किसान फंड का वायदा landless के लिए था, जो खेत मजदूरों के लिए था, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। वह उन्हें नहीं मिला है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

10वाँ सबसे बड़ा * देश की जनता के साथ यह हुआ कि 10 साल में आर्थिक अपराधी जो देश छोड़कर भाग गए हैं, हम उनको ले आएँगे। मान्यवर, आज की तारीख में क्या यह हो पाया? आज भी मोदी जी वहीं हैं - मैं दूसरे मोदी का जिक्र कर रहा हूँ, ललित मोदी का। मान्यवर, जो तीनों-चारों लोग भाग कर गए थे, क्या उनमें से कोई लौटा? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी के इस पूरे अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है और न कोई इरादा दर्शाया गया है।

मान्यवर, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बार का प्रचार, जिसका जिक्र मुझसे पहले बोलने वाले हमारे आदर्श राजनेता कर रहे थे, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। यह कहा गया था और बहुत ही साफ कहा गया था कि जो घोटालेबाज हैं, उनको हम लेकर आएँगे, उनको prosecute करेंगे, परन्तु वह नहीं हुआ। हाँ, एक राज जरूर खुल गया। बहुत से घोटाले हुए, बहुत से आरोप लगे, लेकिन माल कहीं नहीं बरामद हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार उन्होंने electoral bonds पर जो कहा था, वह कर दिखाया और 7,000 करोड़ माल बरामद हुआ। जो बरामद हुआ, इसमें काम दो, धंधा दो, चंदा लो। एक चीज तो यह है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जिन पर ED और CBI की जाँच चल रही थी, उनका slowdown हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी के बाद * **...(व्यवधान)...**

मान्यवर, इसमें एक बात वह भी है, जो हमारी-आपकी जिन्दगी से खिलवाड़ हुआ है, देश की 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिस कम्पनी से electoral bonds में 52 करोड़ रुपये लिये गये थे - उसका नाम लूँगा, तो वे फिर कुछ कहेंगे। वह पुणे की कम्पनी थी। उसको राहुल गांधी जी ने मना किया था और तमाम नेताओं ने मना किया था कि इसको वैक्सीन बनाने - क्योंकि अभी पूरी दुनिया में यह certify नहीं हुआ है कि किसी तरीके से यह सुरक्षित है, लेकिन उसको वह काम दिया गया। AstraZeneca ने U.K. High Court में यह कबूल किया है कि Covid 19 vaccine से Thrombocytopenia Syndrome (TTS) हुआ है, जिससे लोग मरे हैं। देश में चलते-फिरते लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, बैठे हुए मर रहे हैं।

मान्यवर, यह जो कुछ किया गया है, उसमें पहले देखना चाहिए था, ऐसा करने के पहले सोचना चाहिए था। मान्यवर, कहा जाता है कि मोदी हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। यह साधारण इंसान तो नहीं कर सकता है। जो पैदा होता है, जो रहता है, वह तो नहीं कर सकता है। मोदी जी ने ठीक कहा है। अब आप कहेंगे, तो मैं इसे भी ऑथेंटिकेट कर दूँगा। उन्होंने कहा है कि भगवान ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अगर कोई बने हुए फर्जी साधु-संत यह कहते कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता। यहाँ प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ - यह क्या है? मान्यवर, अगर वे बायोलॉजिकल नहीं हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहूँगा कि जब वे बोलें, तो वे यह बताएँ कि वे क्या हैं, कहाँ से आए हैं?...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापतिः प्लीज़, सीट पर बैठ कर बात न करें। कृपया प्रमोद जी को बोलने दें।...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, मेरा यह आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीट पर बैठें।...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारीः मान्यवर, आप इस पीठ पर बैठे थे और मैं यहीं से बोल रहा था।...(**व्यवधान**)... उस समय मैंने एक बात कही थी कि मैं अवध का रहने वाला हूँ और मैं अयोध्या को जानता हूँ, पहचानता हूँ तथा वहाँ कई बार गया हूँ। मैंने कहा था कि अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज पर संकट आता है। चारों शंकराचार्य इसीलिए नहीं आए। आखिर हुआ क्या? आपने मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की, चुनाव अप्रैल-मई में होना था। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि इधर बैठे हुए लोग भगवान राम के सच्चे पुजारी हैं और उधर बैठे हुए लोग भगवान राम के व्यापारी हैं तथा ये भगवान राम का सौदा करते हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, यह ऑथेंटिक है और मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूँगा, कि वहाँ के मुख्य पुजारी ने कहा कि मंदिर गर्भगृह में पानी टपक रहा है। मैं उसकी क्वालिटी पर नहीं जाता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, मेरे तीन-चार मिनट कौन ले गया?

श्री उपसभापतिः आपका समय खत्म हो गया।...(**व्यवधान**)... कृपया आप बैठें।...(**व्यवधान**)... आप दो मिनय में अपनी बात खत्म करें।

श्री प्रमोद तिवारीः मान्यवर, चूँकि भगवान राम का दुरुपयोग करना था, उनके नाम का दुरुपयोग करना था, इसलिए 22 जनवरी को मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी गई, वरना एक साल बाद, डेढ़ साल बाद जब मंदिर का काम पूरा हो जाता, तब तो उसकी प्राण-प्रतिष्ठा हो सकती थी। चूँकि अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी गई, इसलिए भगवान नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। इनको अयोध्या में रगड़ दिया, जिसकी टीस इनके मन से नहीं जा रही है। मान्यवर, जहाँ-जहाँ राम के कदम पड़े, वहाँ से ये साफ हो गए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ राम भी हैं, काशी भी है, मथुरा भी है। आप 63 सीट से घट कर 33 पर पहुँच गए, अगली बार आपका अता-पता नहीं चलेगा। यह भगवान राम का कोप है, सारे भगवान का कोप है। सर, मैंने अब अपनी बात को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मैं एक बात इधर बैठे लोगों की तरफ से, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह कहा गया कि संविधान बदलने का रॉंग नैरेटिव दिया गया, लेकिन अयोध्या के एमपी ने क्या कहा था, राजस्थान में आपके कैंडिडेट ने क्या कहा था, कर्णाटक में क्या कहा था? इन सब लोगों ने संविधान बदलने के लिए कहा था। मैं यह गवाही के साथ, नाम के साथ आपके सामने रख रहा हूँ, पर इतनी चुनौती देता हूँ अपनी तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि अब न आपकी हैसियत रही, न हिम्मत रही कि आप संविधान बदल दें और आप संविधान बदल नहीं पाएंगे - यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस पर हम कृतसंकल्प हैं।

मान्यवर, मेरे से ठीक पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनकी बात सुन कर मुझे यही पता नहीं लग रहा था कि वे इधर से बोल रहे हैं या उधर से बोल रहे हैं। मान्यवर, हमने बहुत सहा है।

राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हमने आदर्श घोटाले में बहुत सहा है। जो लोग कल तक आदर्श घोटाला के बारे में बोल रहे थे, वही आज मेज थपथपा रहे हैं। ऐसी कौन-सी वाशिंग मशीन है, जिसके अंदर टीनोपॉल डाल देते हैं कि इधर बैठे थे, तो आदर्श घोटाला और उधर जाकर निकले, तो आपके साफ-सुथरे नेता बन गए? ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः कृपया आपस में बात न करें। प्रमोद जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारीः मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ।

श्री उपसभापतिः अब मैं अगले स्पीकर को बुलाऊँगा।

श्री प्रमोद तिवारीः सर, आप यह बताइए कि अगर मैं आपसे एक मिनट माँगू और आप न दें, तो हम दोनों दोस्त कैसे हुए?

श्री उपसभापतिः प्रमोद जी, आप ऑलरेडी तीन मिनट ले चुके हैं, इसलिए अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वे लोग ज्यादा बोलते हैं, जो कहीं और से आयात होते हैं। उन बेचारों के साथ जो हो रहा है, स्वतंत्रता के लिए मरे-जिए, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, धन्यवाद। मोहम्मद नदीमुल हक।...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारीः मान्यवर, यह मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी यहीं से गए हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक।...(**व्यवधान**)... माननीय नदीमुल हक।...(**व्यवधान**)... आपका हो गया। आप ऑलरेडी तीन मिनट अधिक बोल चुके हैं, जो आपकी पार्टी से कम हुआ है।...(**व्यवधान**)... माननीय नदीमुल जी, कृपया आप बोलें, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।...(**व्यवधान**)... नदीमुल हक जी, यह आपका समय है, इसलिए आप बोलें। उनकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी।...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी : #

12.00 **Noon**

Not recorded.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Thank you Sir for giving me this opportunity to speak on the President's Address. We thank the President for her Address which we know is written by the Union Government, she just reads it out. I quote from para 3 of the Address-"The world is witnessing that the people of India have elected a stable Government with clear majority for the third term." We respectfully disagree not on a personal basis, but, on what the Address contains. The biggest blunder in the Address is one important word that is missing, and that biggest missing word is 'coalition'. This is a coalition Government; coalition, coalition, coalition. You cannot cover this up. The Modi-led BJP Government has been rejected. The BJP was 36 seats short, hence coalition. This is a coalition with partners and to these partners, I say:

"भँवर जब भी डुबोएगा, उभारा देकर मारेगा,
सुनो ऐ मछलियों तुमको, वो चारा देकर मारेगा,
गलतफहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएँगे,
बड़ा चालाक पार्टनर है, सहारा देकर मारेगा।"

بھنور جب بھی ڈبوئے گا، ابھارا دیکر مار ے گا،[†]
سنو اے مچھلیوں تم کو، وہ چارہ دیکر مارے گا،
غلط فہمی ہے یہ تم کو کہ اچھے دن بھی آئیں گے،
بڑا چالاک پارٹنر ہے، سہارا دیکر مارے گا۔

Sir, the Godi Media created jolly exit polls to keep the BJP happy. Stock markets were manipulated to make huge profits, where the savings of ordinary investors were wiped out. SEBI must do a thorough investigation of this scam. The same 'godi media' called these elections historic. They were historic. Modi*ji* stayed away from Manipur and the people spoke. Faizabad in Uttar Pradesh where Ayodhya is situated has rejected the BJP. They expected 30 seats in Bengal and just hit the double figures in the State of *Ma, Mati, Maanush*. They targeted 400 and only crossed 200 seats. The Prime Minister himself was trailing in his Constituency in the morning of the results. These results are historic. The BJP lost and the Constitution of India has won.

The 29th paragraph of the President's Address says, "When Parliament conducts its business smoothly, then, the people repose confidence not only in the Government, but also in the entire system." Sir, the number of sittings per year of Lok Sabha has reduced from an average of 121 days to just 70 days. The 17th Lok

[†] Transliteration in Urdu Script.

Sabha did not have a Deputy Speaker for its entire five years term. Nine out of ten Bills introduced have been marked by zero or incomplete consultations. No discussion on matters of national importance suggested by the Opposition under Rule 267 has been accepted in the last eight years. The Prime Minister has not answered a single question on the floor of Parliament and the Government talks about competitive, cooperative federalism.

Now, let us talk about the double standards of the BJP Government. We all know the story of Chief Minister Hemant Soren and Chief Minister Arvind Kejriwal. The Union Government has repeatedly encroached upon the exclusive subject matters on the State list. This includes the abolition of Article 370, the Farm Bills, non-payment of GST dues to the States and the abolition of the Planning Commission. On behalf of the All India Trinamool Congress, this is my open challenge to the Prime Minister. Release a white paper proving you have paid even one rupee to the State of West Bengal under MGNREGA and the Awas Yojana since the BJP were routed in the 2021 Assembly elections in Bengal. Sir, 59 lakh MGNREGA workers, 11 lakh Awas Yojana beneficiaries were deprived. Rs. 15,000 crores is owed to Bengal under these two schemes. This is the politics of vendetta.

Sir, let us talk about *Gareeb, Yuva, Annadata and Nari* or rather the injustice being done to them. As per the ILO, one in every three youths is not in education, employment or training. Forty-two per cent graduates below the age of 25 are unemployed. Over 35,000 MSMEs have been shut down between 2020 and 2024. Instead of touting exaggerated numbers of doubling farmers' income, the Government must do what is right. The Government must apologise to the families of Bishant Singh, Gurjant Singh, Zira Singh, Manjeet Singh, Darshan Singh and Karnail Singh. Let me tell you who they are. They are not mere statistics or names or numbers. These were 60, 70 or 80-odd farmers who spent their lives feeding the nation. In their old age, they were forced to the streets to fight for their livelihood. The Government should lower its head in shame and seek forgiveness from the family of Shubh Karan Singh, a 21-year old farmer who was shot dead by the police.

Sir, 30 farmers commit suicide every day in India. We have to think about this. The BJP can never respect or give women equal opportunity. ...(*Interruptions*)... I have to ask many questions on this. Why did the BJP send only 13 per cent women MPs in the 18th Lok Sabha?

श्री उपसभापति: प्लीज़, आपस में बात न करें।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Why did they * the women? ...*(Interruptions)*... Why did they * the nation?

श्री उपसभापति: आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। Please take your seat.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Why did they * the nation about Women's Reservation Bill? Why could not the BJP learn from the All India Trinamool Congress which has sent 38 per cent women MPs to Lok Sabha? Why have six lakh ASHA workers from all over the country been protesting against exploitative working conditions that have pushed them to the brink of poverty? Why did the BJP reward their MP who sexually assaulted our nation's champion women wrestlers and even made his son a candidate? Why did the BJP free the Bilkis Bano's rapists? What about Hathras? What about Unnao? What about more than 800 cases of assault on SCs women in Uttar Pradesh? What about the video that exposed the Sandeshkhali? What about that?

हम इस दौर के, अंदाज़ निराले देखे,
फैसले कत्ल के, कातिल के हवाले देखे,
† ہم نے اس دور کے، انداز نرالے دیکھے،
فیصلے قتل کے، قاتل کے حوالے دیکھے،

Sir, about the paper leaks, INDIA MPs wanted the voices of 33 lakh young students who were cheated to be heard in both the Houses on Friday. The Coalition Government did not have any answer, which did not allow it.

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप दोनों बैठ जाएं।

AN HON. MEMBER: Please bring the House in order.

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप अपनी जगह बैठें। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। No, you are not allowed. ...(*Interruptions*)... Please take your seats. ...(*Interruptions*)... Or else, I will be forced to take your names. ...(*Interruptions*)... आपस में कोई बात नहीं करेगा। ...(**व्यवधान**)... मैं आग्रह करूंगा ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. You are not allowed.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, on paper leaks, I will say this much.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

† Transliteration in Urdu Script.

पेपर लीक में विनीत भागा, सोता चौकीदार है
कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू ज़िम्मेदार है।

सर, इस बात के कोई मायने हैं? Sir, the President's Address says and I quote: "Development works in the North-East are being taken up in every field including education, health, tourism and employment." Let me say about Manipur. Sir, 219 deaths, 60,000 people were displaced, 14,000 school-going children are affected. Why has the Prime Minister not visited Manipur even once in the last one year? Is this a demonstration of heartlessness, * or simply arrogance?

Sir, I began my speech with election results. The people of India have given a clear message. I don't know whether this message is biological or non-biological. But the message is, protect India's institutions. Don't turn these institutions into party offices or Shakhas. Stop using CBI, Raj Bhavans, ED and Income-Tax for political vendetta. I was saddened when people referred to the Election Commission as entirely compromised. But, was there some truth in it? सर, क्या आत्मनिर्भर भारत अब परमात्मा निर्भर हो रहा है? I wanted to end my speech with election campaign. * My great India has rejected this divisive and offensive politics. The farmers, the youth, the women, the marginalized have rejected Modiji's and BJP's idea of India. India won, not just the T20 World Cup but, more importantly, Constitution of India won and Modi's BJP has lost.

So, I end with this couplet.

"दीप है तेरा नफरत वाला,
देखें कब तक जलता है
कोई बता दो इस पागल से
सूरज भी तो ढलता है।"
دیپ ہے تیرا نفرت والا،†
دیکھیں کب تک جلتا ہے
کوئی بتا دو اس پاگل سے،
سورج بھی تو ڈھلتا ہے۔

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु): उपसभापति जी, हमारे साथी नदीमुल हक जी बहुत अच्छा बोले हैं। हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं और हम लोग नॉर्मली टोकते नहीं हैं, केवल सुनते हैं। जब कोई विषय एलीगेशन के रूप में substantiate नहीं होता है,

* Expunged as ordered by the Chair.

† Transliteration in Urdu Script.

तभी टोकते हैं। वरना, हम तो यह चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि 14वीं लोक सभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से अकेली ममता जी जीत कर आई थीं, उस समय कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो प्रहार हुआ था, उसमें ममता जी को बचाने वाली सारी भारतीय जनता पार्टी ही थी। आप इस बात को भूल गए हैं। नदीमुल हक जी हमारे दोस्त हैं और इनसे निजी तौर पर कुछ नहीं है।...(**व्यवधान**)... लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी के ऊपर आपने जो निजी हमला किया है, मैं उसी पर आपत्ति व्यक्त करना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री देश का होता है। ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री देश का होता है। देश के लोगों ने प्रधान मंत्री चुना है...(**व्यवधान**)... इसलिए प्रधान मंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखिए। नरेन्द्र मोदी जी हमारे अकेले के प्रधान मंत्री नहीं हैं, वे देश के प्रधान मंत्री हैं। इसलिए उस पद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज, अपनी जगह पर बैठिए। किसी और की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, प्लीज। माननीय नदीमुल हक जी please take your seat. ...*(Interruptions)*... No; I am not allowing. ...*(Interruptions)*...Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Nadimulji, please be brief.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : सर, ममता जी को उनके डिफेंस की जरूरत नहीं है। Mamataji is a great leader. She is part of INDIA coalition and she is very much there. ...*(Interruptions)*...I will tell you this much. We have defeated the BJP in Bengal. We have shown them the door. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Noting is going on record. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, प्लीज़, आप बैठें। आप बिना चेयर के परमिशन के खड़े न हों। ...(**व्यवधान**)... बिना चेयर की परमिशन के आप खड़े न हों और कोई भी न खड़ा हो।...(**व्यवधान**)... मैं सारे सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर जानते हैं। मैं सबके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर के एक अंश का उल्लेख करना चाहूंगा। It is Rule 238A. It says, "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given previous intimation to the Chairman and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply." ...*(Interruptions)*... There are a number of things. ...*(Interruptions)*... Please take your seat, Mr. Gokhle. आप हर चीज में खड़े क्यों हो जाते हैं। जो आपसे अपेक्षा की जाती है, मैं उस रूल को क्वोट कर रहा हूं। प्लीज, गोखले जी आप बिना बोले क्यों खड़े हो जाते हैं। Mr. Gokhale, please take your seat. ...*(Interruptions)*... I will be forced to name you today. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Yerram Venkata Subba Reddy. ...*(Interruptions)*...प्लीज़, आपस में बात न करें।

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you hon. Deputy Chairman, Sir, for granting me the opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks to the President's Address. Sir, on behalf of my party, the YSR Congress Party, and our leader and former Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, I extend my gratitude to the hon. President for her Address and highlighting various priorities and achievements of the Government. I also thank my party President and former Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, for having given me this opportunity to present our party's views in this august House.

I would like to address the following critical issues very briefly. The first one is reforming the Indian testing system. Sir, the NEET-UG exam is taken by over 70,000 aspirants from Andhra Pradesh each year out of a total of 23 lakh students. Of these, only around 2,000 students are selected to study at AIIMS. There is a significant shortage of seats in Government medical colleges. Despite the increasing number of applicants, the availability of seats and colleges has not risen proportionately. Currently, there are only 55,648 Government medical college seats. This number must be increased to at least one lakh to ensure fair opportunities for NEET aspirants to realise their dreams of becoming doctors.

Secondly, there is a need for strengthening public health infrastructure to deal with pandemics. The COVID-19 pandemic underscored the importance of robust public health infrastructure to handle health emergencies. In 2024, preparing for potential pandemics remains a national priority. According to a report of the Global Health Security Index, India ranks poorly in terms of pandemic preparedness, with significant gaps in health infrastructure, disease surveillance, and emergency response systems. The Central Government should invest in upgrading healthcare facilities, including increasing hospital beds, and ICU units, and stockpiling medical supplies. Improving the National Centre for Disease Control and deploying advanced technology for real-time disease surveillance are essential. Training healthcare staff in emergency response and establishing research facilities for infectious diseases are vital steps towards strengthening the public health system.

I would like to hereby remind this august House the special concern our leader and former CM Shri Jagan Mohan Reddy had towards the health care sector in the State of Andhra Pradesh. Sixteen new Medical colleges were established in the last five years. This was solely done for the purpose of increasing the number of seats to ensure that more doctors are able to finish their studies at an affordable cost and speciality treatment is available to the poor and needy at a place near to their homes. The implementation of the 'Family Doctor' concept and introducing village clinics and

health camps were one of the first of its kind activities taken up in the State of Andhra Pradesh during the last five years in health sector.

Now I come to the point of relief to farmers. I thank the hon. President and the Government of India for providing ₹3.20 lakh crores to farmers under the *PM Kisan Samman Nidhi* and increasing the MSP for various produces. However, there is still much work to be done. I urge the Government to increase the financial assistance provided under *PM Kisan Samman Nidhi* from ₹6,000 to ₹10,000.

I appreciate the Government for making changes in the agricultural system in line with the current requirements. Currently, demand for organic products is increasing rapidly in the world. I urge the Government to strengthen the natural farming and create robust supply chains for the related products. I also request the Government to increase the MSP so that the hard-working farmers can get remunerative prices for their produce.

Sir, special care should be taken to ensure that the farmers are covered under crop insurance so that they are properly compensated, especially when the harvest suffers due to global warming, like, sudden heat waves or the highly unpredictable rainfall. Farmers should not be made to suffer unnecessarily.

Now, I come to railway safety. There is a need for enhanced Budget allocation for safety and modernization of railways. The Indian Railways requires a significant increase in budget allocation to address critical safety and modernization needs. The merger of the Railway Budget with the General Budget in 2017-18 has led to a decrease in its share from 15 per cent to a mere 10 per cent. This reduction has hindered the comprehensive implementation of advanced safety technologies such as the Train Collision Avoidance System and the Kavach Anti-collision System. It has to be specially noted that the last major accidents in Bengal, Odisha and Andhra Pradesh took place in a span of less than five months and that too in the Eastern Region. So I urge the Government to take steps to prevent the precious loss of lives. By increasing the Budget allocation, the Central Government can ensure the widespread deployment of these safety systems, upgrade old tracks, and improve overall railway infrastructure, thereby reducing the frequency of accidents and enhancing operational efficiency.

I also request for the operationalisation of the Railway Zone for which land has already been identified by the previous Government. The pending railway project especially the Nadikudi-Srikalahasti line which was sanctioned in 2014 also need to be completed. The Vizag Chennai coastal corridor also needs to be completed soon. In addition to that, the road connecting Vizag Port to the Bhogapuram International Airport also needs to be completed at the earliest.

Sir, I congratulate the Government for taking Metro to 21 cities in the country. Here, I also request the Government to take steps to ensure that Vishakhapatnam Metro is sanctioned. And, since the Bhogapuram International Airport is coming up, I request the Government to sanction the Metro from the Bhogapuram International airport to Vishakhapatnam.

Sir, now I come to Andhra Pradesh related issues. Our hon. former Chief Minister, Jagan Mohan Reddy *Garu* had met the hon. Prime Minister and the Home Minister many times and each time he requested for Special Category status for Andhra Pradesh. But, today, this opportunity has come to the Telugu Desam Party as not only are they in power in Andhra Pradesh; they are also sharing power with NDA Government, at the Centre. So, all that the Telugu Desam Party has to do in this situation is to ask the Central Government for Special Category status for the people of Andhra Pradesh so that this dream of all the people of Andhra Pradesh is fulfilled.

Sir, the Special Category status is not a mere demand but a right of the people of Andhra Pradesh who have suffered immensely due to the unjust bifurcation. The State has also faced several challenges in resolving the pending issues related to the bifurcation such as sharing of assets and liabilities, allocation of employees, division of institutions and the completion of projects. However, rather than demanding Special Category status over the last five weeks after the result has come, *

Sir, I also request the Central Government to take steps to complete the Polavaram Project as early as possible. Necessary funds may be sanctioned for the speedy completion of the Polavaram Project.

I would like to request the Central Government to stop the privatization of Vizag Steel Plant. I also request the Finance Minister to sanction sufficient funds to revive the plant as a special package. The Government should also provide captive mines on a preferential basis to Vizag Steel Plant.

Thus, I urge the Central Government to insist upon the State Government, which is also a NDA partner there, to ask for Special Category status for Andhra Pradesh on priority basis. I would also urge, through you, to the Government to take steps to ensure that peace is restored and democratic practices are followed in our State of Andhra Pradesh. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri P. Wilson. You have eight minutes.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, mike is not working.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mike is already on, Mr. Wilson.

SHRI P. WILSON: Mr. Deputy Chairman, Sir, I will be requiring a few minutes. We can adjust it from our group.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The time which is mentioned here is eight minutes; you have to stick to it. Please.

SHRI P. WILSON: Okay, Sir. Sir, I thank the hon. President for delivering the President's Address prepared by the NDA Government. I take this opportunity to argue for the rights of my nation and for my State.

Firstly, I would like to start with NEET. Considering the fact that the NEET based selection process is against the students from poor and under-privileged background, Tamil Nadu has always opted for the MBBS selection process through 10+2 marks, that is, 12th standard Board Exam marks rather than through a separate selection entrance examination. Such NEET based selection also imposes immense psychological stress on MBBS aspirants and financial burden on their families. To do away from the NEET menace, the 'Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Bill, 2021' was passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly on 13.09.2021 at the behest of our hon. Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, and it was forwarded by hon. Governor of Tamil Nadu to the Union Ministry of Home Affairs and is pending for assent for nearly three years. Sir, this has caused immense anxiety and stress in the minds of students and parents.

Recently, the nation has witnessed large-scale confusions. Starting with question paper leaks and irregular handling of awarding grace marks for wrong key answers and compensatory marks, almost 23.33 lakh candidates are today affected by the 2024 UG NEET Exam. This has also led to filing of many cases in the hon. Supreme Court of India and ordering of CBI Inquiry by the Union Government. Sir, the Tamil Nadu Legislative Assembly has recently moved a Resolution seeking exemption for Tamil Nadu from NEET examination or to scrap completely the NEET for admissions to medical courses. Therefore, we seek the hon. Prime Minister's immediate attention in this regard either to approve the Bill passed by the State Government in this matter or to bring out such amendments to the National Medical Commission Act so that the NEET and the NEXT Exam system is given up at the national level.

Sir, rather than being a test of merit, NEET has become a world of scams and corruptions as exam papers can be purchased from residences just a phone call away, even through Dunzo and Amazon, and results can be easily tampered with. You can even have a ghost writer in a few centres to get full marks of 720 out of 720.

Sir, when NEET was introduced in 2010 through regulations, Dr. Kalaignar Karunanidhi, the then Chief Minister of Tamil Nadu, asked me to file a Writ Petition and to get a stay. Sir, I appeared before the Madras High Court and I got a stay of implementation of the NEET regulations. Always Tamil Nadu raises its voice first whenever it sees injustice or inequality. Our Youth Wing Secretary and hon. Sports Minister, Mr. Udhayanidhi Stalin, undertook a campaign against NEET and as many as 80 lakh persons signed seeking to ban NEET.

Sir, there has been an extraordinary delay of 48 days in ordering a CBI investigation in NEET scam, and this delay has helped the fraudsters to tamper with documents and erase the evidence.

Another interesting factor is, the Parliament passed the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 on 09.02.2024. The President gave her assent on 12.02.2024. However, it is shocking to note that the Act was notified only on 21.06.2024 after the scam of paper leak of NEET and NET has happened. The object of Public Examination Act, 2024 is to bring stringent provisions to curb the malpractices as there was no substantive law to deal with unfair means or offences committed such as paper leakage. Both the State and the Central Governments have powers to order investigation. My question is, why this Act was notified belatedly in June, 2024 when the Act was passed and assent given on 12.02.2024? Now, the NTA officials will clearly escape from the clutches of this Public Examination Act. Interestingly, the National Testing Agency which is responsible for conducting more than 14 critical competitive exams, including NEET, is registered under the Societies Registration Act like any other Flat Owners Housing Societies. Crores of funds are given to this unaccountable body. From 2014 to 2024, the Government passed as many 427 Bills in Lok Sabha and 365 Bills in Rajya Sabha. However, the Union Government was not interested in introducing legislation to provide statutory backing for NTA. This lack of legislation may allow NTA to avoid accountability and face no consequences for corruption or illegal activities. There is no answer why such important exams were given to an incompetent body and made unaccountable for this.

Sir, I will go to the State issues. The first one is the CMRL Project. Phase-2 of the Chennai Metro has been proposed at a cost of Rs. 63,246 crores and covering 119 kilometres at 50:50 joint venture between Union of India and Government of Tamil

Nadu. Although Phase-2 Project's foundation stone was laid by the hon. Union Minister of Home Affairs on 21.11.2020 and the announcement for counterpart funding was made in the Union Budget for 2021-22, there has been no progress at all. Though the project was recommended by the Public Investment Board on 17/08/2021, it is still awaiting the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs. Many other city metro proposals, which were subsequently recommended by the Public Investment Board, have since been approved by the Union Government. Considering the pressing needs of the Chennai metropolitan area, the Government of Tamil Nadu has commenced work on Phase-II in anticipation of approval by the Union Government and the expenditure is currently being met from the State funds. While such funding of project expenditure has ensured that the works are on track, the State's fiscal situation has been adversely impacted by it. This situation needs to be set right without any further delay. We urge the hon. Prime Minister to give Cabinet clearance and allocate 50 per cent of the cost, that is, Rs. 31,623 crore.

Sir, my second point is about NDRF claims. Tamil Nadu faced two unprecedented natural disasters in the month of December, 2023. Cyclonic storm Michaung brought extremely heavy rainfall and also the southern districts of Tamil Nadu like Thoothukudi, Thirunelveli, Tenkasi and Kanniyakumari districts received unprecedented extremely heavy rainfall in December, 2023. As a result, infrastructure, both public and private, and livelihoods of people have been devastated. After the IMCT officials came and assessed the damages, the State Government made a claim of Rs. 37,907.21 crores. However, the Union Government has sanctioned a meager compensation of Rs. 276 crore from the NDRF on 26.04.2024. Given the magnitude of the natural disaster and the colossal damage caused to infrastructure and livelihood, this compensation is grossly inadequate and is a grave injustice to the State of Tamil Nadu. ...*(Time-bell rings.)*... Hence, hon. Prime Minister is requested that at least Rs. 3,000 crore may be immediately sanctioned under the NDRF to take up the restoration and relief work to defray the expenditure.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, Shri Wilson, please conclude.

SHRI P. WILSON: Sir, let me take some time from other Members. This is important. We agree on that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are 46 speakers. Unless I get it in writing, I cannot permit that. Please conclude.

SHRI P. WILSON: Sir, we need a caste-based census. There is no contemporary data available after 1931. So, we need a caste-based census. Several new railway projects in Tamil Nadu require sanction on high priority. Tambaram-Chengalpattu, Tirupattur-Krishnagiri-Hosur new line, Madurai-Thoothukudi-Aruppukkotai, then, Minjur...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri P. Wilson. Shri Sandeep Kumar Pathak.

SHRI P. WILSON: Sir, we would adjust time among ourselves.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are 46 speakers more.

SHRI P. WILSON: Sir, give me just two minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sorry. Shri Sandeep Kumar Pathak, please speak. ...*(Interruptions)*... There is a time constraint. I cannot give you time. संदीप कुमार पाठक जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... Please speak. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. Please, it is not going on record. Stick to your time; stick to your time. We have 46 speakers today. Please.

श्री संदीप कुमार पाठक (पंजाब): डिप्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और इस सभा का धन्यवाद करता हूं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, हमने राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का बहिष्कार किया था। आपने मुझे 6 मिनट का समय दिया है...

श्री उपसभापति: समय मैंने नहीं दिया है, वह आपकी पार्टी का समय है।

श्री संदीप कुमार पाठक: मैं 6 मिनट में आपके माध्यम से देश को बताऊंगा कि कैसे यह पूरा जो अभिभाषण है, उसमें कोई विज़न नहीं है। यह पूरे तरीके से खोखला है। आप किसी भी सरकार के कार्यकाल को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उनका विज़न क्या है और वह क्या करना चाहती है। इसमें एक भी विषय पर कोई विज़न दिखाई नहीं देता है। पिछले 10 सालों में अगर कुछ दिखाई देता है, तो गुड़, गोबर, मंगलसूत्र, भैंस, * ये सारी बातें दिखाई देती हैं। प्रधान मंत्री जी के मुंह से यह शोभा नहीं देता है, लेकिन यही विज़न है। आप कार्यकाल में किए गए सारे कार्यों को देखेंगे, तो विज़न से यह खोखला दिखता है, पर जिन चीज़ों से यह भरा है, वे हैं घृणा, क्रोध और अहंकार। इतना अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं होता है और प्रजातंत्र में तो निश्चित रूप से यह अच्छा

* Expunged as ordered by the Chair.

नहीं होता है। अहंकार के वृक्ष पर सिर्फ विनाश का फल लगता है। 400 से 240 आने में समय नहीं लगा।

ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, कई सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक विषय को यहां रखना चाहता हूं, वह है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के कारण ही आज भारत भारत है। प्रजातंत्र का सबसे प्रमुख आधार चुनाव होता है और किस तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यह हमें समझना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि चुनाव कराने वाली संस्था चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव में अगर आप निष्पक्षता नहीं रखेंगे, अगर आप न्यूट्रैलिटी नहीं रखेंगे, तो आप कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अगर चुनाव पर लगने वाले पैसे पर कोई रोक नहीं रहेगी, तो इस देश का एक आम आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा। एक तरफ अरबपति, खरबपति चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक साधारण आदमी। आप electoral bond लेकर आए। Electoral bond में 55 प्रतिशत चंदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसके अलावा, 33 ऐसी loss making companies थीं, जिन्होंने पैसे दिए, उसमें से 75 परसेंट पैसा बीजेपी को जाता है। यह चंदा, जो भारतीय जनता पार्टी को गया, उसके जिम्मेदार कौन हैं? क्या यह देश के सामने नहीं है? क्या यह हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर निष्पक्षता लाएँ, पारदर्शिता लाएँ? ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह electoral bond unconstitutional है। सरकार की तरफ से बात आती है, वह कहती है कि हम इसको revive करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को, shut down होने के बाद आप revive करने की बात करते हैं, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ है? यह देश में selective emergency लगी हुई है। मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि अगर यह selective emergency नहीं है, तो फिर क्या है। दूसरी तरफ आप देखिए, खरीद-बिक्री। चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 11 सरकारें बनाई हैं। आप नाम ले सकते हैं - महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। You name it. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, 11 सरकारें चुनाव हारने के बाद, यह emergency नहीं है, तो क्या है! ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, इसमें आपको चौथा पक्ष देखना पड़ेगा, जो जेल का है। आज से पहले तक चुनाव में जेल का कोई रोल नहीं होता था। कोड लगने के बाद अरविंद केजरीवाल जी, जो चुने हुए मुख्य मंत्री हैं, उनको जेल भेजा जाता है। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, कोड लगने के बाद! ...(**व्यवधान**)... कोड लगने के बाद जेल भेजा जाता है। आप सामने से चुनाव नहीं लड़ सकते, आपमें इतनी हिम्मत नहीं है। आप पहले ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, उससे काम नहीं बनता है। सरकार खरीदने की, धमकाने की कोशिश करती हैं, काम नहीं बनता है। जब काम नहीं बनता है, तो आप जेल में डाल रहे हैं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, चुनाव की प्रक्रिया में हमारे देश में यह जेल कहाँ से आ गई? यह selective emergency नहीं है, तो फिर क्या है?

सर, अगर मैं executive के बारे में अगली एक बात रखूँ, तो जितने IPS, IAS हैं, जब वे पढ़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छी भावना से देश के लिए पढ़ाई करते हैं कि मैं ऐसा बनूँगा तो देश की सेवा करूँगा, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा undue pressure है। उनकी गलती नहीं है। इतना ज्यादा undue pressure है, वे कहाँ से deliver करेंगे, कहाँ से देश के लिए सेवा करेंगे! आप देखिए, अगर आप सीबीआई और ईडी का motto पढ़ेंगे - Industry, Impartiality, Integrity, Accountability, Excellence. ये ईडी और सीबीआई के motto हैं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन

सर, आप इसमें एक भी count पर अगर यह बता दें, यह पूरे देश और दुनिया के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज तक ईडी और सीबीआई के द्वारा जितने भी केसेज़ हुए, उनमें से 95 परसेंट ऑपोज़िशन पार्टीज़ के ऊपर थे। 95 परसेंट ऑपोज़िशन के लीडर्स के ऊपर आपने ये केसेज़ किए। Impartiality, Accountability, Excellence, ये सारी बातें किताब में रह गई हैं।

ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, आप judiciary को लीजिए। Judiciary के तीन हिस्से हैं। Judiciary itself, दूसरी agencies और तीसरा है कानून। आप PMLA लेकर आते हैं। आप उसमें सेक्शन 45 लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह unconstitutional है, वह struck down कर देता है, फिर आप उसको revive करते हैं। आप revive करके PMLA लेकर आते हैं। उस PMLA को आप हथियार बनाते हैं। आपने PMLA को हथियार बनाया, सीबीआई और ईडी को अपना हथियार बनाया। आपके पास एक तरफ कानून भी आ गया, दूसरी तरफ agencies आ गईं, विपक्षियों पर करो हमला, एक-एक करके। Judiciary में जज का selection है। अब जज के selection में इनको अपना सरकारी तंत्र चाहिए, ताकि उसमें भी कुछ कर सकें।

सर, अगर मैं संघीय ढाँचे की बात करूँ, तो दिल्ली को 100 MGD पानी कम कर दिया गया। 28 लाख लोगों को पानी की कमी पड़ गई। क्या हमारा देश इस स्थिति में आ गया है कि राजनीति के लिए हम पानी रोकेंगे। पंजाब के 8 हजार करोड़ रुपए आप रख लेते हैं। आप 26 जनवरी को उसकी झाँकी नहीं लगाते हैं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, पंजाब दिन-रात शहीदी दे रहा है, देश का पेट पोस रहा है, लेकिन 26 जनवरी को आप उसकी झाँकी नहीं लगा सकते। धिक्कार है ऐसी परिस्थिति को!

ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि क्रोध और अहंकार का परित्याग करो। ...(**समय की घंटी**)... भगवान राम और रावण में एक ही अंतर था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उनके पास 6 मिनट हैं।

श्री संदीप कुमार पाठक: ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, भगवान राम और रावण में एक ही अंतर था कि राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अहंकार छोड़ते हैं, मिल कर काम करते हैं, देश बनाते हैं, बहुत काम हैं। इस तरीके से आपका पतन सुनिश्चित है, 400 से 240. ईश्वर साक्षी है, अगली बार इतनी हाय और इतनी बददुआएँ लगेंगी कि 40 आते-आते देर नहीं लगेगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। ऑनरेबल श्री मुजीबुल्ला खान जी।

श्री संजय सिंह: डिप्टी चेयरमैन सर, अभी टाइम बचा हुआ था।

श्री उपसभापति: आपके और speakers हैं, हम check करवाते हैं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ हम check करवाते हैं। यहाँ 6 मिनट समय रखा हुआ है। प्लीज़।

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं बीजू जनता दल की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहता हूँ।

महोदय, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब राज्य सभा में आया, तो मुझे बहुत उत्सुकता थी कि यहाँ मैं बहुत कुछ सीखूँगा, बहुत कुछ जानूँगा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि दो साल कोरोना में निकल गये, बाकी दो साल लड़ाई-झगड़े में निकल गये। मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता। एक तरफ से कोई बोलता है, तो दूसरी तरफ से कोई टोकता है। जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में झगड़ा होता है, वही यहाँ चला है, तो हम जो नए लोग यहाँ आते हैं, हम लोग क्या सीखेंगे? बड़ा अजीब सा लगता है। देखते-देखते कोरोना के साल मिलाकर मेरे 4 साल निकल गए और अब बड़ी मुश्किल से 2 साल बचे हैं। आज बोलने का मौका तो मिला है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा।

सबसे पहले मैं पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक क्वोट कहना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि "भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यह है कि राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए।" यह बात सही है, लेकिन आज जो जमाना है, आज का जो दिन है, राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखने की बात मैं कहीं पर नहीं देख पा रहा हूँ, हर जगह राजनीति ऊपर रहती है। पहले के जमाने में लोग राजनीति करते थे, तो वे ईमानदारी से राजनीति करते थे। आज जिसकी कोई नीति नहीं है, वही राजनीति करता है - बिना नीति के राजनीति।

उपसभापति महोदय, मैं भारतवर्ष के कुछ पुराने नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जिन्होंने राजनीति की, कैसी शालीनता से की, कैसी simplicity से अपना राजनीतिक जीवन पार किया। उनके बारे में मैं जो थोड़ा-बहुत जानता हूँ, वह कहना चाहता हूँ। उनमें से एक हैं - चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधान मंत्री। मुझे जितना मालूम है, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जब वे प्रधान मंत्री बने, तो वे एक कृषक के वेश में, एक किसान के वेश में एक पुलिस स्टेशन में पहुँचे और उन्होंने वहाँ बोला कि मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। उस पुलिस स्टेशन वालों को पता नहीं था कि ये भारत के प्रधान मंत्री हैं। उसने बोला कि कुछ पैसे निकालो, तब तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। चूँकि वे एक किसान के वेश में थे, तो उनको वहाँ बहुत देर तक बिठा दिया गया। फिर आगे चल कर पता चला, धीरे-धीरे सबको पता चला कि प्रधान मंत्री जी खुद आए हुए हैं, तो उनकी क्या हालत हुई होगी, यह आप खुद समझ सकते हैं। वे एक किसान के वेश में जाने वाले प्रधान मंत्री थे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, अब मैं और क्या कहूँ?

उपसभापति महोदय, कर्पूरी ठाकुर जी कितने सरल नेता थे, यह आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं। मैंने सुना है कि 70 के दशक में हरियाणा के रोहतक एरिया में एक उपचुनाव हो रहा था। एक युवा नेता को बोला गया कि कर्पूरी ठाकुर जी इस चुनाव के प्रचार में रहेंगे, आप दिल्ली जाकर वहाँ से उन्हें लेकर आओ। वह युवा नेता दिल्ली पहुँचकर बिहार भवन में कर्पूरी ठाकुर जी से मिला। कर्पूरी ठाकुर जी ने उससे पूछा कि क्या आप गाड़ी लाए हो? उस युवा नेता के पास गाड़ी कहाँ थी, वह बेचारा तो बस से वहाँ गया था। उसने कहा कि सर, मैं तो गाड़ी नहीं लाया हूँ। तब उन्होंने उसे कहा कि चलो, हम साथ में बस में चलते हैं। उसने बोला कि सर, क्या आपकी गाड़ी नहीं है? कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। वे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी, खूँदा-खूँदी जैसी स्थिति

थी, जिसको हम लोग ओड़िया में ठेला-पेला बोलते हैं। बस में लोग एक-दूसरे को धक्का मार रहे थे। तभी उस युवा नेता ने कर्पूरी ठाकुर साहब से कहा कि मैं किसी को बोलता हूँ कि ये एक्स-चीफ मिनिस्टर हैं, तो इससे आपको जगह मिल जाएगी। इस पर कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खड़े होकर जाऊँगा। वे दिल्ली से रोहतक तक 70 किलोमीटर खड़े होकर गए।

महोदय, आप जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वे तीन दिन के प्रचार के लिए गए थे। उस युवा नेता ने उनसे पूछा कि सर, आप तो कोई बैग वगैरह नहीं लाये हैं और आपका कपड़ा तो मैला लग रहा है, इस कपड़े में एक दिन बीत गया, आप कल क्या पहनेंगे? उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास है। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, तो उसके अंदर एक और कुर्ता था। वे एक साथ तीन कुर्ते पहन कर गए थे। वे बोले कि मैं तीन दिन में अंदर के ही तीन कुर्ते बदल लूँगा। उन्होंने मैला वाला कुर्ता अंदर पहना और साफ वाले कुर्ते को ऊपर रखा। इसी तरह से तीसरे दिन भी वही किया। यह देख कर वह युवा नेता आश्चर्यचकित हो गया। आपको जान कर खुशी होगी कि वह युवा नेता आज राज्य सभा के एक सदस्य हैं और अभी भी सदन में हमारे साथ बैठे हैं। उनका नाम रामचंद्र जांगड़ा जी है। आप ही वे युवा नेता थे न? रामचंद्र जांगड़ा जी वह युवा नेता थे, जो उस समय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ गए थे। एक एक्स-चीफ मिनिस्टर तीन ड्रेस एक साथ पहन कर गए थे और आज के नेता लोगों को देखिए, सुबह एक, बारह बजे एक, दो बजे एक और शाम को एक ड्रेस चेंज होती है। वह भी जैकेट के साथ चेंज होती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ।...(**व्यवधान**)...

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा)**:** महोदय, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः जांगड़ा जी, उनको बोलने दीजिए, कंटिन्यू करने दीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री रामचंद्र जांगड़ाः सर, मुझे 30 सेकंड का समय दे दीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः चूँकि बहुत स्पीकर्स हैं, सबको समय मिले, इसलिए उनको बोलने दीजिए।...(**व्यवधान**)... 46 से अधिक स्पीकर्स हैं, इसलिए कृपया उनको बोलने दीजिए।

श्री मुजीबुल्ला खान: महोदय, दूसरे नेता नवकृष्ण चौधरी जी हैं, जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर थे। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी बहुत सिम्पल थे, वैसे ही वे भी बहुत सिम्पल थे। नवकृष्ण चौधरी जी के बड़े भाई गोपबंधु चौधरी जी थे। गोपबंधु चौधरी जी की पत्नी, श्रीमती रमा देवी, जिनको माँ रमा देवी के नाम से सब जानते हैं, वे महात्मा गाँधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में जोगिनी थीं। नवकृष्ण चौधरी जी की पत्नी, श्रीमती मालती चौधरी संविधान सभा की एक सदस्या थीं। गोपबंधु चौधरी जी के बेटे, मनमोहन चौधरी, जो सात साल की उम्र में स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने के कारण जेल गए थे, वे काफी दिनों तक जेल में थे। इस कारण से वे बचपन में स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन भविष्य में उन्होंने पदार्थ विज्ञान में रिसर्च का काम किया। उन्होंने बिना स्कूल

गए, बिना पढ़ाई किए पदार्थ विज्ञान में रिसर्च किया। ये पूरा परिवार बहुत सिम्पलसिटी में रहते था और बहुत सिम्पल परिवेश में जीते था। मैंने सुना है कि एक बार विधान सभा में नवकृष्ण चौधरी जी का पूर्ण बहुमत था, लेकिन दो सदस्यों का मत भिन्न था। वे दोनों सदस्य किसी चीज के लिए नवकृष्ण चौधरी जी को अपोज़ कर रहे थे। इस पर नवकृष्ण चौधरी जी ने कहा कि अगर एक भी सदस्य मुझे अपोज़ करेगा, तो मैं मुख्य मंत्री के पद पर नहीं रहूँगा। इसके बाद वे मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर एक लोकल बस में बैठ कर, हमारे ओडिशा में अनुगुल एक जिला है, वहाँ पर बाजीराव जी के नाम पर एक आश्रम है, वहाँ चले गए। बाजीराव जी सबसे कम उम्र के स्वाधीनता सेनानी थे, उनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। वे अंग्रेजों की नैया पार कराने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके कारण कम उम्र में ही उनको शहीद होना पड़ा था। उन्हीं बाजीराव जी के नाम पर वहाँ पर एक आश्रम है। नवकृष्ण चौधरी जी ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ करके उसी आश्रम में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ी थी।

महोदय, जमाना बहुत बदल गया है। तब उनका बहुमत था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्य मंत्री का पद छोड़ दिया। आजकल जमाना ऐसा हो गया है, बहुमत रहे या ना रहे, पद छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं है। महोदय, हर जगह ऐसा होता है। मैं किसी एक पार्टी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। अगर बहुमत नहीं है तो जुगाड़ में लग जाते हैं, इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, इसको भगाओ, उसको दौड़ाओ - यह सब बड़ा अजीब सा लगता है। महोदय, यह देखकर अजीब सा लगता है कि आप सोचिए, एक विपक्ष के नेता ने खड़े होकर भाषण दिया, सरकार के विरोध में बोला, अपना पक्ष रखा, जोरदार बोला और हम सबने ताली बजाई, लेकिन जब हम निकलकर बाहर जाते हैं, तो देखते हैं कि मीडिया के सामने वह नेता बोलता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। भाई, आप तो अभी थोड़ी देर पहले सत्ता पक्ष के विरोध में बोल रहे थे, फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? पता नहीं, इसी के अंदर ऐसी क्या सेटिंग हो गयी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महोदय, ऐसे बहुत से केसेज़ हैं। ऐसा बहुत से राज्यों की विधान सभाओं में होता है, हमारे पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अपनी पार्टी में मुख्य मंत्री का पद पाने वाले नेता भी ऐसा करते हैं। एक पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी बीजू जनता दल और मेरे नेता, नवीन पटनायक जी ने मुझे राज्य सभा में भेजा है, अपर हाउस में भेजा है, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं अपनी पार्टी का सम्मान करता हूं, अपने नेता का सम्मान करता हूं, तो मेरा दिल कभी यह नहीं कहेगा कि मैं अपने नेता को छोड़कर कहीं जाऊं। लेकिन ऐसे बहुत से नेता हैं, जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहता, जिन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से मुख्य मंत्री का पद मिलने के बाद भी ऐसा किया। भाई, पार्टी आपको उससे बड़ी पोस्ट और क्या देगी? उसने मुख्य मंत्री का पद दिया, उससे ज्यादा आपको वह क्या देगी, जबकि आप उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हो! वे क्यों जाते हैं, यह तो वे ही बता सकते हैं। जो छोड़कर जाता है, वही बता सकता है कि वह मजबूरी में गया, डर के गया या वह इंसान लालच में गया। इनमें से कोई तो एक बात हुई होगी, कोई तो बात हुई होगी, जैसा कि फिल्मों में होता है! फिल्मों में क्या होता है? कोई विलेन बच्चों को किडनैप कर लेता है। महोदय, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से आता हूं, इसीलिए मैं यह अच्छी तरह से बोल सकता हूं। हम लोग पिक्चर में देखते हैं कि वे बच्चों को किडनैप करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम यह काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तो जो हीरो होता है, वह मजबूरी में सरेंडर कर जाता है। इसके अलावा, जब उस इंसान को किसी चीज़ का

लालच दिया जाता है, तब वह सरेंडर कर जाता है या चेंज करता है। यानी, या तो डर से या भर से वह ऐसा करता है। "भर से" का मतलब है- भरने वाला। चाहे वह पैसा भरे, सोना भरे, दौलत भरे या कुछ भी भरे, भर से या डर से, इन दो चीज़ों की वजह से ही आदमी अपना जमीर तक बेच देता है, अपना ईमान बेच देता है। आखिर वह करे भी तो क्या करे?

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

चेयरमैन सर, आप आ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। महोदय, मैं बचपन से राजनीति में इसलिए हूं, क्योंकि मेरे परिवार के सब लोग राजनीति में थे। मैं बचपन से यह चाहता था कि राजनीति में बड़े-बड़े नेताओं से मैं कैसे मिलूँ। मेरी छुटपन से, बचपन से यह सोचने की आदत थी कि बड़े-बड़े नेताओं से मेरी जान-पहचान कैसे होगी। मैं जब छोटा था तो मैं बीजू बाबू से मिला था, क्योंकि मेरे पिताजी बीजू बाबू के साथ काम करते थे। मैं बचपन में बीजू पटनायक जी से मिला था। तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं बीजू पटनायक जैसे नेता से मिला। ...(**समय की घंटी**)... सर, मेरे 15 मिनट्स हैं। मेरे सिर्फ सात मिनट्स बीते हैं, मैं घड़ी देख-देखकर बोल रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: It is not reflecting correctly. You have thirty seconds left. Round up. It was a good address. I was listening to it.

श्री मुजीबुल्ला खान: सर, आज मैं ground reality से सरपंच से सीधे राज्य सभा में पहुंचा। यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के पास आकर मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ जानने का मौका मिला। मैं सरपंच था, अब सरपंच से सीधे राज्य सभा में आया हूं। मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, मुझे कभी विधान सभा चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला, सरपंच से सीधे राज्य सभा में आया हूं। ...(**समय की घंटी**)...

सभापति महोदय, आज मैं राष्ट्रपति महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। राष्ट्रपति महोदया भी हमारे ओडिशा से हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि भारत की राष्ट्रपति ओडिशा से हैं। राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में clear majority वाली सरकार कहा था, लेकिन मैं जितना जानता हूं, उसके हिसाब से वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में clear majority वाली सरकार थी, अभी clear majority नहीं है, अभी गठवंधन की सरकार है। ...(**समय की घंटी**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have only ten seconds left. Please conclude.

श्री मुजीबुल्ला खान: सर, मेरे पास 15 मिनट का समय है।

MR. CHAIRMAN: Don't look at that. At the moment, it has to be corrected.

श्री मुजीबुल्ला खानः सर, राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासियों के लिए अभिभाषण दिया था, लेकिन हमारे ओडिशा में 162 ऐसी communities हैं, जिनको आदिवासी कम्युनिटी में शामिल करना ज़रूरी है, ताकि वे आदिवासियों को मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। सर, राष्ट्रपति महोदया का जो अभिभाषण था, उसमें कहीं minority का ज़िक्र नहीं था।

MR. CHAIRMAN: Shri A. D.Singh.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, he got stuck somewhere. He is coming within half an hour.

MR. CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, to be present in the House at 1.00 p.m., this can hardly be a premise. He is not present. Shri Ravi Chandra Vaddiraju.

श्री मुजीबुल्ला खानः सर, क्या मैं conclude कर सकता हूं?

MR. CHAIRMAN: You are not concluding.

श्री रविचंद्र वद्दीराजू (तेलंगाना): सभापति महोदय...

MR. CHAIRMAN: One second, Shri Ravi Chandra Vaddiraju.

श्री मुजीबुल्ला खान : सर, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूंगा कि मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए - हम लोग बहुत दिन से ओडिशा की तरफ से यह विषय उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी। सबसे बड़ी बात यह कि अहिंसा शब्द को हमारे संविधान के Preamble में शामिल करने के लिए बहुत समय से हमारी डिमांड है। यह शब्द महात्मा गांधी जी का शब्द है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अहिंसा शब्द को संविधान के Preamble में शामिल किया जाए। धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सर, क्या आधे मिनट का समय मिल सकता है?

MR. CHAIRMAN: Wait for your turn. The House is regulated by rules and procedure. Take your seat. Shri Ravi Chandra Vaddiraju, you have seven minutes.

श्री रविचंद्र वद्दीराजूः सभापति महोदय, मैं तेलुगू में बात करना चाहता हूं। मैंने नोटिस दे दिया है।

1.00 **P.M.**

#"Hon'ble Chairman Sir, on behalf of the Bharat Rashtra Samithi (BRS), I would like to express my heartfelt thanks to the hon. President Smt. Draupadi Murmu who addressed both the Houses on the occasion of the newly formed 18th Lok Sabha. First of all, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. I also thank Shri KCR for nominating me to this august House for the second time.

Sir, we are very proud that the newly formed state of Telangana has also become a partner in making India a developed country. 75 years have passed since we attained independence and we are approaching the 75th year of the adoption of the Constitution. On this occasion, I am proud to say that Telangana has contributed a lot to the development of the country.

Shri K. Chandrashekar Rao, the leader of the Telangana movement, became the first Chief Minister of the State of Telangana, which successfully achieved the struggle for the formation of a separate State. He stood as a role model by bringing development in all fields. I am happy to say that Shri KCR has unveiled the model of Telangana progress.

Sir, it is commendable that the country's economy has moved to 5th position from 11th position under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Hope it becomes more financially stronger. I am confident that the upcoming Budget will be beneficial to all people.

Development was seen in all the sectors in Telangana during KCR's tenure of ten years. The progress of Telangana State from 2014 to December 2023 under the leadership of Shri KCR was truly a golden era. Telangana region suffered during the earlier rulers. The State achieved all-round development during the tenure of Shri Kalvakuntla Chandrashekar Rao. The standard of living of the people of Telangana has improved drastically. Some of the schemes implemented during his tenure became an example for the entire country. Schemes like Kisan Samman Nidhi and Har Ghar Jal introduced by the hon. Prime Minister are similar to KCR's RythuBandhu and Mission Bhagirath Schemes. Shri KCR has introduced and implemented many such great schemes.

If Telangana was formed, there would be no IT jobs. Shutting the mouths of those who thought IT would be a disaster, Telangana scaled new heights. Even though there were few IT companies established in Hyderabad during the United Andhra Pradesh, IT exports were severely affected due to power cuts. This creates a risk of IT companies moving to cities like Bangalore. As a result, immediately after

---

#English translation of the original speech delivered in Telugu.

coming to power in 2014, the KCR Government continuously focused on the generation of electricity and building infrastructure. Incubators have been set up to provide skill training for setting up new start-ups. Incentives were provided. Subsequently, Telangana has become the IT hub of the country. More than 20 multinational companies (MNCs) such as Google, Amazon, Apple, Facebook, and Microsoft, which are among the list of Fortune 500 companies, are operating from Hyderabad. Moreover, with the development of IT sector, other sectors that are dependent on IT sector also benefited a lot. It is said that with the creation of one IT job, four more jobs will be created indirectly. Due to the growth of IT in Telangana, the real estate, hospitality, entertainment, transport and logistics sectors have grown at a rocket speed. Directly, 20 lakh people got employment. During the formation of Telangana, there were only 3 startup incubators and 200 startup companies. By 2023, they have increased to 77 incubators and over 7 thousand startups. In the last nine years, we were able to increase the IT jobs to 9,05,715 by 2023. IT Exports in the last nine years: in 2014, exports were 66,276 crores and by 2023 IT exports increased to 2,41,275 crores.

Telangana is a successful model for small states. IT exports increased by 4 times and jobs by 3 times. Telangana's installed power capacity hasincreased from 7.8 gigawatts to 19.3 gigawatts. The GSDP growth rate of the state exceeded the country's GDP.

Sir, ten years ago, when Telangana emerged as the 29th state, it was 10th in per capita income, 11th in geographical area, and 12th in population. During the past decade, the State has seen remarkable development. Telangana has raised from uncertainties in power supply to continuous power supply without interruption even for a second. Significant progress has been made in industrialization and job creation. It has reached the top position among small States in terms of per capita income. At 2.7 per cent of the country's population, Telangana's GDP growth has exceeded the nation's average. The development of Telangana is a model for the benefits of bifurcating large states.

Telangana's GSDP increased in ten years: In 2014, GSDP was Rs. 3.79 lakh crores and by 2023, it became Rs. 13.28 lakh crores. This is an increase of 251 percent. Per Capita Income of Telangana: In 2014, the per capita income was Rs. 93,151, by 2023 with a 230 per cent increase, it reached Rs. 3,12,398.

Sir, lakhs of acres were brought under cultivation with the Kaleshwaram project, which is said to be an engineering marvel. 90 per cent of the Sitarama project has been ambitiously completed so that some parts of the land in the Warangal district along with the joint Khammam district can be cultivated. The trial run of the

Sitarama project was successfully done four days back. With this project, about 11 lakh acres of barrenland in three districts can be brought under cultivation. As a visionary leader, KCR initiated these massive programs with foresight and success, bringing joy to the farmers.

Before the formation of Telangana, 36 lakh tons of grain were harvested, But, after the formation of the state, by 2023, we have grown 3 crore tons of grain because of the facilities provided by Shri KCR. Sir, we are requesting the Central Government to meet the fair demands for the benefit of the people of Telangana. Palamuru-Rangareddy Irrigation Scheme should be given national status and allocate large amounts of funds. Similarly, a railway coach factory should be established in Kazipet. The Central Government should set up the Bayyaram steel factor as mentioned in the Andhra Pradesh Reorganization Act. Bailadila Iron ore mines in Chhattisgarh should be allocated to Bayyaram. All coal blocks in Telangana should be allocated to Singareni. Airport should be established in Mamnoor&Kothagudem in Warangal. What rulers for the last 65 years could not achieve, Shri KCR did in just 10 years. KCR changed Telangana into Golden Telangana and into Annapurna State. He made it the number one State in India.

I request the hon. Prime Minister, to establish IIM in Telangana as mentioned in the Andhra Pradesh Reorganization Act. I once again express my sincere thanks for allowing me to participate in the Motion of thanks on the President's Address. Jai Hind! Jai Telangana! Jai KCR!

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya. *...(Interruptions)...*

श्रीमती रेणुका चौधरी (तेलंगाना): सर, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* Renuka*ji*, I don't appreciate such kind of interventions. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I sought your permission, Sir.

MR. CHAIRMAN: No; I never gave it. Please take your seat. *...(Interruptions)...* I deprecate such tendencies. *...(Interruptions)...* You are very experienced, please don't.....*(Interruptions)...* No please; nothing. *...(Interruptions)...* I would appeal to the leaders, they must control their Members. Their Members cannot be at large.

…(Interruptions)… Please take your seat. I have not given you permission. *…(Interruptions)…* I have not given you permission. *…(Interruptions)…* No, please. *…(Interruptions)…* You must have some regard. I am already in deep pain. I have suffered observations which I thought, all my life, I will not suffer from LoP. *…(Interruptions)…* What he made was absolutely touching my conscience to the core. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya, please. *…(Interruptions)…* Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya, you have seven minutes. *…(Interruptions)…* Please continue now. *…(Interruptions)…*

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (WEST BENGAL): #"Hon. Chairman Sir, the language which gave Vande Matram to India, the language which gave Jan gan man adhinayak to India, I would like to speak in that language Bengali. At the outset I will make a submission that whenever any Member makes a speech, if you have any objection to any part of it, if you wish to expunge it, then kindly preserve the original speech of the concerned speaker and thereafter mention your objection so that the future generation knows what the original speech was and what was expunged. Sir, I thank hon. President of India for her Address.' *…(Interruptions)…* I am told there is no interpreter. *…(Interruptions)…*

MR. CHAIRMAN: Please continue. *…(Interruptions)…* Bikash Ranjan Bhattacharyya*ji*, Bengali is such a lovely language, very mellifluous. *…(Interruptions)…* We understand it.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Not only lovely language, this is the language which has given us *Jana Gana Mana*. And, which has given us *Vande Mataram*, that language is not being interpreted.

MR. CHAIRMAN: Bikash Bhattacharyya*ji*, what will we do? *…(Interruptions)…* One minute. *…(Interruptions)…* Does he need support? *…(Interruptions)…* Such a distinguished person and he was the Mayor of Kolkata City and a senior Advocate. Take your seat. Bikash*ji*,… *…(Interruptions)…* I urge the Members that those Members who wish to speak in their regional language have to give notice. I will call you after about an hour and there will be translation. One minute. *…(Interruptions)…* You would have noticed the speaker earlier to you had so indicated and there was

English translation of the original speech delivered in Bengali.

translation. So, we will take it. We will have the benefit of your sound views after about an hour so that arrangements will be made.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: No; Sir, I would seek your kind leave to speak in English. But, this is a very sorry state of affairs in the country of multi-lingual, multi-cultural unity when the Constitution says, 'Union of States'. The Constitution does not say that this is a unitary country. This is not one country, one language and one leader. But, this is a country of multiple-culture and multiple-language. Therefore, language of every corner ought to have been immediately translated. I have had my experience of international conferences where I don't have to give notice that I will speak in my own language. It automatically goes on translating. Unfortunately, we are talking of Digital India. We are talking of so-called advancement but we....

MR. CHAIRMAN: Bikash*ji*, let us not take time of the House on this. At the moment, we have a mechanism in place which is duly notified to all the hon. Members and any hon. Member who informs the Table Office, arrangements are made. The speaker before you, Shri Ravi Chandra Vaddiraju, spoke in Telugu. Everyone heard him and I am accommodating you. I am being sensitive to it. So, let us not make an issue of it.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Sir, I accept your opinion. I accept your judgement.

MR. CHAIRMAN: I am so happy. We will give you adequate time. I need to listen to you more carefully. I have such attachment with Bengal and Bengali Language. Now, Shrimati Mahua Maji.

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया को उनके अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

हमारे झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट भवन में जिस तरह से महात्मा गाँधी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को वहाँ से हटाकर पार्लियामेंट के पीछे की तरफ रख दिया गया है, उसी तरह से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को भी उस स्थान से हटाकर पीछे शिफ्ट किया गया है और उनके कद को भी पहले से

छोटा किया गया है। महोदय, इससे हमारा आदिवासी समाज बहुत दुखी है। माननीय उपसभापति महोदय, आप इस पर कुछ कीजिए।

महोदय, आदिवासी समाज तब भी दुखी था, जब इस पार्लियामेंट भवन के अभिभावकसरूपा आपको गृह प्रवेश के समय पर आमंत्रित नहीं किया गया था। आदिवासियों के वीर शहीद बिरसा मुंडा को गुलाम भारत में अंग्रेज़ों ने रांची जेल में डाल दिया था। आज 21वीं सदी में आपकी सरकार ने हमारे लोकप्रिय युवा मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी को भी उसी तरह से रांची जेल में डाल दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने खुद कहा है, लिखकर भी दिया है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक निर्दोष मुख्यमंत्री को पाँच महीने तक उनके पद से रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया गया, एमपी इलेक्शन के दौरान चुनाव से बाहर रखा गया। महोदय, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, उन्हें मानसिक यंत्रणा दी गई, जिसकी वजह से उनके परिवार ने सफर किया। माननीय उपसभापति जी, इसकी भरपाई कौन करेगा? दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी वही हो रहा है। इस तरह से पूरे देश में एक खेल चल रहा है। उपसभापति जी, इस बदले की राजनीति को दूर कीजिए।

उपसभापति जी, गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ कोयले की रॉयल्टी के 1 लाख, 36 हज़ार करोड़ रुपये के लिए केंद्र सरकार से बार-बार कहा गया, लेकिन वह नहीं दिया गया। वहाँ महिलाओं की तस्करी होती है, रोजगार का अभाव है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, आदि के ये तमाम काम उस 1 लाख, 36 हज़ार करोड़ रुपये से हो सकते थे, लेकिन आप वह पैसा उस राज्य को नहीं दे रहे हैं।

उपसभापति जी, राज्य को जीएसटी के पैसे देने में भी आना-कानी होती है। जब 8 लाख प्रधान मंत्री आवास नहीं दिए गए, तो हमारी सरकार ने 'अबुआ आवास योजना' लाँच की। राज्य को बिजली देने में आना-कानी की जाती है, ताकि राज्य ठीक से काम नहीं कर सके। सरना धर्म कोड को पारित करना आदिवासियों की वर्षों पुरानी माँग है। इसे झारखंड में दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, जो आदिवासियों की माँग है, उसे भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उसे भी पारित किया था। महोदया, आपने अभिभाषण में आपकी सरकार की लगभग सभी उपलब्धियों का जिक्र किया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अयोध्या राम मंदिर की उपलब्धि पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पूरा देश हैरान है। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगी। माननीय मोदी जी जय श्रीराम का नारा लगाकर अपनी सभाओं में बात करते हैं, लेकिन लोक सभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद, अयोध्या हार जाने के बाद अपने सांसदों को संबोधित करते समय, उन्होंने जय श्रीराम को भुलाकर सिर्फ जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि जगन्नाथ में उन्होंने बीजेडी को लोक सभा और विधान सभा से वॉश आउट कर दिया है। इससे भी हमारे राज्य में लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर की जगह जय जगन्नाथ का मंदिर बनाना चाहिए।

सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाने वाली बीजेपी की सरकार में बीफ को लेकर अल्पसंख्यकों के साथ न जाने कितने ही अत्याचार हुए, कितने ही घर जले, गाड़ियाँ जलीं, मॉब लिंचिंग्स हुईं, हत्याएं हुईं, मगर यह जानकर देश हैरान रह गया कि इलेक्टोरल बाँड के माध्यम से न जाने कितनी बीफ-प्रोड्यूसिंग कंपनियों से बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए चंदे लिए। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी से लगभग 30 लाख नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। सात साल में 70

बार पेपर लीक हुए हैं। ...(**समय की घंटी**)... परीक्षाओं में शुचिता बरतनी चाहिए। आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी। हमारे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे लागू किया। वह बुढ़ापे की लाठी है। इसे पुनः बरकरार रखा जाए। अग्निवीर योजना चार साल की होने की वजह से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इसमें बदलाव करके, फिर से पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: थैंक यू, महुआ जी। श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल जी, आपके पास दस मिनट हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती महुआ माजी: मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पाँच मिनट... ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: टाइम ओवर हो गया है। ...(**व्यवधान**)... तीन मिनट, 33 सेकंड थे, आप अधिक बोलीं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... आपका समय खत्म हो चुका है, 3 मिनट, 33 सेकंड थे। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): सर, आज आपने मुझे यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका और मेरी पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ। चुनाव के बाद, यह हमारा पहला सेशन हो रहा है, तो मुझे डा. विश्वास की एक पंक्ति याद आ रही है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सत्ता के कारण अहंकार में लुप्त लोगों के क्या हाल होते हैं।

"उधर वे हाथों के पत्थर बदलते रहते हैं,
इधर भी अहल-ए-जुनूँ सर बदलते रहते हैं,
ये दबदबा ये हुकूमत ये नशा-ए-दौलत
किराय-दार हैं सब घर बदलते रहते हैं।"

सर, परिस्थिति बदलती रहती है और हम उसका साक्षी-प्रमाण लेते हैं। रावण को भी यही अहंकार था कि मैं सबका मालिक हूँ, रावण को यह अहंकार था कि मैं अकेला सब पर भारी पड़ूंगा, लेकिन वह भारी नहीं पड़ा और जो पूरी की पूरी रामायण हुई, वह आप सबको मालूम है। सत्ता पक्ष को यह एहसास दिलाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष, राहुल गाँधी जी ने किया है। कल के भाषण में उन्होंने उनके अहंकार का पूरे का पूरा मुखौटा फोड़ डाला और बता दिया कि आपका सत्य चेहरा क्या है। लोक सभा में तो उन्होंने कर ही दिया, यहाँ पर भी हमारे खरगे साहब ने भी यही वक्तव्य देकर, उन्हें पूरा आईना दिखाने का काम किया है। इस देश के 64 करोड़ लोगों ने मतदान के रूप में उन्हें यह बताया है, जताया है कि आप परमानेंट नहीं हैं, आपको भी कभी न कभी जाना है और वह जाने का समय नजदीक आ गया है। सर, अगर हम दस साल का हिसाब माँगेंगे, क्योंकि वे हमेशा 70 साल, 70 साल बोलते रहे हैं, तो हम दस साल का हिसाब माँगेंगे और पूछेंगे कि दस साल में आपने क्या किया, तो सिर्फ जुमले, सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ लोगों को भ्रमित करना, इतना ही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब हम 75 साल की आज़ादी का अमृत काल मना रहे

हैं, तो जब आप बाकी के क्षण याद करके बार-बार बोलते रहते हैं, दोहराते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए इस देश के बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। यहां पर अगर आपने कांग्रेस के योगदान को नकारा, तो यह आपकी गलती होगी। उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। सर, इनको selective Alzheimer है। ये कभी-कभी भूल जाते हैं और कभी-कभी उनको अचानक से याद आता है। जैसे आमीर खान की एक पिक्चर गजनी आई थी, वैसे ही बीच में कुछ याद आता है और बीच में भूल जाते हैं। सत्ताधारी यह भूल जाते हैं कि इस देश को यह चेहरा देने का काम कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने और इस देश की जनता ने किया है। इस देश में चाहे वह आईआईटी हो, आईआईएम हो, स्कूल्स हों, कॉलेजेज़ हों, हम सबको यहां पर आने की जो ताकत मिली है, वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। वे यह भूल जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन एक परिवार में बाप जब बच्चों को बड़ा करता है, उनको सिखाता है, उनको खिलाता है, उनको बड़ा करके नौकरी में लगाता है और अगर बच्चे बाप को पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो बाप बोलता है बेटा, बाप तो बाप ही होता है। वैसे हम बाप ही हैं। अगर बेटा नालायक भी हो, लेकिन हम तो बाप ही हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह बोला कि दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। यही competitive cooperative federalism की सच्ची spirit है, यह भी उन्होंने बोला था। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूं और मैं महाराष्ट्र में इसका उदाहरण देकर बोलना चाहती हूं कि इन तीन-चार सालों में जितने भी 16-17 जो उद्योग आए थे, वे सबके सब महाराष्ट्र से गुजरात में ले जाने का काम इस डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है। **..(व्यवधान)...** मैं यह बताना चाहती हूं कि Vedanta-Foxconn, submarine project, Tata-Airbus, Bulk Drug Park, diamond park, ये तो दो-चार नाम हैं, लेकिन सभी के सभी **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: आप इधर चेयर की तरफ देखकर बोलें। प्लीज़, सीट पर बैठकर न बोलें।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः इन सभी को गुजरात में ले जाने का काम किसी ने किया है। जब ये cooperative federalism की बात करते हैं, जब ये बोलते हैं कि हमें सबको साथ में लेना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में आए उद्योगों को आप गुजरात में लेकर जाते हो, यह कहां का न्याय हुआ, यह आप बताइए? महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा डाकाखोरी, मुझे मालूम नहीं है कि यहां डाकाखोरी, दरोडेखोरी नाम अलाउ है या नहीं, लेकिन अगर ये हुई है, तो हमारी गवर्नमेंट में हुई है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक पार्टी का नारा बन गया था, 50 खोखे बाकी सब ओके। यानी 50 खोखे ले लो और पार्टी छोड़ो और बीजेपी में जाकर वॉशिंग मशीन में धुलकर आ जाओ। यह हमारा नारा था **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: मैंने आपसे आग्रह किया गया था कि जो भी मेम्बर्स एलिगेशन लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको rules substantiate करना है। आपको उसको सर्टिफाई करना है कि...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः सर, मैं करूंगी।

श्री उपसभापति: उसे आप रिकॉर्ड पर रखें।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: हमारे यहां छोटा-छोटा बच्चा भी बोलता है...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As per Rule 238, आपको सर्टिफाई करना होगा, substantiate करना होगा।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: छोटा बच्चा भी बोलता है, 50 खोखे बाकी सब ओके। यह नारा बहुत प्रसिद्ध हो गया है। दूसरी पार्टी को भी कभी सुबह 7 बजे शपथ विधि की, कभी दोपहर में किया, एक-एक पार्टी, एक-एक घर तोड़-तोड़कर, तोड़-मरोड़कर उन्होंने अपनी गर्वनमेंट बना ली। हमारे बाकी के लोग यहां बोले कि जिनको वॉशिंग मशीन में डाला, जिनके ऊपर आपने अमुक घोटाला, तमुक घोटाला, 70 हज़ार, 80 हज़ार इतने बड़े-बड़े नाम लिए थे, उन सभी लोगों को पार्टी में लिया, वॉशिंग मशीन में डाला और वे एकदम साफ हो गए। उनमें एकदम निरमा की चमक आ गई, गुजरात का निरमा है, तो वहां की चमक आ गई। फिर उन लोगों को उन्होंने यहां पर पहली लाइन पर बैठाया है।

सर, मुझे इतना ही कहना है कि जब हम बोलते एक हैं और करते एक हैं, तो कम से कम जो लोग हमारे साथ रहते हैं, उनका तो हमें बिल्कुल साथ देना चाहिए। कभी ईडी, कभी सीबीआई और दस साल से उन्होंने यह undeclared emergency लगाई कि अगर कभी भी खिलाफ में बोले, तो अंदर। लोग बोलने से भी घबराते हैं। हमारे साथ बात करने से भी घबराते हैं। यह जो डर है, यह जो भयानक स्थिति है, हमें उसे कम करना चाहिए। राज्य के विकास में देश का विकास - यह महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला था। राज्य के विकास में ही देश का विकास होता है। क्या यह राज्य का विकास हो रहा है? जैसे आप एक राज्य को कम देते हैं और एक राज्य को ज्यादा देते हैं, यह कहां का federalism है? राष्ट्रपति जी ने बोला था - विकसित भारत तभी संभव है, जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। यह उनकी स्पीच का वाक्य है। सर, गरीब बेरोजगारी से जूझ रहा है, मंहगाई से जूझ रहा है। आप कहां से उनको सपने दिखाते हो? आप कहां से अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि ये बहुत अच्छे दिन हैं। आपके अच्छे दिन का सपना तो कभी का कभी हवा हो गया है। युवाओं को अपना भविष्य मालूम नहीं है, क्योंकि वे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज हमारे महाराष्ट्र के युवा इसलिए भ्रमित हैं, क्योंकि जो उनकी जमीन थी, उसमें उत्पादन नहीं होता है। MSP legalise नहीं हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, मराठवाड़ा क्षेत्र से, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर इतना मराठा आंदोलन चल रहा है कि वहाँ लोग आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, क्योंकि उन बच्चों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। वे कहते हैं कि आप आरक्षण की बात करते हैं, हमें तो न्याय दे दो। हमें वह न्याय देने की जरूरत है और उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

सर, मैं महिलाओं के लिए बात कहूँगी। महिला आरक्षण से पहली बार मैं जिला परिषद में चुन कर आई थी। हम पहली बार आए थे, जब हमारे नेता, राजीव गाँधी जी ने वह आरक्षण दिया था। उन्होंने 33 प्रतिशत महिलाओं को पंचायतों, नगर पंचायतों में आरक्षण दिया और उसके तहत हम लोग पहली बार चुन कर आए। तब से यहाँ तक लाने का काम हमारी पार्टी ने किया। हमारे

प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने last Session में 'नारी शक्ति वंदन' declare कर दिया। देश भर की सभी नारियों को बुलाया और खुद का सम्मान करवा लिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमें 10 साल के बाद मिलने वाला जो आरक्षण है, उसके लिए आप अभी से बात करते हैं। बीरबल की जो खिचड़ी है, वह कब पकेगी, इसके लिए हम wait कर रहे हैं। बीरबल की खिचड़ी पक ही रही है, इसके लिए हम wait कर रहे हैं।

सर, मुझे यहाँ एक बात जरूर कहनी है कि सदन में narrative की बात की गई। जो narrative है, वह narrative किसी ने set नहीं किया, वह लोगों ने अपने आप समझ लिया है। किसी ने भी लोगों के मन में कुछ डाला नहीं। Narrative set हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने भाषणों में बोला कि अगर हमें ज्यादा बहुमत देते हैं, तो हम इस घटना को बदल देंगे और कैसे हम चमत्कार करके दिखाएँगे, ऐसा बताया गया था। अगर आप नाम भी चाहते हैं, तो मैं उनका नाम ले सकती हूँ, लेकिन यह वाजिब नहीं होगा। इन सब सांसदों ने narrative बनाया।

सर, हमारे नेता, विपक्ष कल मूर्तियों के बारे में बोले। मूर्तियों के बारे में उनका कहना यही था कि इसके लिए एक कमिटी होती है। अगर पार्लियामेंट में कोई फोटो भी लगानी होती है, तो वह कमिटी में मंजूर होती है और मंजूरी मिलने के बाद उसे लगाया जाता है। यह तो हमें मालूम ही नहीं था, हम ढूँढ़ते रहे कि गाँधी जी कहाँ हैं, हम ढूँढ़ते रहे कि अम्बेडकर जी कहाँ हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ हैं। उनकी मूर्तियाँ ही गायब! जब हम आए, तो मूर्तियाँ गायब थीं और अभी बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छी जगह पर रख रहे हैं।

सर, मुझे यही कहना है कि कम से कम लोगों की नजर पड़े, ऐसी जगह आपको रखनी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)...

इसके आगे मैं यही बोलूँगी कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कम से कम 3-4 बार सुनने के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन मेरी यही विनती है कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके ऊपर आप विचार करें। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shrimati Rajaniji. श्रीमती सागरिका घोष जी।

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Thank you hon. Deputy Chairman, Sir, this is my maiden speech, I hope you will give me a little bit of extra time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have fifteen minutes.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: At the outset, I would like to thank my party leaders, Ms. Mamata Banerjee, Mr. Abhishek Banerjee for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks of the President's Address. I would like to humbly thank every citizen of Bengal and every party worker of the All India Trinamool Congress because of whom I stand here today.

Sir, I come to Parliament as a student of history and inspired by the great founders of our republic. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore and B. R. Ambedkar. Each of them has given us a life lesson. What has Mahatma Gandhi taught us? He has taught us that to create political transformation, there needs to be transformation of the self. Mahatma Gandhi has written a wonderful essay in the Harijan weekly on 3rd October, 1936 where he likens the war in the Mahabharat to a philosophical metaphor. This is the war within. The war within between our best self and our worst self. It is when our best self triumphs over our worst self that is when we can create the perfect society and the just society. So, the key to social and political transformation is the transformation of the self. Let us be our best self and cast out anger and hatred.

Nehru taught us that only constitutional representative, parliamentary democracy can improve the conditions of humanity at large. No other system of Government, Sir, not military dictatorship, not the One Party State, not any form of dictatorial regime can do this. It is Constitutional parliamentary representative democracy that can improve the condition of humanity and give justice and opportunity for all. I want to remind you that in the 1950s, Nehruvian parliamentary democracy was such that there was one star in that parliamentary system who shone and who became a colossal leader. This leader was Shri Atal Bihari Vajpayee. He shone in Nehruvian parliamentary democracy. It was Nehruvian parliamentary democracy which made possible the emergence of Nehru's rivals. This is the beauty of parliamentary democracy. Vajpayeeji was a critique of Nehru; Vajpayeeji was an ideological opponent of Nehru, but was given a stage and a platform by Nehru. Our founders dreamt big. They had the audacity of hope. At Independence, we had 80 per cent incidence of poverty; we were 12 per cent literate. Yes, we were poor and not literate; but we decided to be a parliamentary democracy. What a dream, Sir, what a hope! Our founders taught us that for this end, we need to inculcate the virtue of reason and rationality. When leaders propagate irrationality, when they propagate magical thinking, when they propagate superstition, when they claim to be non-biological beings, they put citizens back to a place where citizens are not able to think and reason. We recall the words of Rabindranath Tagore: Let my country be one where, "the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit". What did Dr. B.R. Ambedkar teach us? Dr. B.R. Ambedkar said that our political democracy will not last if at its base there is no social democracy. We can't have political democracy without social democracy; without liberty, without equality, without fraternity in society, we will not be able to sustain our political democracy.

Sir, I have been a journalist for thirty years, criss-crossing India writing reports and writing articles. I was fiercely non-aligned and independent. Today I am fiercely aligned and, paradoxically, by being fiercely aligned to the right values, to constitutional values, to the values of protecting democracy, I feel I can speak the truth. Journalism once had a golden age. Doyens of the free press asked fearless questions of the powerful. Look at the state of the media today. Look at the mainstream newspapers. Look at the television channels. There is one ideology that has a ferocious stronghold. There is one school of thought that is dominant. A hidden hand is guiding the camera. A not-so-hidden hand is guiding the journalistic pen. What is happening to the media is that it has been captured. The media has been captured. Most of the legacy media can't ask questions of the Government anymore. But, without asking questions, how can democracy breathe? If journalists can't tell truth to power, how can democracy get oxygen? Legacy media is getting suffocated in an airless, oxygen-less jail. When media is in jail, how can democracy survive? That is why I have chosen to speak today in response to the hon. President's Address on what I call the 'Democracy Deficit'.

I humbly thank the hon. President of India for her Address. In the Address, the respected President said in para 17: 'The basic spirit of democracy has been greatly undermined.' But undermined by whom? In para 28, the hon. President refers to the Emergency of 1975. But, Sir, we are not in 1975. We are in 2024. How long are we going to look in the rear view mirror? How long are we going to use the sins of the past to condemn the present? ...(*Interruptions*)...

Those who are obsessed with the Emergency of 1975: if they want to oppose the Emergency, why don't they bolster democracy? Why are they imprisoned in an 'Emergency mindset'? Why don't they set free the police, as per the 2006 Supreme Court judgment? Why don't they uphold the federal principle? Why don't they make India safer for dissent? Why don't they allow the Opposition a voice? Why don't they stop having a stranglehold on democratic institutions? That is the way to oppose Emergency. But what is the point of always opposing the Emergency, talking of 1975 and then doing the same thing as in 1975, implementing 1975, imitating 1975? Those who are constantly talking about the Emergency of 1975 are victims of an 'Emergency mindset', which is why we have a 'Democracy Deficit' today.

Here are 15 examples today of India's 'Democracy Deficit'. When the Government shows no visible empathy to the suffering, we have a democracy deficit. When instruments of State are used to partisan ends, we have a democracy deficit. When citizenship is defined by religion, we have a democracy deficit. When the party system is attacked, we have a democracy deficit. When there are attempts made to

delegitimize the opposition, we have a democracy deficit. When free press is crushed, we have a democracy deficit. When hate speech is normalized, we have a democracy deficit. When lynch mobs are not given exemplary punishment, we have a democracy deficit. When official speeches do not mention even one word of the name of a State which has witnessed a civil war for over a year (when Manipur is not mentioned) we have a democracy deficit. When those in power are not accountable, we have a democracy deficit. When individuals believe they are bigger than institutions, we have a democracy deficit. When citizens are not told the truth, we have a democracy deficit. When the federal principle is buried, we have a democracy deficit. When we don't celebrate religious pluralism as Indian's greatest strength, we have a democracy deficit. When protest is criminalized, we have a democracy deficit. A quick expansion of all of these.

Sir, the principle of empathy: Sir, to quote Shakespeare, "the quality of mercy is not strained; it droppeth like the gentle rain from heaven". In the same way, Sir, where is the quality of empathy? Empathy is a principle of good governance. Sir, 23 lakh students sat for the NEET. A desperate child takes an examination, finds that the paper has leaked, loses that examination, goes on the streets to protest and the Education Minister says that this is a "motivated protest" and it did not happen. Where is empathy, Sir? Sir, my son is a doctor. I have seen the hard work and the herculean effort that students put in pushing themselves to the brink to prepare for these examinations. Where is empathy for these students who are on the streets and desperate? Sir, 26 students in 2023 took their own lives in Kota! Sir, 70 papers have leaked in seven years. This is the anguish students are facing today.

Sir, there is democracy deficit when instruments of State are used for partisan purposes. When enforcement agencies become a washing machine, one side always guilty and the other side is always innocent. The moment you switch sides, you are deemed innocent. Among politicians, 95 per cent cases of enforcements agencies are against opposition politicians. Since 2014, 25 opposition leaders facing probes have crossed over to BJP and 23 of them have got clean chits.

There is a democracy deficit when Citizenship is linked to religion. How can religious identity be the basis of citizenship? This is a principle our founders would have opposed with all their might. Sir, 19 lakh excluded in Assam. Majority of them are Hindus. Sir, 41 lakhs are still living under threat of the CAA and the NRC. Lakhs of people worried that an unconstitutional law is taking away their lives, taking away their liberty, taking away their homes, taking away their universe because of an unconstitutional law imposed from above.

There is a democracy deficit when the party-system is attacked. With allurements and inducements parties are broken, Governments are toppled and administrations are brought down — nine Governments toppled in nine years.

There is a democracy deficit when attempts are made to delegitimize the Opposition. You just don't want to win; you want to delegitimize the Opposition completely. Why this name-calling 'Khan Market Gang', 'Tukde-Tukde gang', 'Lutyens' gang' for the Opposition, Sir? The Opposition is an established part of the democratic system. The Opposition is very much part and parcel of the Parliamentary democratic system.

In a democracy, the people are sovereign. When sovereign people vote for the Opposition, how can those elected representatives be delegitimized? This is not the politics of democracy. This is authoritarian populism. This is strongman politics. It is not enough to win, you want total domination. This year voters have cut you to size and, in fact, voted for the Opposition.

There is a democracy deficit when free press is crushed. As I mentioned earlier, India ranked 159 out of 180 in the Annual World Press Index released by 'Reporters Without Borders'. India's press freedom has fallen by 19 places since BJP-led dispensation came to power in 2014.

In Para 26, the hon. President of India said in her Address, 'In the era of communication revolution, disruptive forces are conspiring to weaken democracy.' But, who is weakening the democracy in the media, Sir? Democracy is being weakened by an overbearing Government which is guiding, manipulating, terrorising, muzzling and threatening journalists. I was shocked to see that journalists are not allowed, accredited senior journalists today are not allowed, in the precincts of Parliament! This is truly shocking for a parliamentary democracy. There is a democracy deficit when hate speech is normalised. When hate speech against religious communities is normalised and acceptable, and those who are responsible for the hate speech get State protection. Seventy-five per cent of hate speech events come from the States ruled by the BJP, according to the India Hate Lab. There is a democracy deficit when lynch mobs are not given exemplary punishments. Does the Government care that three men died in a horrific case of mob lynching in Chhatisgarh, earlier this month? There have been many such crimes which have gone unnoticed. A report by the IndiaSpend reveals that out of total attacks between 2010 and 2017, centred on cattle-related issues, 97 per cent cases were reported in just three years, that is, from 2014 to 2017. Sixty-one, out of sixty-three such cases, are registered after creation of Cow-Protection Squads and beef trade restrictions, showing that it is under the BJP's dispensation that these attacks have increased.

There is a democracy deficit when a civil war has raged for over a year in a State and that State's name cannot be mentioned by the hon. President in her Address and the Prime Minister does not visit even once the state of Manipur where over 70,000 people have become homeless and over 200 have died. There is a democracy deficit when those in power are not accountable. There is a little accountability, of those in power, neither to students nor to rail victims, nor to unemployed youths, nor to the women who are victims of crime. There have been 244 consequential train accidents between 2017 and 2022. Does the Government care?

The BJP was proudly proclaiming that it brought in the Women's Reservation Bill. But the percentage of tickets given to women by the BJP, this time, was just about 15 per cent. The All India Trinamool Congress has given almost 30 per cent tickets to women. Thirty-eight per cent of our MPs are women. There is a Bengal model of women's empowerment that should be emulated across India because in Bengal, leaders are accountable for their promises. There is a democracy deficit when individuals believe that they are bigger than institutions, when there is arrogance of power. Gandhi*ji* believed that means must be good for ends to be good...*(Time-Bell rings.)*... Gandhi*ji* called off the Non Cooperation Movement, 1922, after Chauri Chaura incident. ...*(Interruptions)*... because it became violent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: Sir, today, power has become performative. Power exists only for itself. Power is projecting itself onscreen. ...*(Interruptions)*... Power is not being used for the people. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Sagarika*ji*. Your time is already over. Next, Dr. Kanimozhi NVN Somu. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: There is democracy deficit when the truth is not told. When citizens are not told of the facts. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over, please. ...*(Interruptions)*... You have already taken your time. ...*(Interruptions)*... डा. कनिमोझी, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...*(Interruptions)*...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, I express my thanks and gratitude to my leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy

M.K. Stalin, for giving me this opportunity to stand upright and speak the truth in this august House.

The hon. President, in her Address, mentioned that they have formed the third consecutive Government, but forgot to mention that it is only a minority BJP Government, with the support of the NDA constituents.

It is like a crippled Government getting support from others to stand and move. It is a big blow for their party, which boasted itself so high as if they were going to win 400 seats. The slogan *"अबकी बार 400 पार",* turned out to be *"अबकी बार चॉकोबार".* Let them enjoy the bar until it melts.

Sir, the world has seen many leaks, USA saw WikiLeaks. But, during the last ten years of Modi *Sarkar,* several leaks have been seen. The NEET question paper leaks; the NET question paper leaks; airport's roof leaks; Ram Lalla Temple roof leaks; Vande Bharat Express leaks; so many video leaks; so many audio leaks. But the nation bleeds. The frequency of various collapses, which occurred in India under Modi Government, is faster than the bullet trains. Sir, we just won the T-20 World Cup. And, Modi*ji* has got a hat trick in that. On March 10, 2024, Jabalapur Airport was inaugurated and on June, 27, it collapsed. On March 10, 2024, the Union Government inaugurated and laid foundations for new terminal buildings and on June 28, Terminal-1, Delhi Airport, collapsed. On July 27, 2023, the Prime Minister had dedicated the Rajkot airport to nation and on June 29, it collapsed. Who knows, they may also say that since T-1 International terminal is in the name of Shrimati Indira Gandhi who happens to be the daughter of Pandit Nehru, that was the reason for the collapse of that Terminal! ...*(Interruptions)*... We never know. Sir, these can be categorised by alphabetical order. 'A' stands for Airport roof collapses, 'B' stands for Bridge collapses, 'C' stands for Currency collapses, 'D' stands for Democracy collapses, 'E' stands for Economy collapses and 'F' stands for Federalism collapses. We do not know how many more alphabets are going to be conquered by the Government until they come to an end.

Sir, in Para 28, as mentioned by our floor leader, Mr. Tiruchi Siva, our party suffered the Emergency. The President's Address also refers to it. If you are so really against the Emergency, please bring back the 'Education' from the Concurrent List to the State List.

Sir, in Para 12, the hon. President has mentioned about the women demanding representation in Parliament and the Legislative Assemblies. We all know what an eye wash was the Women's Reservation Bill. To implement it, first, delimitation of constituencies has to be done. For implementing delimitation, latest Census has to be

done. In Tamil, we have a proverb saying when something is not possible *"Finding path to a place not to be reached." That is, to go to a place where we don't know the routes. This suits aptly to the schemes of Modi's BJP Government.

In Para 19, it is mentioned that in the last 10 years,15 AIIMS medical college have been built. Sorry, there is a correction. It is literally only 14 AIIMS medical college because in Tamil Nadu, AIIMS college is just a brick and a compound wall and, still, we have not got the college.

Sir, in Para 20, the hon. President makes a remark, "Even earlier, we have witnessed many instances of paper leaks." We just cannot say this and play with the lives of the students. It is just not only the students; it is the entire family who works for the education of the student. Until now, the Government has not opened the mouth about the NEET scams.

Sir, in the present scenario, the economic inequality is the biggest problem faced by our country. The 'billionaire raj' is now more unequal than the British Colonial Raj. What is particularly worrying in India's case is that the economic inequality is being added to the society that is already fractured along the lines of caste, religion, region and gender. That is why an exhaustive caste based census is the need of the hour. But this Government has conveniently forgotten about conducting a census. The data available is decades old and we are not certain about the present data which is very essential for policy making.

Sir, the BJP Government has turned a blind eye towards the non-BJP ruled States like Tamil Nadu and others, often shows a step-motherly attitude towards the people of Tamil Nadu for reasons better known only to them. This is against the cooperative federal system prescribed in our Constitution. Tamil Nadu has been betrayed in this Government in all spheres of work, even though it contributes substantially to the Central Exchequer. The Madurai AIIMS is going on like a Sindbad story. The Union Government has no* in admitting the inordinate delay in construction of AIIMS in Madurai. The Union Government has so far not paid a single rupee for the execution of the Chennai Metro rail phase-II project, which is a very important infrastructure project to ease the traffic in the ater Chennai region.

Just a few weeks before the 2021 Assembly elections in Tamil Nadu, the hon. Prime Minister had openly announced that the Union Government has sanctioned a record amount of Rs.63,000 crores in one go to execute the project but in 2024, not even a single rupee has been given by the Union Government for this crucial project.

---

*English translation of the speech delivered in Tamil.

* Expunged as ordered by the Chair.

Why this partiality, Sir? Are the Prime Minister and his Cabinet colleagues angry with the people of Tamil Nadu for not winning a single Lok Sabha seat from Tamil Nadu? Are you taking a revenge on the people of Tamil Nadu for your failure to win seats from Tamil Nadu? This is not democracy, Sir. This does not reflect the true spirit of cooperative federalism enshrined in our Constitution. No other Government in the past has seen the value of Indian rupee against the US dollar fall so badly. But, still, the Government is trying to convince the people in its own saying that 'the value of Indian rupee is not falling, only the value of the US dollar is growing'. This is something which needs to be really laughed at. Sir, the Government had promised to create 20 lakh crore new jobs but what has happened in the past 10 years is a catastrophe. Sir, 10 crore people have lost their jobs and fallen into the dirty dumps of unemployment. People are getting sacked from their jobs continuously. This Government's much-hyped promise of doubling the farmers' income by 2022 remains a day-light dream. Unfortunately, the number of farmers committed suicide has only doubled.

Sir, this Government in the past had brought in several draconian laws even without the Opposition there to discuss them by sending all of us out of this House. Because you had a brute majority, that is why, people have reduced you to minority. Even now, if you don't change your nature, the people will throw you out of power soon.

Sir, before I conclude, I would like to remind the Government with two sentences. Remember, whatever happens, a Promise is always a Promise. An unfulfilled promise is a curse. People especially, the poor, downtrodden and middle class live with faith and hope. For Heaven's sake, don't kill them by giving false hopes and fake promises. Please be aware of the power of the curse of innocent poor and downtrodden people. It is more powerful than the scud missiles. At least, from now on, be faithful and loyal to the people who have voted you. Practice the art of delivering the promises to the poor middle class population of the nation and uphold social justice, equality, communal harmony and cooperative federalism. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Kanimozhi. माननीय श्री राघव चड्ढा जी। वे सदन में नहीं हैं। श्रीमती सुलता देव। आपका दस मिनट का समय है।

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): जय जगन्नाथ। उपसभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं मेरे सभापति श्री नवीन पटनायक जी की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा और मैं यहां ओडिशा को रिप्रेजेंट कर

पा रही हूं। राष्ट्रपति जी ओडिशा से belong करती हैं, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और वे ट्राइबल्स को भी belong करती हैं, यह और भी बड़ी बात है। मैं उनके अभिभाषण को क्वोट, अनक्वोट कर रही हूं, जो पैरा 3 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला। "दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है।" सर, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति जी लोकमत और जनमत से वाकिफ नहीं हैं। यह न ही स्थिर सरकार है और यह भी पता नहीं है कि स्थिर सरकार कब तक चलेगी और न ही यह बहुमत की सरकार है। यह कैसे चलेगी? यह हाथ में बैसाखी लेकर ही चलेगी। अगर देखा जाए, तो यह 'एनडीए' नहीं है, बल्कि यह 'एनएनडीए' सरकार है - नीतीश, नायडू के साथ एलायन्स करके ही यह सरकार चल रही है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बिंदुओं को टच करूंगी, उससे पहले मैं ओडिशा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे से बोला कि लोक सभा का चुनाव हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और भी बहुत अच्छा बोला, जिससे सुनने में सबको सब कुछ हरा-भरा और गुलाबी लगे। अगर देखा जाए, तो आंकड़े कहीं हैं और सच्चाई कहीं और थी, क्योंकि जब इलैक्शन हो रहे थे, तो मैं किसी और राज्य के बारे में बोलूं न बोलूं, सबको मालूम है, जो लोग हमें यहां से देख रहे हैं, यह सबको मालूम है कि किस तरह से कैम्पेन चल रहा था। मैं मेरे ओडिशा के बारे में बोलूंगी कि किस तरह से कैम्पेन चल रहा था, जब इलैक्शन हो रहे थे। कैसा * कैम्पेन चल रहा था, कैसा जुमला कैम्पेन चल रहा था, मैं यह कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं मेरे सभापति नवीन पटनायक जी को अच्छी तरह से जानती हूं और मैं ही नहीं, बल्कि सारा भारत जानता है कि वे किस तरह के इंसान हैं, वे कैसे सेंसिटिव इंसान हैं, कैसे humble इंसान हैं। किस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पर सपोर्ट किया है, unconditional support भी किया है, जिसमें देश की भलाई हो। अगर देखा जाए कि क्या हुआ, जब निर्वाचन हुआ, जब कैम्पेन शुरू हुआ, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी तबीयत को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बोला, वे अपनी गरिमा भी भूल गए। वे बोले, 'नवीन पटनायक जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बंदी जैसे बनाकर रखा हुआ है। अगर हम लोग सरकार में आएंगे, तो नवीन पटनायक जी की हेल्थ का चैकअप करेंगे।' हम एक कमेटी बनाएंगे और वह कमेटी नवीन पटनायक जी के स्वास्थ्य की जांच करेगी। मान्यवर, मैं आपसे यह गुजारिश करती हूं कि जब बीजेपी ने ओडिशा में नई सरकार की शपथ ली, तब हमारे राज्य के एक्स चीफ मिनिस्टर, श्री नवीन पटनायक जी, जो हमारे सभापति हैं, वे शपथ ग्रहण के समारोह में गए थे। मान्यवर जी को पता तो चल गया होगा कि वे ठीक हैं या नहीं, तो फिर यह क्या था, यह * क्या था ? मतलब यह है कि आप * बोलो, * के ऊपर * बोलो और * को सच करने के लिए और * बोलो। क्या आपका कैम्पेन यही है? मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, देखिए, आपने जो-जो बातें बोलीं, उन्हें ओडिशा के लोगों ने सब याद रखा है, वे सब याद रखेंगे और आज नहीं तो कल इसका जवाब देंगे। क्योंकि आपने बोला रत्न भंडार, हमारे जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार है, उस रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु ने ले ली, मगर देखा जाए तो हमारे आद्य साधक गजपति महाराज जी हैं, वे क्या बोले, वे बोले कि चाबी सही सलामत है, फिर क्या हुआ, आप क्यों ऐसा बोले? आपने बोला कि चाबी

---

* Expunged as ordered by the Chair.

तमिलनाडु चली गई, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप इलेक्शन में प्रचार के लिए कुछ भी बोल सकते हैं? फिर आपने वायदा किया कि हम सरकार में आएंगे, तो रत्न भंडार को 6 दिन में, 8 दिन में खुलवा देंगे। आपको आए हुए तो कई दिन हो गए अभी तक रत्न भंडार तो खुला नहीं, क्या यह भी एक जुमला था? सर, एक बात और है, आपने बोला कि जब हम सरकार में आएंगे, तो पुरी के चार द्वार खोल देंगे। आपने चार द्वार खोल भी दिए, मगर उसके बाद क्या हुआ? जब आपने चार द्वार खोले, वहां पर इतना stampede हुआ, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, जिसके कारण आपने तीन द्वार को एग्जिट करने के लिए खोला और एक द्वार को एंट्री करने के लिए खोला। यह कहां की बात हुई? हमारी ओड़िया में बोलते हैं, 'यथापूर्वम् तथापरम्' । आपकी नज़र में वे चार द्वार खुले, मगर सच में देखा जाए, तो एक द्वार ही खुला।

सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला है, पैरा 19 में बोला है कि मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए ज़रूरी माहौल बनाने में जुटी है। कैसा ज़रूरी माहौल बनाने में जुटी है? कैसे ये युवाओं के सपने पूरा करते हैं, ये नीट स्कैम करके! ये नीट स्कैम करके! लाखों-लाखों युवक-युवतियां, जो छात्र-छात्राएं हैं, इस नीट स्कैम की वजह से वे बहुत मुश्किल में हैं। यह एक ही स्कैम नहीं है, इस एक स्कैम से पता चल गया कि पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कैम है। यह एक स्कैम नहीं है। अगर देखा जाए, तो सात साल में 70 स्कैम्स हुए हैं और एक करोड़ 70 लाख बच्चे इसमें प्रभावित हुए हैं। अगर इसमें उनके मां-बाप को जोड़ लिया जाए, तो कम से कम पांच से सात करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इसका जिम्मा कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी तो किसी को आगे बढ़कर लेनी चाहिए। आप अगर बोलेंगे कि हम सही चला रहे हैं, युवक और युवतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या यही है आपका उनको आगे बढ़ाना? मैं तो आपके माध्यम से कहूंगी कि नीट के जो क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं, इसके लिए आप एक कमेटी बैठाइए, जो एनटीए कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे हैं, इसके लिए एक कमेटी बैठाइए, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में, क्योंकि एपेक्स बॉडी में न मेरा विश्वास है, न किसी और को विश्वास है। इसके बारे में आपको भी पता है, इसलिए ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, आपने जीएसटी को बारे में बोला है। अगर जीएसटी के बारे में बोलेंगे, तो एजुकेशन में, शिक्षा में 18 परसेंट जीएसटी ले रहे हैं, मगर डायमंड में दो परसेंट ले रहे हैं। इसमें से कौन-सा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है या हीरा व्यापारियों के लिए दो परसेंट जीएसटी जरूरी है?

हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी ने बार-बार, सौ बार चिट्ठियां लिखी हैं, महामहिम जी खुद एक ट्रायबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, ट्रायबल कम्युनिटी में कम से कम 10 लाख ऐसे ट्रायबल्स हैं, जो केंदू पत्ता को pluck करने के लिए जाते हैं और आपने केंदु पत्ता पर जीएसटी को 5 परसेंट से बढ़ाकर 18 परसेंट कर दिया है। लगभग सौ बार चिट्ठी लिखी गई है कि आप केंदु पत्ते में जीएसटी कम कीजिए। महोदय, केवल इतना ही नहीं है, आप केंदु पत्ते में 18 परसेंट जीएसटी लेते हैं, केंदु पत्ते से जो बीड़ी बनती है, उसमें भी 18 परसेंट लेते हैं और बीड़ी बन जाने के बाद भी 18 परसेंट लेते हैं, इस तरह से कितना परसेंट हुआ? इस तरह से 54 परसेंट हुआ। आप 1 रुपये में 54 पैसा ले जाते हैं। क्या यही है सरकार का विज़न? मैं फिर से बोलूंगी कि आप रेलवे के बारे में बोल रहे हैं और इसमें आप बुलेट ट्रेन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ओडिशा के 8 जिलों को रेलवे की एक लाइन ने भी टच नहीं किया है।

क्या हुआ है और ऐसा क्यों है? अगर देखा जाए, तो ओडिशा राज्य रेलवे को बहुत सारा रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके 8 जिले रेलवे ने अभी तक टच भी नहीं किए हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बार-बार बोला है कि काम के लिए 50 परसेंट योगदान देंगे, फ्री में जगह देंगे, लेकिन उस पर भी आज तक काम नहीं हो पाया। जिन लोगों ने ट्रेन ही नहीं देखी है, वे लोग बुलेट ट्रेन का क्या सपना देखेंगे? हमें सब जगह के लिए ट्रेन चाहिए। इसके साथ ही एक और बात है। महोदय, हम बालासोर का तो देख ही चुके हैं, इसलिए अब हमें कहीं न कहीं रेल में सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। ..(**समय की घंटी**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्रीमती सुलता देव: सर, एक मिनट, मैं कन्क्लूड कर रही हूं।

आप रेलवे देखिए, एनएच देखिए। हमारे ओडिशा में जो एनएच हैं, मैं उसके बारे में और एक बात बोलती हूं।* "You undo more than you do." यह मैं क्यों बोली हूँ? आप लोग बोलते हैं कि एक दिन में 39 किलोमीटर एनएच बन रहा है, लेकिन एनएच 55, जो हमारा कटक-अंगुल है, संबलपुर है वाया अंगुल, उस पर आज तक वह काम नहीं हो पाया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें जितने लोगों की जान गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री उपसभापति: श्रीमती सुलता देव जी, आप कन्क्लूड कीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्रीमती सुलता देव: हम लोग आज तक भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक सिस्टम नहीं है, रेल नहीं है। इस तरह से कैसे काम होगा?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्रीमती सुलता देव: मैं इसीलिए बोल रही हूं कि ओडिशा को स्पेशल फोकस्ड स्टेट की मान्यता कीजिए।..(**व्यवधान**)..

2.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. V. Sivadasan, please speak. आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Mr. Deputy Chairman, Sir, I am representing the Communist Party of India (Marxist) which has not received a single rupee through electoral bond, a corrupt practice introduced by the BJP Government. Here, in India, we see everywhere the evidence of corruption done by this

*English translation of the speech delivered in Odia.

Government. This Government came back to power in the name of Lord Rama. But they have used the name of Lord Rama for their corruption and making money. The believers, including our family, chant the name of Lord Rama for a better future and salvation. But this Government chant the name of Lord Rama for making money and hiding their corruption. They have made a huge amount of money for their electoral purpose. The priest of Ram Temple told us that the roof of Ram Temple is leaking. The cost of Temple construction is Rs.1800 crore. Ram Temple was opened by *Sampujya Pradhanmantri* Narendra Modi*ji*. There are big potholes on Ram Path now. The cost of construction of Ram Path is Rs.845 crore. Who has inaugurated it? It was *Sampujya Pradhanmantri* Narendra Modi*ji*. The wall of the railway station in Ayodhya has collapsed. These incidents reveal the depth of corruption of this Government. Common people are saying that God Rama has punished the corrupt Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please authenticate it.

DR. V. SIVADASAN: That is why the BJP has lost its seat in Faizabad where the Ram Temple is situated. सर, आपको पता है कि after Ayodhya, they were saying, "काशी-मथुरा बाकी है।" In Mathura, the day before yesterday, a big water tank, which was built in 2021, collapsed. Innocent people were killed. Many people have been injured. It is a clear case of corruption.There is nobody to ensure safety and security of the people. सब राम भरोसे पर है। We know that communalism is moral corruption, but now, we know that communalism also leads to economic corruption. सर, आपको पता है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर क्या हुआ? The roof of Terminal-1 collapsed because of lack of proper maintenance and care. The innocent people suffered. Deaths have been reported. In Gujarat also, just one day after the Delhi airport incident, the terminal of Rajkot Airport collapsed. In Madhya Pradesh, the terminal of Jabalpur Airport has collapsed. They had spent Rs.450 crore for the construction of this airport. It was inaugurated by Sampujya Pradhan Mantri Narendra Modiji. Then, what has happened to Atal Setu in Mumbai? 'Atal' means 'firm', लेकिन अटल सेतु अटल नहीं है। The cracks have been reported there.They spent Rs.17,480 crores on Atal Setu. It was inaugurated by Sampujya Pradhan Mantri Narendra Modiji. In the last 20 days, six bridges have collapsed in Bihar.

Then, what is the situation in the education sector? 'NEET' is not 'neat' anymore. NEET question paper leak is one of the biggest issues in the country. Lakhs of students and their parents are crying. We don't know the credibility of existing rank list. The medical sector is very crucial for the existence of humanity. The quality of the

system should be protected. We should remember the Vyapam corruption and its culprits. In this year, the UGC-NET exam was cancelled affecting 9,08,580 aspirants. This Government destroyed the federal character of examination system. They tried to ruin the diversity of the nation. That is why; they have started an agency called the 'NTA' for UG to PG exams and covering the entire higher education system. This Government is ruining the examination system and protecting the culprits of corruption and malpractices. If we look at the earlier incidents, in 2022, there was paper leak of JEE exam affecting 9,39,080 aspirants. In 2021, the paper leak of UGC-NET exam affected 12,67,000 aspirants. In 2021, paper leak of NEET exam affected 13,66,000 aspirants. In 2022 NEET cheating scam, 17,64,570 aspirants were affected. The system and the agency running it itself is corrupt. So, the Union Government should dissolve the NTA and should authorise the State Governments and the Universities to conduct the examinations, which is the duty of the State Governments and the Universities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

DR. V. SIVADASAN: The Government proved that communalism is moral, political, social and economic corruption. People will unite and defeat the corrupt Government. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (WEST BENGAL): #"The language that gave "Vande Mataram" to our great country, the language that gave India its national anthem "Jana Gana Mana", it is unfortunate that today we have to wait for an interpreter for that concerned language. No matter how much we try to project Hindi as superior, it can never match the standards of the Bengali language. This is the language that fetched us the Nobel Prize.* Hon. Chairman Sir, you are an expert in law, I do not need to explain to you that the State and the Government are not the same. Had the hon. President talked about the country, it would have been a different discourse. How do the common people of India truly sustain themselves

#English translation of the original speech delivered in Bengali.

*Expunged as ordered by the Chair

these days? They are struggling for their daily livelihood. Our Chairman Sir surely doesn't have to go to the market; so he might not be able to comprehend the plight that inflating prices of daily commodities have brought to people. Today the impoverished are at the brink of starvation. What is the state of our education system? Many have discussed this already. Today there is a systemic dismantling of our education system so that the sector can be heavily privatized. The marginalized will be robbed of education. The marginalized students will not be able to make the transition to higher studies. *Those who don't come from an affluent background and can't pay that amount won't qualify for the NEET exam. It is my misfortune that I have to say as a representative from West Bengal, that our State is plagued by this malady. There has been an attempt to take the privilege of education away from the marginalized. This is a central design, and it doesn't adhere to the constitutional morality of India. There is no place for any Hindu, Muslim or Christian morality. We achieved independence after a long struggle and the finest outcome of this is our Constitution. You know this yourself. The Supreme Court preaches us recurrently about constitutional morality, but we see no signs of it in the way this Government functions. The Supreme Court of India has stated that corruption is a cancer to the society. That slowly destroys every organ of the body. *The Constitution states that we need to reduce the financial discrimination in society, we have to eliminate inequality, we have to reach a state of economic justice and social justice as well. *India has been well respected by the world since ancient times because the country has the fundamentals of characteristic tenacity, transparency, and duty-boundness. Once the poet had said, "Humanity is above all, and there is no truth holier than this". But now there has been a contempt for humans. Instead of eliminating corruption, we are welcoming it. Can you imagine!!! When our Supreme Court stated that electoral bonds are unconstitutional, why didn't our* say that they will return that money? What is unconstitutional is illegal from its very inception. I have not commented on those transactions, but they have surely received the illegal money- and I am speaking of that fundamental reality. Look at this Corruption! Who is giving this money? The people who have exploited the Indian populace for profit. If the Government is being nurtured by that fund, can that Government actually think of the betterment of the Indian populace? Recently, a harsh reality has come to our notice that most of the cabinet members are multimillionaires. How can these multimillionaires think of the welfare of millions of oppressed citizens? Thus this Government is not fit to achieve the cherished goal of our constitution. This education scam is not a first time phenomenon, it has been happening recurrently. What measures have been taken? Who is going to take the responsibility? How do they

plan to ensure that education will reach each & everyone and there will be no such corruption? Money will play no role in education. They boast of Gujarat being the model State. But now it is evident that it is the new centerpiece of corruption in the country. Will we accept this? For the sake of our country, we expect our Prime Minister* He is claiming to have the majority, I don't want to ridicule this claim, because his voice has now been softened. He is dependent on two crutches, both of which might get imbalanced at any point in time. What will they do then? Can't I request you again to bring forth the topic of constitutional morality? Sir, this is my last request to you. If you deem any word, I said, as unconstitutional, you can expunge it, but whatever we said, do keep this in the record- make a note of what you excluded as well, so that in future when the next generation attempts academic research on this, they will get to know that what the Rajya Sabha members had spoken and what has been expunged by you. How justified were those decisions should be left to history. With these words, I conclude my speech and I thank you.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Samirul Islam. Your time is 15 minutes. It is his maiden speech.

SHRI SAMIRUL ISLAM (West Bengal): Respected Chairman, Sir, thank you for the opportunity given to me to speak on President's Address. In her Address on 27th June, hon. President Madam referred to complete transparency and probity in all Union Government recruitments. Everyone in this august House is now familiar with how the premier entrance examination, NEET (UG), which facilitates students' admission to the medical colleges, has been compromised. I understand that my colleague from the ruling BJP will attempt to deflect the same under the guise of the so-called CBI investigation and recent removal of NTA Chairman. They need to acknowledge that under this Union Government the credit card has overshadowed the report card of students. Not only NEET, Sir, but similar scams have also unfolded in other premier entrance examinations, like UGC NET, which ensures that our education system gets good quality teachers and excellent researchers.

I have two crucial points to present before you. The first one is, those involved in the scam and malpractice in this premier exam, have not only accepted money but also undermined the future of lakhs of deserving students who were deprived of their rightful opportunity despite their competence. Sir, how will the Union Government compensate these unfortunate individuals who have been dreaming for years of

* Expunged as ordered by the Chair.

becoming doctors and ensure that they do not leave the country to pursue their dreams? My second point is that irregularities exposed this year do not suggest that they were unprecedented. It raises a serious question on similar practices that might have occurred in previous examinations as well. Therefore, I urge you to establish a joint parliamentary committee to investigate whether the earlier examinations conducted by the NTA were fair. If it is found that there were irregularities, then, the Government has compromised the lives of the ordinary people as the unqualified students, who might have gained admission to the medical colleges, are likely to become sub-standard doctors.

Sir, now I want to raise another two major issues in front of you in my mother tongue which is Bengali. *"Hon'ble Chairman Sir, Hon'ble President Ma'am in her speech has praised the Indian Government's role in uplifting the traditions & heritage of the Bhagwan Birsa Munda. Regarding this, I want to point out that not only in West Bengal but crores of Adivasis in India worship nature. It is Saari & Sarna religion to them. It is the main religion of Santhalis, Bhumij, Munda, Lodha, Savar, Vibhor, and Oraon. Especially in West Bengal, lakhs of Adivasis from many districts of North and South Bengal have traditionally practiced these two religions. At the same time, many people who belong to the Kurmi tribe also practice these religions. But unfortunately, the Indian Government has yet to officially acknowledge Saari and Sarna as religion. Despite having a thousand years of history associated with them, the Indian Government is not acknowledging this. On 17th February 2023, the hon. Chief Minister of West Bengal, Madam Mamata Banerjee led the West Bengal Government to pass a resolution in the Assembly to acknowledge Saari and Sarna as religions. This resolution has been forwarded to the Indian Government on 27th February, 2023. But unfortunately, the Indian Government hasn't taken any steps regarding this. According to the Indian Constitution, it is a fundamental right of every citizen to practice their faith and religion. Yet this Indian Government is depriving crores of Adivasis who practice Saari and Sarna religion. A survey needs to be conducted to acknowledge this religion and to identify the practitioners of this religion. Yet the Indian Government has taken no measures towards this. It is unfortunate that even after having a clear resolution from the West Bengal Government, the Indian Government has been unable to take any real steps to recommend Saari and Sarna as a separate religious code. Pandit Raghunath Murmu has spoken in Santhali: "You have your alphabet; you have your language. You have your religion- your hope of life. If your alphabet is lost, your language will be lost. If your religion is lost, then the

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

hope of life will be lost". I again demand the Indian Government to immediately acknowledge the Saari and Sarna religions as separate religious codes. Our hon. Prime Minister Narendra Modi always mentions "Sabka Saath, Sabka Bikash, Sabka Viswas" in his speeches. However, during the tenure of this Government of India, repeated incidents of injustice and religious persecution have been taking place against the Scheduled Castes, Schedule Tribes and aborigines. Every one of us should remember the words of Rabindranath that "whoever you put down will put you down. The one you put back will drag you back as well". All hail the Johar, All hail the aborigines, All hail the Constitution.

Sir, hon. President Madam in her speech said that the Government of India is continuously working to empower the poor, the youth, the women and the farmers of the country. But the question is that is West Bengal out of the country where millions of poor, youth, women and farmers of Bengal are being deprived of the light by the Central Government? Since the defeat of the Bharatiya Janata Party in Bengal in the Assembly Elections in 2021, the Government of India has not given the money owed to the Government of West Bengal over one and a half lacs. As a result, it is depriving Bengal, the women of Bengal, and the farmers of Bengal. Let alone any financial cooperation, the Government of India is instead adopting non-cooperation to break the financial backbone of the people of Bengal. The Indian Government is depriving lacs of poor working-class people of Bengal of their hard-earned money and thus bulldozing the federal structure. Since 2021, thousands of crores of 100 days of MGNREGA work projects have not yet been paid by the Government of India. We, the Trinamool MPs and MLAs sat down in Delhi protesting and demanding payment of the amount they owed. The Minister of Agriculture didn't give us an appointment. The Minister of State wanted to evade meeting us and thus they kept us waiting outside the house. In return, we were lathi-charged by the Police, even the women MPs were not spared from such treatment. We have protested from Delhi to Kolkata. The Governor promised that the due amount would be paid by the Government of India to the State Government. But we still haven't received that money. Our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee met the Prime Minister regarding this issue but the people of Bengal have not received that money yet. Especially since Corona, for many, this 100 days' work was their only hope of earning. The Indian Government has not shown even a simple act of humanity to the West Bengal Government. They kept on procrastinating. An idea has been created why you did not vote for BJP; the people of Bengal will now have to pay for it. This is the Central Government's attitude towards Bengal. But the humanitarian Chief Minister of Bengal, Ms. Mamata Banerjee did not rely on the Indian Government and kept her word by delivering these crores of wages

for 100 days of work from the State treasury to almost everyone's account. Not only that, the State is launching the "Karmasree project" with a guarantee of 50 days of work without relying on the Government of India. Deprivation of Bengal does not end here. Housing scheme money has been stopped. Rural road project money has been stopped. National Health Mission money has been withheld. Funds of the Sarva Shiksha Mission have been withheld. Funds for food security schemes meant to empower poor people have been withheld. Even after the cyclone hit in state, no compensation was provided from the Government of India funds. Our Central Government is graciously distributing funds to the states run by the BJP government. Only the hardworking poor of Bengal are being deprived. West Bengal has been widely acknowledged both inside and outside of India as a pioneer of women's empowerment. The "Kanyashree scheme" has won the title of best in the state in advancing women's education. Bengal is now a model state and yet how long can the Government of India deprive us? Sir, I ask the Central Government, at a time when you are preaching the idea regarding the grand celebration of the Amritkaal, why are the people of Bengal who were at the forefront of the Independence struggle being deprived? This is the holy land of Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay, Kazi Nazrul Islam, and Netaji Subhash Chandra Bose. There were numerous martyrs like Khudiram, Binay Badal Dinesh, and Matangini Hazra who sacrificed their lives for the nation, yet Bengal was deprived during these days of Amritkaal. Prime Minister Narendra Modi displays his love for Bengal only before the elections. Thus, just before the elections, he impersonates Rabindranath or Swami Vivekananda. The abundance of love! This time, right before the elections, he stated that he has so much love for Bengal that he wants rebirth in West Bengal in his next life. If he truly loves Bengal, why is he depriving the hard-working poor populace of Bengal? Why is he depriving them of their right? We demand his answer. Gokhale, had said, "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow". Even after 77 years of Independence, the Government should not neglect Bengal. The Government of India has made a conspiracy to starve the people of Bengal similar to how the Britishers conspired to starve the people of Bengal pre-independence. I demand they stop having this attitude towards Bengal. I would conclude by demanding they immediately release the rightful fund that they owe us.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I rise to participate, support and put forth my views on the President's Address delivered on 27th June, 2024 on behalf of A.I.A.D.M.K. Party and my leader, General Secretary, Edappadi K. Palaniswami.

While recognising the historic third term of the hon. Prime Minister, hon. President, in her Address, highlighted the achievements and good governance undertaken during the last ten years and outlined the policy priorities of the Government to make India a developed nation by 2047. The Address intends to set the tone for the Parliament Session including reference to several critical issues and achievements. The hon. President stated that in ten years, India has risen to become the fifth largest economy from the eleventh and striving to become the third largest economy. While taking care of the economy, the Government should although address the huge level of unemployment in the country. This has to be tackled immediately. Unrest among the youth is increasing. Their unrest is due to unemployment and they are being diverted to drugs and other illegal means in order to survive. The Government has to seriously ponder on this issue. Whichever Government comes, they concentrate on giving the welfare programmes for the people. The ruling is not only for the protection of the citizens of the country but to see that they have to give welfare programmes to them. For example, if you take the Asoka period, we can see in front of us the Asoka Chakra. On the Parliament Building, Asoka's symbol of lions is kept. The objective says that for the first time in Hindu culture area, there appeared the idea of welfare State of the general good, the promotion of which Asoka regarded as the duty of the king. The welfare programmes in India started many times, especially, during Asoka period, which you are claiming and the symbol, we are still following. This book tells about his period. This is written by Max Weber. It says in that book, "During his period, hospitals for men and animals, as required for that, should be established. Fruits and shade trees should be planted on the streets. Rest houses also should be set up for the men and animals." These are the things which started from our period, the welfare programmes. Also, Sir, our Dravidian movement... ...*(Time bell rings.)*... Sir, my party has 27 minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपके पास 3.33 मिनट का समय है, चार मिनट हो चुके हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: No, Sir. The allotment of time was 27 minutes for me. Twenty-seven minutes was given for AIADMK Party.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपके लिए 3.33 मिनट का समय है।

DR. M. THAMBIDURAI: You are telling me wrongly. Twenty-seven minutes was given and I have noted it. That is why, I started to speak. You are suddenly stopping me. There is no point.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बोलिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, twenty-seven minutes was allotted for my party. Sir, verify it.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप सीनियर मेम्बर हैं, आप बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: That is why, if you are simply stopping me, then, there is no point in it. We are having four Members and are given twenty-seven minutes. I have noted that. Therefore, sufficient time has to be given; otherwise, there is no point of this.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : यह 'Others' के लिए है, आपके नाम के आगे...

DR. M. THAMBIDURAI: No; Sir. I have seen that out of the 21 hours that was allotted for discussion, the AIADMK Party was allotted 27 minutes. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप बोलिए, आप 1-2 मिनट और बोल लीजिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Otherwise, I don't want to speak.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप 2 मिनट और बोल लीजिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, otherwise, I don't want to speak, if you say like this. It is because there are some important issues, and we are a four Member party. It is already mentioned. The list is there. It has been told to me that 27 minutes have been allotted. Sir, if you tell me to speak in two minutes, what can I speak?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप 2 मिनट में जितना बोल सकते हैं, उतना बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am completing. I am coming to the point. There are so many issues that I want to highlight. You just find out the allotted time. Otherwise, I will have to very brief because they told me that I have 27 minutes. ...*(Interruptions)*... No; they have shown.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, tell me as to how much time I have.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): जितने 'Others' हैं, उन सबको 3-3 मिनट का समय दिया गया है। आपके पास भी 3.33 मिनट का समय है, आपके लिए भी उतना ही समय है, आप समय बरबाद न करें।

DR. M. THAMBIDURAI: Then, Sir, please allow me to speak for five minutes, at least. The important issue that I want to highlight, first of all, is the State rights of Tamil Nadu, especially, the Sri Lankan issue, and that the Tamil Nadu fishermen are not protected properly by this Government. Regarding the Cauvery issue, we are not against giving Cauvery drinking water to the Bengaluru city people. But, at the same time, they can take the 18 TMC water. It is given by Krishnaraja Sagar Dam. We are not against it. Therefore, this is the basic point. Regarding the NEET examination, when has it come? ...*(Interruptions)*... Walk-out is different. Sir, NEET exam was introduced on 27th December, 2010. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया बैठिए। Please sit down. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: The Medical Council of India announced the NEET examination at that time. ...*(Interruptions)*... I am giving the authentic information, it is on record. ...*(Interruptions)*... At that time, the Ruling Party was the Congress and the DMK was part of the Government. ...*(Interruptions)*... They were responsible for introducing this kind of NEET exam. ...*(Interruptions)*...

The VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, we are also against the NEET examination. ...*(Interruptions)*... Walk out is different, but I have to tell the facts. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। ...(**समय की घंटी**)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, regarding Kallakurichi, for example, illicit liquor... ...*(Interruptions)*...

SHRI N.R ELANGO: Sir, it is a State issue.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, *Dalit* people. ...*(Interruptions)*... *Dalit* people. ...*(Interruptions)*...

The VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... कृपया बैठिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, sixty *Dalit* people have died. *Dalit* people have died because of that. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। Now, Shri Ryaga Krishnaiah. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: That shows the inefficiency of the DMK Government. ...*(Interruptions)*... Sir, serious action has to be taken in this matter. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): तंबी जी, आपका भाषण समाप्त हुआ। कृपया आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्य, आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है। Now Shri Ryaga Krishnaiah. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... तंबी जी का भाषण अंकित नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए। वे देख लेंगे, आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... तंबी जी, आपका भाषण खत्म हो गया है। Shri Ryaga Krishnaiah; not present. Shrimati Priyanka Chaturvedi; not present. Shrimati Ranjeet Ranjan; not present. Shri R. Girirajan. You have eight minutes.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): *"Hon. Vice Chairman Sir, I would like to begin my speech with a poem in Tamil:

"Both our life and our riches
Are like our never fading Tamil ,
Blow this aloud, O Conch-Shell;
Vanished are our foes somewhere"

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

In this election, our foes had disappeared somewhere. INDIA alliance is united. Four hundred plus! People who thumped their chest that they would win more than four hundred seats, are now sidelined to corners."

You can replace the statues. This Government, this administration replaced the statue of *Annal* Ambedkar, who is the author of the Constitution. But one day, it will be back there. But you cannot replace the Constitution.

*"What did you say before coming to power? If you win 400 seats, you will change the Constitution. But now, you are in a pitiable situation. Yesterday, our leader Mr. Tiruchi Siva had said that you would not be happy even though you had won the election. Even though we are in the losing side, we will raise people's issues in this House, not only for five years, but also continuously. This is Rahul's era. But for BJP, it is Rahu Kaal."

Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on President's Address. I express my gratitude and indebtedness to my beloved party leader and the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Thalapathy* M.K. Stalin and our upcoming leader Udhayanidhi Stalin for giving me an opportunity to speak in this august House.

I would like to record in this august House what really matters and what really is missing in the hon. President's Address. The hon. President has failed to mention the failures of this Government on crucial fronts. Several important issues and problems are missing obviously from her speech.

Sir, the President's Address fails to mention what is happening in Manipur State, whether any appropriate action being taken by the Government to stop the ethnic violence in Manipur and to restore peace and normalcy in Manipur State in the country. We demand a concrete answer from hon. Prime Minister who is keeping himself away from Manipur and never want to speak anything on this burning issue. It is unfortunate that the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi did not visit Manipur and take any action on it. In Tamil Nadu, our beloved Dr. Kalaignar, M. Karunanidhi has announced free electricity for the farmers in the year 1989 to save the farmers' lives. Now, what is happening? Sir, it is very unfortunate that the incidence of death by suicide by farmers and farm workers is on the rise. More than one lakh farmers have committed suicide in the last ten years. According to the National Crime Records Bureau, 30 farmers die every day. The free electricity connection given by our *Thalaivar* Dr. Kalaignar, still continues in Tamil Nadu. The Union Government should follow the footsteps of Tamil Nadu. The Union Government should waive all

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

farmers' loans from all banks including cooperative banks and MSP should be implemented.

Sir, regarding the NEET issue, this Government has not come forward for discussion in this House. Lakhs and lakhs of NEET aspirant students suffered due to the paper leakage. Sir, NEET examination is unwarranted. It is our party's decision. Because of that only, from the beginning itself, we are opposing NEET examination, abolish the NEET examination. In Tamil Nadu, around 17 students have committed suicide. Two Bills were unanimously passed in the Tamil Nadu Assembly and sent for the assent of hon. President. And, recently, two days ago, one more Bill was unanimously passed in Tamil Nadu Assembly to abolish the NEET examination and has been sent for the President's assent. But, still this Government is not hearing the voice of the Tamil Nadu.

Sir, the overall unemployment rate in India as of now has gone beyond 10 per cent. In the beginning of 2024, the unemployment rate was 5.4 per cent; as of now, it is 10.03 per cent. This Government has promised 2 crore jobs every year. But, they have so far not fulfilled the promises. Adding fuel to the issue, the Union Government has not filled several lakh vacancies in the last 10 years. This is an ample proof for the precarious condition this Government is in. Sir, in the last ten years of this Government, the crime against the SC/STs has been increased. As per the report of the National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, more than 5 lakh atrocity cases have been registered in the last 10 years. I request you, Sir, the attack and atrocities against SC/ST and oppressed community should be curtailed. In the last ten years, more than 8,000 students belonging to the SC/ST/OBC and minority communities have dropped from IITs, IIMs, IIITs, IISERs and 50 students died by suicide inside the campuses across the country. I urge the Government to take necessary steps to curtail the dropout of SC/ST/OBC students from the premier institutions and conduct appropriate counseling to students from poor and deprived communities to combat the peer pressures to stop suicides in the higher institutions in this country.

Sir, there is a bias and injustice shown by the Union Government to Tamil Nadu in the devolution of funds. The hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman says that she followed the recommendations of the Finance Commission. What is the Finance Commission? The Finance Commission is appointed by the Government. We are asking the Central Government for our share, our rights. They are not sanctioning our demands. Sir, the Government has initiated the 16th Finance Commission and its Chairman and members are to be elected. The Finance Commission is appointed by the President under Article 280 of the Constitution. My

humble request to the Government is to increase the devolution of funds from the divisible pool of Central funds from the present 43 per cent to 50 per cent. Sir, Tamil Nadu is the most betrayed State in the country. The Union Government has denied the Tamil Nadu its rightful share and I can mention many such projects where the Union Government's lethargic and lackadaisical approach has robbed the people of Tamil Nadu, what they deserve. For example, Sir, in 2015, the Government announced the AIIMS projects. In 2018, the site was identified. In 2020, the land was handed over by the Government. In the past ten years, they have not put a single stone there for basement. This is the way the Union Government is ruined by the ruling dispensation. Sir, our hon. Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin has requested the Prime Minister, Shri Narendra Modi to declare floods as a "calamity of severe nature" and allot the required amount of funds for carrying out relief and rehabilitation works in the affected Districts. But, still the funds requested by the State Government are not being allotted. ...(*Time-bell rings*)... Sir, I am coming to the conclusion.

Sir, I would like to speak about one important issue. The Government says that it is bringing out the nation from the clutches of the colonial rule. But, the very same Government is thinking of allowing foreign lawyers to practice in India. Actually, the last ten years of Modi rule has taken us back to the Colonial rule.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया समाप्त कीजिए।

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, this is height of * cannot stay at the top of power for a long time. Sir, I will just conclude. I would like to record in this august House that our Dravidian model legacy will continue to flourish Tamil Nadu and India through our youth leaders spearheaded by the Rising Sun and Youth icon of Tamil Nadu, Shri Udayanidhi Stalin. Thank you, Sir.

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष जी, जय जगन्नाथ।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, मैं जगन्नाथ धाम ओडिशा की पावन भूमि से आती हूं, जहाँ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी हैं। हम दोनों एक ही मयूरभंज जिले से संबंधित हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारा गर्व और गौरव हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत पुण्य था, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की सेवा और स्थिति के बारे में बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं। महोदय, मै क्षमा चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी की टिप्पणी और वास्तविकता पूरी तरह से अलग है।

* Expunged as ordered by the Chair.

महामहिम जी के हिसाब से देश में रिफॉर्म आया है। उन्होंने बोला है कि देश में रिफॉर्म आया है, लेकिन महोदय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता है, अमरीका में हमारी पावन भूमि की प्रशंसा करने से रिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि रिफॉर्म तब होगा, जब हमारे देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सेवा क्षेत्र में सुधार आयेगा, जब महिला स्वावलंबी होकर सुरक्षित रहेगी, जब हर गाँव को सड़क, पानी, बिजली की सुविधा मिलेगी।

महोदय, महिला को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार महिला आरक्षण देने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' लाई थी। यह बहुत खुशी की बात है और मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। महोदय, तत्कालीन बीजेडी सरकार के हमारे पूर्व मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने जब पहली बार समर्थन दिया था, तब वे महिला के हक के लिए बने पहले बिल पर बोले थे। महोदय, महिला संरक्षण बिल कार्यकारी होना चाहिए। मेरे ओडिशा राज्य में पिछला इलेक्शन हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा और विधान सभा चुनाव के पिछले इलेक्शन में 30 परसेंट महिलाओं को टिकट नहीं दिया है। अभी नये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लेकिन ओडिशा सरकार में एक ही महिला मंत्री को पद मिला है। महोदय, ऐसे में बीजेपी द्वारा महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? *

महोदय, 2024 के इलेक्शन में मेरे राज्य ओडिशा में जब पहले बीजू जनता दल की सरकार थी, तब बीजेडी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय ने अपनी सरकार में गर्भवती महिला से लेकर हर एक के लिए लोक हित योजना प्रस्तुत की थी। विशेषकर, महिलाओं के विकास और उन्हें समाज का स्वतंत्र परिचय देने के लिए योजना बनी थी, लेकिन आज ओडिशा में सत्ता पाई हुई सरकार इस लोकहित योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। महोदय, सरकार तो आएगी-जाएगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन लोगों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए। महोदय, हम इस विकसित भारत के नागरिक हैं। मेरा जिला इस भारत से बाहर नहीं है। मेरे जिले और गाँव के विकसित हुए बिना विकसित भारत का गठन कैसे होगा? महामहिम राष्ट्रपति महोदया के जिले में 4 सब-डिवीजंस हैं। इन 4 सब-डिवीजंस में आज तक रेल सेवा नहीं पहुंच पाई है। मयूरभंज जिला रेल सेवा से वंचित है। मयूरभंज जिले के बंग्रिपोसी-गोरुमहिसानी, बादामपहाड़-क्योंझर, बुडामारा-चाकुलिया रेल लाइन प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकार में है और राष्ट्रपति जी बुलेट ट्रेन के बारे में बोल रही हैं। बजट में प्रति वर्ष 100 से लेकर 1,000 रुपये मिलते हैं। आज भी मयूरभंजवासी रेल सेवा से वंचित हैं। क्या इस अंचल के लोग दुनिया से बाहर हैं? क्या कभी ये लोग रेल सेवा नहीं पाएंगे?

महोदय, राष्ट्रीय राजपथ के बारे में बोलूँ, तो क्या बोलूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के जिले राइरंगपुर, जहाँ पर उनका खुद का घर है और करंजिया सब-डिवीज़न के लोग जिला मुख्यालय बारीपदा जाने के लिए एनएच49 पर निर्भर करते हैं। इस रास्ते की देख-रेख करते हैं। यहाँ एक Duarsuni घाटी आती है, जिसमें रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। महीने में 20 एक्सीडेंट्स जरूर होते हैं और पाँच-दस लोगों की जान जाती है। अभी तक उस रास्ते की मरम्मत नहीं हुई है। एनएच49 में झारपोखरीया (बॉम्बे चाक) आता है। उसे पाँच-छः साल हो गए हैं, लेकिन वह ओवरब्रिज अभी

* Expunged as ordered by the Chair.

तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसे आधे पर ही छोड़ दिया है। वहाँ पर रोज ट्रक आता है और गिर जाता है। अभी तक पाँच-छः साल हो गए हैं, लेकिन वह कंपलीट नहीं हुआ है।

महोदय, मैं एक और विषय मेरे खुद के ब्लॉक के संबंध में उठाना चाहती हूँ। उस ब्लॉक में ओवरब्रिज बनाने की डिमांड कई सालों से है, लेकिन जो हमारे पूर्ववर्ती केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, श्री बिश्वेश्वर टुडू जी थे, वे बार-बार भूमि पूजन करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी ईंट नहीं लगी है। सर, मैं एयरपोर्ट की बात बोलती हूँ। हमारे रसगोविंदपुर, मयूरभंज, जिसे अमरदा बोलते हैं और दांडबोस, राइरंगपुर में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बार-बार बोल रहे हैं कि हुआ है, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। मैं नेटवर्क के बारे में बोलती हूँ। मेरा जिला आदिवासी ट्राइबल जिला है। उस जिले में ऐसे बहुत सारे गाँव है। वह जिला मेरा भी है और महामहिम राष्ट्रपति जी का भी है, लेकिन 26 ब्लॉक में से 15 से 20 ब्लॉक्स में अभी तक नेटवर्क नहीं है। ऐसे में, सबका साथ, सबका विकास में कैसे शामिल होंगे? चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, सब कामों के लिए नेटवर्क जरूर होना चाहिए। ओडिशा के उत्तर भाग में मयूरभंज जिला आदिवासी संप्रदाय का क्षेत्र है। ...(**समय की घंटी**)... इस इलाके में स्वास्थ्य सेवा अपाहिज है। मेरे पास दस मिनट हैं। तत्कालीन नवीन पटनायक सरकार ने बारीपादा, मयूरभंज जिले में पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है।

3.00 **P.M.**

इस इलाके में केंद्र सरकार को एम्स की एक शाखा की स्थापना के लिए कदम उठाना चाहिए। ऐसा होने से केवल ओडिशा राज्य ही नहीं, बल्कि पश्चिमी बंगाल, झारखंड के लोग भी सुविधा पाएंगे। आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): अब आप समाप्त करें।

श्रीमती ममता मोहंता: सर, मेरे पास 10 मिनट का समय है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): ठीक है। आप एक मिनट और बोल लीजिए।

श्रीमती ममता मोहंता: महामहिम राष्ट्रपति जी ने आदिवासियों के बारे में बोला। यह उनके लिए था जो आदिवासी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन और भी कुछ जाति-समाज है, जो आदिवासी जैसे जीवन यापन करते हैं। वे दरिद्रता की सीमा रेखा में हैं और आदिवासी जाति में शामिल होने के लिए लड़ते हैं। वे उनका अधिकार पाने के लिए वंचित हैं, जैसे कि कुर्मी समाज, कुर्मी जाति है। स्वाधीनता के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे अपने हक पाने के लिए लड़ रहे हैं। जब इलेक्शन था, तब बहुत सारे नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्य मंत्री गए थे। ओडिशा में 25 लाख कुर्मी समाज, कुर्मी जाति के लोग रहते हैं। मैंने बार-बार कुर्मी समाज के लिए उपस्थापन किया था और हमारे पूर्व आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उनका एक आन्सर था कि राज्य ने रिकमंडेशन नहीं किया। अभी तो इलेक्शन में सरकार भी गठित हो गई है। बीजेपी सरकार राज्य में भी आ गई है और

केंद्र में भी है। ...(**समय की घंटी**)... अभी रिकमंडेशन करके कुर्मी जाति को हक दे दें, उनको उनका अधिकार दे दें और एसटी में उनको शामिल करना चाहिए। उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप विराजिए।

श्रीमती ममता मोहंता: सर, एक मिनट...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): अब आप बैठिए।

श्रीमती ममता मोहंता: महोदय, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती ममता मोहंता: इसलिए आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया, अब आप बैठिए।

श्रीमती ममता मोहंता: सर, थोड़ा समय ...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री संजय राउत।

श्रीमती ममता मोहंता: सर, एक मिनट ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री संजय राउत, आपका समय तीन मिनट है।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, जो नई लोक सभा गठित हुई है और नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद हमने महामहिम राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण सुना। राष्ट्रपति जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला हैं। संवैधानिक पद की जो मर्यादा होती है, उनका पालन वहां से शुरू होता है और हम उनका आदर करते हैं। इस बार हमने यह पहली बार देखा कि जब मोदी जी

ने राष्ट्रपति भवन जाकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो सभी अखबारों में एक फोटो छपी, †

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यों के बारे में सदन में चर्चा नहीं करें।

श्री संजय राउत: मैं टीका नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह नहीं करें।

श्री संजय राउत: †

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया, यह अंकित नहीं होगा।

श्री संजय राउत: लेकिन लोकतंत्र के लिए यह चित्र विचलित करने वाला है। राष्ट्रपति जी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, वे किसी पार्टी के नहीं होते, वे पूरे देश के होते हैं। राष्ट्रपति जी बीजेपी की हैं, राष्ट्रपति जी कांग्रेस पार्टी की हैं, शिव सेना की हैं, हम सबकी हैं। मुझे लगता है कि †

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा नहीं करें। यह अंकित नहीं होगा।

श्री संजय राउत: राष्ट्रपति जी देश के संविधान की संरक्षक हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, वह हम सबने सुना।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): हाँ, उस पर बोलिए।

श्री संजय राउत : उसमें हर पन्ने पर * है। हर पन्ने पर * है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय राउत साहब, वैसे ...

श्री संजय राउत: राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहती हैं कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है ...(**व्यवधान**)... और गठबंधन की सरकार 6 दशक के बाद बनी है। ...(**व्यवधान**)... यह गलत है। ...(**व्यवधान**)... मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। ...(**व्यवधान**)...

---

†Not recorded .

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय राउत: मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय राउत: मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त किया है। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय राउत: मोदी जी कांग्रेस मुक्त संसद और भारत की भाषा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बहुमत मुक्त किया है। ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री संजय राउत: अभी मैंने शुरू ही नहीं किया...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपके पास 3 मिनट का समय था, लेकिन आपको 4 मिनट मिल गए।

श्री संजय राउत: मैंने शुरू ही नहीं किया, धन्यवाद क्या है? इसीलिए तो हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। ...(**व्यवधान**)... आपने 400 पार का नारा दिया, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): ये सीनियर मेम्बर हैं, तो गागर में सागर भर सकते हैं।

श्री संजय राउत: आप 240 पर अटक गए। * ...(**व्यवधान**)... आपको बहुमत नहीं मिला है। ...(**व्यवधान**)... उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, बिहार में ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री संजय राउत: 50 सीटें ऐसी हैं, जिनको आप बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं। ...(**व्यवधान**)... अब मामला कोर्ट में जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): आपका समय समाप्त हुआ। श्री मदन राठौड़। ...(**व्यवधान**)... आपका भाषण समाप्त हुआ, माननीय संजय राउत जी, कृपया विराज जाएँ। ...(**व्यवधान**)... आप कृपया बैठिए। आपका समय समाप्त हुआ। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): कृपया बैठिए।

श्री मदन राठौड़: उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी पश्चिमी बंगाल के बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला, सबसे खराब स्थिति पश्चिमी बंगाल की है। वहाँ पर कानून का राज नहीं है, वहाँ पर शरिया कानून चल रहा है। ...(**व्यवधान**)... पश्चिमी बंगाल में शरिया कानून चल रहा है। ...(**व्यवधान**)... अभी मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। कल टीवी चैनल पर एक जेसीबी नाम का व्यक्ति, जो जेल से छूट कर आया, वह शरिया कानून चला रहा था, महिलाओं की पिटाई कर रहा था। पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार की स्थिति है! ...(**व्यवधान**)... पश्चिमी बंगाल से घटिया कोई यदि शासन व्यवस्था है, तो यह दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पश्चिमी बंगाल में संघीय ढाँचे को तोड़ने का षडयंत्र चल रहा है। वहाँ पर बंगलादेशी घुसपैठिए आ गए। ...(**व्यवधान**)... घुसपैठियों ने वहाँ आकर वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया। वे वहाँ उनका वोट लेकर सत्ता चला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

[**उपसभाध्यक्ष** (**डा. फौजिया खान**) *पीठासीन हुईं*]

एआईटीसी वहाँ पर इनको संरक्षण दे रही है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**डा. फौजिया खान**): ऑनरेबल मेम्बर्स, प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मदन राठौड़: हाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आज केरल की बात करें, केरल में भी लोगों को मारा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं पश्चिमी बंगाल गया था। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बीरभूम जिले में गया था, मैं वहाँ पर डेढ़ महीने रहा हूँ। डेढ़ महीने में मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर अधिकारी टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। ...(**व्यवधान**)... वहाँ पर इस प्रकार का सेलेक्शन होता है। ...(**व्यवधान**)... वहाँ टीएमसी का जिला अध्यक्ष ...(**व्यवधान**)... टीएमसी का जिला अध्यक्ष कलक्टर के साथ बैठ कर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सेलेक्ट करता है और उनसे कहता है कि आप वसूली करो, आधा पैसा टीएमसी में जमा कराओ, आधे पैसे में अपना घर चलाओ। ...(**व्यवधान**)... वहाँ पर यह स्थिति है। ...(**व्यवधान**)... यही बात नहीं है, सीपीआई और सीपीएम के जो कुछ भी लोग थे, वे सारे टीएमसी में जमा हो गए और मोहल्ले से वसूली कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह स्थिति बहुत खराब स्थिति है। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि

वहाँ पर बम चलाना सामान्य बात हो गई है। ...(**व्यवधान**)... आम बात है। ...(**व्यवधान**)... बम फोड़े जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... घरों में बम फोड़े जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह वहाँ की स्थिति है। ...(**व्यवधान**)... इससे ज्यादा खराब स्थिति और क्या हो सकती है! ...(**व्यवधान**)... मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप मेजें थपथपा रहे हैं, कल आपका नम्बर आएगा। वहाँ पर बंगलादेशी घुसपैठिए आए हैं, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ...(**व्यवधान**)... आप आँख मूँद कर बैठे हैं, कितने दिन बैठे रहेंगे? **...(व्यवधान)...** थोड़ा विचार कीजिए। **...(व्यवधान)...** यह जो स्थिति है, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। **...(व्यवधान)...** आपकी भी वही स्थिति बनेगी जो आज वहाँ सामान्य व्यक्ति की बन रही है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भी कानून-व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। **...(व्यवधान)...** आश्चर्य की बात तो तब होती है कि वहाँ पर जितने राज्यपाल गए, किसी भी राज्यपाल से उनकी पटरी नहीं बैठी। ...(**व्यवधान**)... हर राज्यपाल के साथ वे इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। **...(व्यवधान)...** मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): ऑनरेबल मेम्बर, **...(व्यवधान)...** आपस में बात मत कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री मदन राठौड़: आप यह एक बात समझिए। **...(व्यवधान)...** यह क्या बात हो गई? **...(व्यवधान)...** इस प्रकार की कानून-व्यवस्था **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. FAUZIA KHAN): Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री मदन राठौड़: क्या वे संघीय ढाँचा को तोड़ना चाहते हैं? **...(व्यवधान)...** क्या वे हमारी संघीय व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं? **...(व्यवधान)...** यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रमोद तिवारी: महोदया, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Hon. Member, there is a point of order.

श्री प्रमोद तिवारी: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि किसी राज्य के राज्यपाल के विषय में यहाँ उल्लेख नहीं हो सकता है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): यह कौन से रूल के तहत है? **...(व्यवधान)...**

श्री प्रमोद तिवारी: यह स्टेट का सब्जेक्ट है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आप रूल बताइए। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रमोद तिवारी: महोदया, रूल 238 के तहत मेरा निवेदन है कि यह राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। **...(व्यवधान)...** इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्री मदन राठौड़: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की। **...(व्यवधान)...** मैंने संघीय व्यवस्था की चर्चा की है। इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं कही है।

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आप कंक्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...** आप जल्दी कंक्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...** आपके पास एक मिनट है।

श्री मदन राठौड़: महोदया, मैं अब एक निवेदन करना चाहूँगा। इन्होंने जो इंडिया गठबंधन किया है..

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपके पास बस एक मिनट है। **...(व्यवधान)...**

श्री मदन राठौड़: इन्होंने जो 'इंडिया' गठबंधन बनाया है - एक एक्ट है - Article -1. आर्टिकल 1 में यह है कि राष्ट्र के नाम के समान कोई भी नाम रखना एक असामान्य घटना है। **...(व्यवधान)...** इससे भ्रम और अस्पष्टता पैदा होती है। **...(व्यवधान)...** National Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please speak on the topic.

श्री मदन राठौड़: इस बात पर दिल्ली के हाई कोर्ट में भी इनसे सवाल-जवाब किया गया है और अभी वह विचाराधीन है। **...(व्यवधान)...** यही नहीं, the Legislature formulated the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950, to prevent the improper use of certain Emblems and Names for professional and commercial purposes.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADAN RATHOD: Such Emblems and names are enlisted in the Schedule appended to the Act. ...*(Interruptions)*... मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि can the term I.N.D.I.A. be registered or used as the name of a political alliance? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, यह भानुमति का कुनबा जोड़ा। **...(समय की घंटी)...** यह क्या बात हो गई? ये कैसे ऐसा कर सकते हैं? **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Please conclude. Your time is up. ...*(Interruptions)*...

श्री मदन राठौड़: बात यह है कि to analyze this aspect, let us delve into the laws prohibiting and restricting use of certain names in India.

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपका समय समाप्त हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मदन राठौड़: यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। आपने क्या किया, यह देखिए। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में क्या किया? ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): आपका समय समाप्त हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मदन राठौड़: कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में पेज नम्बर 7 पर यह है कि बहुसंख्यक ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान): श्री दिग्विजय सिंह जी। ...(**व्यवधान**)... श्री दिग्विजय सिंह। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का कुछ कारणों की वजह से समर्थन नहीं कर पा रहा हूँ।

चुनाव आयोग के प्रति आभार, किस बात का आभार? खुद के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आभार, Representation of People's Act का उल्लंघन करने का आभार या कश्मीर के विधान सभा चुनाव नहीं कराने के बारे में आभार?

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

माननीय सभापति महोदय, आप पधारे, बड़ी कृपा की। Mother of democracy, हमारे देश की डेमोक्रेसी को कहा जाता है, लेकिन पूरे तरीके से यदि आप इस लोक सभा चुनाव में चुनाव आयोग का व्यवहार देखेंगे, तो यह पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यता नहीं थी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गैर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के हमारे अपोज़िशन पार्टीज़ ने अप्रैल, 2023 से लेकर आज तक, अनेक बार माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय माँगा और माननीय चुनाव आयोग ने हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिलने का अवसर नहीं दिया। माननीय सभापति जी, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का किस बात का आभार? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज देश में ईवीएम के विषय पर एक भ्रम की स्थिति है।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़। राधा मोहन जी, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, हमने माननीय चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे थे। देश की सिविल सोसाइटीज़ ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में जहाँ सॉफ्टवेयर है, वह कमांड देने वाले का आदेश मानेगा। मशीन सॉफ्टवेयर का आदेश मानता है। हम इन छोटे प्रश्नों के बारे में, ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहते थे। कौन जीता, कौन हारा - इसका प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हम आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रसी को, उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे छोड़ सकते हैं? आज के युग में जहाँ दूरदराज देशों में रहने वाले लोग रिज़र्व बैंक के वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और मिलियन्स ऑफ डॉलर चुरा लेते हैं, वहाँ ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है या नहीं होता है - यह चर्चा का विषय है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि यह मेरा अधिकार है कि मैं जहाँ वोट डालूँ, वहाँ वोट गिरना चाहिए और उसकी गिनती होनी चाहिए। हमें वह सात सेकंड के लिए दिखता है, कहाँ वोट गया, कहाँ छपा, इसकी जानकारी नहीं है। इसका कारण यह है कि बैलट यूनिट का कमांड वीवीपैट में आता है और वीवीपैट का कमांड कंट्रोल यूनिट में जाता है। इस तरह से कंट्रोल यूनिट में कमांड वीवीपैट से जाता है और वीवीपैट में कौन-सा सॉफ्यवेयर डाला गया है, उसके बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है। आप उस सॉफ्टवेयर को उजागर क्यों नहीं करते हैं, क्यों डरते हैं? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है? इस बात को लेकर माननीय चुनाव आयोग की जो मानसिकता है, हम उसका घोर विरोध करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता और उपनेता जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में मूल उद्देश्य सेवा करना नहीं है, बल्कि व्यवसाय करना है और ये लोग अलग-अलग तरीके से व्यवसाय करते हैं। पहले जनसंघ के संबंध में कहा जाता था कि यह व्यवसायियों की पार्टी है, छोटे-मोटे व्यवसायियों की पार्टी है, दुकानदारों की पार्टी है। आज वही पार्टी जीएसटी के बाद दुकानदारों को भी घर बैठा कर बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स की पार्टी बन गई है और वे कॉरपोरेट्स कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह से ये कर सकते हैं - मैं इन सब बातों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला, इन्होंने अपनी विचारधारा को समाज, व्यवसाय, शिक्षा, पब्लिक सर्विस कमिशन, यूपीएससी, एनटीए में किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन किया है - इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के पद पर अपात्र लोगों की नियुक्ति की गई। उन्होंने कई नेशनल इंस्टिट्यूट्स में वाइस चांसलर्स की जो नियुक्तियाँ की हैं, उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ और उन्हें मैं ऑथेंटिकेट करके दूँगा।

इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति जुलाई, 2018 से हैं। उन्होंने 2018 में 4,000 छात्रों को बिना एग्जाम के पास कर दिया। पेपर लीक 2018 में, उत्तर पुस्तिका घोटाला 2019 में, वित्तीय अनिमितताओं के अनेक आरोप -- माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल के पूर्व कुलपति वित्तीय घोटाले में पकड़े गए और फरार रहे। फरारी में ही उनको हरियाणा में उच्च शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष बना दिया गया। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति नवम्बर, 2014-17

तक - चयन प्रक्रिया का उल्लंघन भी हुआ और अनेक अनियमितताओं के आरोप होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष बना दिए गए। इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय में हिंसा हुई, लड़के गिरफ्तार हुए, कैम्पस में छात्राओं का प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताएं हुईं। सीएजी की रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताएं थीं और वे सारी बातें उजागर हुईं।

गुवाहाटी में कुलपति महोदय 2019 से आज तक हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के केस फॉर मार्क्स घोटाले की देश भर में चर्चा है। उसकी आज भी जांच चल रही है और उसमें 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय 2020 से लेकर आज तक हैं। मार्क्स घोटाला, एडमिशन घोटाला, वित्तीय घोटाले, पेपर लीक घोटाला, फर्जी डिग्री घोटाला आदि अनेक घोटाले हैं। इसी तरह, आईआईटी गुवाहाटी में भी, आईआईटी रूड़की में भी, आईआईएम लखनऊ में भी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी, हमारे राजीव गांधी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, भोपाल में भी - तो उन महाशय जी ने 156 करोड़ रुपये नियम विरुद्ध प्रायवेट बैंक में खाते खुलवाकर उसमें से 19.48 करोड़ रुपए निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए। ये उस विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा के जगत को व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया। ...(**समय की घंटी**)... मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की नियुक्तियों के बारे में सारी बातें मैंने कर दी हैं, अब मैं नीट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

सर, नीट में भी आप देखेंगे तो जो महाशय आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं, 2006 में वैसे तो तत्कालीन गवर्नर साहब ने अपात्र होने के बावजूद भी उनको जबलपुर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट प्रोफेसर बना दिया था, फिर उनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश में होती है, जहां वे अपात्र लोगों की भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों पर कर देते हैं, जबकि यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है तो उसके पास कम से कम 10 साल का पीएचडी का अनुभव होना चाहिए।

श्री सभापतिः अब आप समाप्त कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंहः सर, मेरे पांच मिनट्स और बाकी हैं।

श्री सभापतिः नहीं।

श्री दिग्विजय सिंहः सर, मेरा एक निवेदन है कि मुझे दो मिनट और दे दीजिए।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंहः सर, आप मेरी पार्टी के टाइम में से मुझे समय दे दीजिए।

श्री सभापतिः नहीं, इनके पास टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया। आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो चुका है।

श्री दिग्विजय सिंहः सर, नीट के मामले में दूसरी बात यह है कि आज जो एनटीए के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में मेरे पास अनेक प्रमाण हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दूँगा। मैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी से नीट के बारे में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या आप 2024 के नीट की परीक्षा को निरस्त करेंगे, हाँ या नहीं? क्या एनटीए के अध्यक्ष, जो इसमें शामिल हैं, उनको आप बर्खास्त करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या नहीं? ये वही व्यक्ति हैं, जो 2006 में व्यापम के रचयिता थे और यहाँ तक पहुँच गए हैं। साथ में सीबीआई जो नीट की जांच कर रही है, उसमें भी हमें सीबीआई पर भरोसा इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीबीआई के अधिकारी जो जांच कर रहे थे, वे ही घोटाले में पकड़े गए और गिरफ्तार किए गए। मैं अंत में आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस देश में भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं - भीमा कोरेगाँव। भीमा कोरेगाँव वह प्रकरण है, जिसका इतिहास आपको मालूम है। वर्ष 2017 में वहां एक विवाद हुआ।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You are out of time.

श्री दिग्विजय सिंहः सर, लास्ट प्वाइंट है। वहां के लोगों से दलितों का विवाद हुआ, उसमें 16 लोगों को यह कह कर गिरफ्तार किया गया कि वे अर्बन नक्सल हैं। माननीय सभापति महोदय, आप तो विद्वान वकील हैं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई है, वे लोग जेल में हैं। यह देश कहां जा रहा है? मैं आपसे केवल इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं। *

श्री सभापति : दिग्विजय जी, आपकी ज़ुबान से एक वाक्य निकल गया है। ...(**व्यवधान**)... सुनिए।। am aware of it. I am expunging it. ...(*Interruptions*)... * ...(**व्यवधान**)... यह नहीं होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... That has already been withdrawn.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I regret and I withdraw it. ...(*Interruptions*).. But I stand on this issue what he said.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singh*ji*, you have set good standard. But making such kind of reference in this manner was not appropriate. Apart from being unparliamentary, it goes against ethos of our civilisation also.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: He said it what I have quoted.

MR. CHAIRMAN: I will request you, Digvijaya Singh*ji*, to authenticate two aspects. One, you said that Makhanlal Chaturvedi University's Vice-Chancellor, फरार हुए, which means 'absconder'. An absconder is one declared by law. Second, you said

*Expunged as ordered by the Chair.

that directly in the personal account Rs.158 crore have gone. Authenticate these two documents.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I will authenticate.

MR. CHAIRMAN: It is already withdrawn. The greatest thing is that if a person makes an observation and he expresses his regret and if the regret is from a person of Digvijaya Singh*ji*'s stature, I think, there should be quietus to the issue. Now, Shri Prakash Chik Baraik; it is the maiden speech of the hon. Member.

श्री प्रकाश चिक बाराईक (पश्चिमी बंगाल): माननीय सभापति महोदय, मैं आज अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं अपने राज्य, पश्चिमी बंगाल एवं पूरे देश की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए इस मौके का उपयोग करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो संबोधन दिया, उसमें वर्तमान सरकार की नीति एवं कार्यों की तारीफ की गई।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे आदिवासी संप्रदाय की एक महिला, राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाती है, लेकिन मुझे कहने में अत्यंत दुख हो रहा है कि आदिवासी संप्रदाय की होने के बावजूद उनके संबोधन में आदिवासी समुदाय एवं उनकी समस्या का एक भी उल्लेख नहीं हुआ। यह वास्तव में दुखद है, क्योंकि मैं एक आदिवासी परिवार से ही आता हूं। मैंने जब संसद परिसर में प्रवेश किया, तो मुझे पहले जैसा अनुभव नहीं हुआ है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let him speak. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश चिक बाराईक: हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। चाहे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हो, चाहे भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की हो, चाहे धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की हो, उनको अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि उन्होंने आदिवासियों के लिए और भारत के सभी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। हमारे लिए वे भगवान हैं। जब मैं पहले संसद परिसर में आता था, तब मुझे गर्व का अनुभव होता था। हमारे क्रांतिकारियों की मूर्तियां हर जगह पर थीं, हमें उनके दर्शन होते थे। वे याद दिलाते थे कि हम यहां हैं, तो क्यों हैं। पश्चिमी बंगाल की माननीय मुख्य मंत्री ने आदिवासी समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। हमारी सरकार ने 2011 में सत्ता में आने के बाद आदिवासी कल्याण दफ्तर बनाया, ताकि आदिवासियों की भलाई हो। सरकार के द्वारा सरना कोड के लिए जो प्रस्ताव आदिवासी समाज

का था, उसको केंद्र में भेजा गया।...(**व्यवधान**)...आप मुझे बोलने दीजिए। उसको केंद्र के पास विश्लेषण करने के लिए भेजा गया।

श्री उपसभापति: आप बैठिए। आपस में बात मत कीजिए।...(**व्यवधान**)... माननीय संजय सिंह जी, आप भी चुप रहें और बाकी सदस्य भी चुप रहें।

श्री प्रकाश चिक बाराईक: मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह बंगाल का ऐसा क्षेत्र है, जो चाय-बागान के लिए प्रसिद्ध है। मैं एक चाय बागान वाले का बेटा हूं और खुद भी चाय श्रमिक हूं। माननीय मुख्य मंत्री, ममता दीदी के आशीर्वाद से नॉर्थ-बंगाल के जितने भी चाय-बागान हैं - आदिवासी, राजवंशी, बोरो, टोटो, राबा, मेज, बंगाली, बिहारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। प्लीज, मुझे बोलने का मौका दीजिए। वहां दिन-रात चाय बागान के मजदूर मेहनत करते हैं, जो चाय श्रमिक हैं, जो आदिवासी हैं। इस देश में चाय पर तो चर्चा होती है, लेकिन चाय मजदूरों की चर्चा नहीं होती है, जो चाय बनाते हैं। एक भी मजदूर की चर्चा नहीं होती है। आप सबसे पहले 1951 के अमेंडमेंट को चेंज कीजिए। 99 परसेंट पॉपुलेशन, जो चाय की प्रोडक्टिविटी करती है, वह ट्राइबल एवं आदिवासी है। 11 स्टेट्स में चाय की प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन चाय बागान के मजदूरों की हालत देखिए, आपने उनके लिए कभी भी काम नहीं किया है। चाय बागान के मजदूर की कैसी अवस्था है, यह आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप चाय बागान के नहीं हैं। मैं चाय बागान का वर्कर हूं, वहां का बेटा हूं, तो मुझे बोलने का अधिकार है। आज इस स्थिति में चाय बागान हैं। जो केंद्र शासित चार चाय बागान हैं- बानरहाट, चूनाभट्टी, न्यू डुआर्स एवं करवला टी स्टेट, जो जलपाईगुड़ी जिले में आता है और पश्चिमी बंगाल से रिलेटेड हैं, जिनको केंद्र सरकार चलाती है, कई महीनों से इन चाय बागान वालों की पेमेंट रोकी गई है, प्रॉविडेंट फंड रोका गया, ग्रैच्युटी रोकी गई है और करोड़ों रुपयों का बकाया पैसा रोका गया है। यह किसने रोका है? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही रोका है। चाय बागान के मजदूर बेबस होकर एनएच 31 पर जाकर धर्मघाट पर बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रॉविडेंट फंड के लिए आवाज उठाई थी, इसके पहले भी हम लोगों ने पीएफ के लिए आवाज उठाई थी। जो मजदूर 250 रुपये की हाजरी में काम करता है, उसका 12 प्रतिशत पैसा काटकर पीएफ ऑफिस में जमा किया जाता है। वह पीएफ ऑफिस किसका है? वह केंद्र का दफ्तर है। जब मजदूर 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद उस दफ्तर में जाते हैं, तो उनको उस दफ्तर से उनका पैसा नहीं मिलता है। क्या आपको मालूम है कि उनको उनका पैसा क्यों नहीं मिलता है? आधार मैचिंग न होने की वजह से उनको पैसा नहीं मिलता है। एक चाय बागान का मजदूर जब प्लकिंग करता है, तो उसका हाथ छिल जाता है, जिसकी वजह से आधार उसकी उंगलियों को absorb नहीं कर पाता है। आपको 58 साल की उम्र के बाद mutual understanding करनी चाहिए। आपको चाय बागान के मजदूरों को provident fund देना चाहिए एवं ग्रैच्युटी देनी चाहिए। इन मजदूरों ने हम लोगों को बहुत दुख के साथ यह बताया है। आज भी हमारी आवाज को रोकने की कोशिश हो रही है। आज भी केन्द्र सरकार द्वारा प्रोवीडेंट फंड के लिए जो नीति बनाई गई है, जो घोषणा की गई है, उससे चाय बागान के मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पश्चिमी बंगाल की मुख्य मंत्री, ममता दीदी के सहयोग से चाय बागानों में करीबन 25 बागानों पर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 53

बागानों पर बच्चों के लिए क्रेच बनाए जा रहे हैं, बिना पैसे में राशन दिया जा रहा है, बिना पैसे में पेयजल की व्यवस्था राज्य की माननीय मुख्य मंत्री जी करा रही हैं। 1998 में पंचायती राज चाय बागान पर भी लागू हुआ, उसके बाद से हर काम राज्य सरकार कर रही है। लेकिन इसमें रेस्पांसेबिलिटी केन्द्र सरकार की भी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलिए, टैक्स बोलिए, चाय से केन्द्र के पास भी टैक्स आता है, तो क्यों इन चाय बागानों के लिए केन्द्र सरकार कुछ नहीं करती है। जब बागान बंद होते हैं, तो आप लोग एलिगेशन लगाते हैं, जबकि हम वहां जाकर उस बागान को खोलने का काम करते हैं।

पिछले 10 वर्ष में केन्द्र सरकार ने अपनी नीति के माध्यम से बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं को धोखा दिया। प्रधान मंत्री महोदय ने 2014 में वायदा किया था कि हर साल दो करोड़ नौकरियां मिलेंगी, मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल बीत गए, इस वायदे का क्या हुआ? हर साल नौकरियों की कटौती होती जा रही है। वास्तविकता यह है कि पिछले 10 वर्ष से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल रोजगार कार्यबल में से लगभग 83 परसेंट युवा हैं। संसद के रिकॉर्ड के अनुसार इस वर्ष 7 लाख 22 हजार लोगों को नौकरियां दी गईं। युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं और सरकार के पास इसकी कोई योजना नहीं है। बेरोजगारी के कारण युवा मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के बावजूद अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं। सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है, मेक इन इंडिया जैसे नारे लगाती है, लेकिन इन नारों का हश्र क्या हुआ, यह आप सभी को मालूम है। यह साफ दर्शाता है कि बेरोजगारी संबंधी वायदे को पूरा करने में सरकार असफल रही है। इसका असर समाज के हर ग्रुप में देखा जा रहा है। इस बेरोजगारी की वजह से युवाओं का विश्वास टूट रहा है। सरकार की नीतियों ने भारत की शिक्षा प्रणाली को तहस-नहस कर दिया है। एनईईटी, एनईटी एवं यूजीसी जैसी प्रमुख परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए। लगभग 7 वर्षों में 70 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इसका असर पूरे छात्रों पर पड़ रहा है। केवल छात्रों को ही नहीं, उनके मां-बाप को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनका भविष्य उनके मां-बाप बनाते हैं। जो बच्चे दिन-रात तैयारी करते हैं, उनको अंत में पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो यह उनके लिए बहुत दुखद समय होता है। उनकी मेहनत को सरकार की लापरवाही ने बरबाद कर दिया। वह मेहनत सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, बल्कि मां-बाप की भी है, उनके परिवार के लोग भी करते हैं। आप उनके सपनों को मत तोड़िए, आप उनकी उड़ान को मत रोकिए। आपको इन बच्चों की आंखों के आंसुओं का हिसाब देना ही पड़ेगा। इनका एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। छात्रों को अपने भविष्य के प्रति कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। हमें इसे बदलने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। युवाओं के बिना देश का विकास संभव नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवा उचित शिक्षा पा सकें, ताकि देश के विकास में उनका भी योगदान हो।

सरकार ने बड़े वायदे के साथ धूमधाम के साथ एनटीए का उद्घाटन किया। यह बताया जाता है कि इस एजेंसी के बनने से परीक्षा से जुड़ी बीमारी का रामबाण इलाज होगा एवं निष्पक्षता, पारदर्शिता का एक नया युग आएगा। हमें पता नहीं था कि एनटीए के तहत पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहां पर परीक्षा में पारदर्शिता नहीं हो रही है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं।

सरकार को इससे जुड़े सभी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी और इसकी सख्त निगरानी करनी होगी। हमारे नौजवान बेटे-बेटियों के जीवन से खेलना बंद करना होगा।

महोदय, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर आँख मूँद चुकी है। सरकार ने जो वादे किए थे, वे केवल वादे ही बनकर रह गए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गये। महिलाएं आज भी अपने घरों, सड़कों एवं कार्य स्थल पर असुरक्षित महसूस करती हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी एनसीआरबी के रिकॉर्ड में साफ बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ चुके हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 एवं 2022 तक महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

महोदय, सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, लेकिन यह आरक्षण का विधेयक इलेक्शन के आधार पर देखा गया। आप तृणमूल दल की गवर्नमेंट से सीखिए, आप माननीय ममता दीदी की गवर्नमेंट से सीखिए, आप लोक सभा और राज्य सभा को देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिला, जिसका रिजल्ट आज दोनों हाउस में देखा जा रहा है। राज्य की मुख्य मंत्री, माननीय दीदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है। इतना ही नहीं, जब बेटी पढ़ती है, तो उन्हें साल में 750 रुपये मिलते हैं, जब बेटी की उम्र 18 साल की हो जाती है, तो उनके एकाउंट में 25 हज़ार रुपये हायर एजुकेशन के लिए मिलते हैं और जब बेटी की शादी की उम्र होती है, तो उनके माँ-बाप के एकाउंट में 25 हज़ार रुपश्री प्रकल्प का पैसा मिलता है।

महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 140 करोड़ जनता की आबादी है एवं पश्चिमी बंगाल की 11 करोड़ पॉप्युलेशन है, जिसमें यह साबित हो गया है कि 'लक्ष्मी भंडार प्रकल्प' is a big achievement to us. यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। माताओं, बहनों और बेटियों के एकाउंट्स में उनका परिवार चलाने के लिए जो विवाहित होते हैं, उनमें एससी/एसटी वर्ग के लिए 1,200 रुपये, जो अदर कास्ट है, जनरल कास्ट के लोग हैं, उनके एकाउंट में 1,000 रुपये देते हैं। महोदय, सरकार को सक्षम होना पड़ेगा। सरकार को केवल एकमात्र विरोधी को दबाकर नहीं, बल्कि सबको मिलाकर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है, राष्ट्र निर्माण का काम करना है, जिसमें सबका योगदान रहे।

महोदय, मैं इस अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं कि सरकार का काम निरपक्ष होगा, सरकार सबके लिए काम करेगी, केवल एक को टारगेट करके नहीं काम करेगी। उस तरफ वाले एक माननीय सांसद ने हम लोगों को एड्रेस करके बोला था। मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी आपराधिक मामला रहा हो, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने जवाब दिया। रात में ही एफआईआर करने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ एफआईआर रजिस्टर भी की गई। मैं यह बात उनकी बात से संबद्ध करके बोलना चाहता हूं कि आप पहले अपनी स्टेट देखिए, अपनी जगह देखिए। ..(**व्यवधान**)..हम लोग चेयर को एड्रेस कर रहे हैं। यह जो भी सरकार है, यह गरीबों की सरकार नहीं है, आदिवासियों की सरकार नहीं है, अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं है। ..(**व्यवधान**)..हमें आने वाले दिनों में सचेतन होना पड़ेगा, नागरिकों को आवाज उठानी पड़ेगी एवं युनाइटेड होना पड़ेगा। आप सचेतन रहिए, क्योंकि घमंड सबका जाता है, इस बार आप लोगों का घमंड गया है। आप लोग सही तौर पर, सही जगह पर आए हैं। आप अहंकार मत कीजिए, समयानुसार जवाब मिलेगा। ..(**समय की घंटी**)..यह घमंड आपको चूर-चूर करेगा। आप वह वक्त

आने का वेट कीजिए। महोदय, मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K.R.N. Rajesh Kumar. You have eight minutes.

SHRI K.R.N. RAJESH KUMAR (Tamil Nadu): *"Sir, I would like to thank Leader of our party and Chief Minister of Tamil Nadu, *Thalapathi* M.K.Stalin, brother Udhayanidhi Stalin, Minister of Youth Affairs and Sports, State Government of Tamil Nadu, and hon. Member, Shri Tiruchi Siva, leader of DMK in Rajya Sabha for giving me this opportunity to speak in this House on the Motion of Thanks on President's Address. In this discussion which is taking place since yesterday, my dear colleagues from my party DMK pointed out the historic win of INDIA alliance in Tamil Nadu in the recently held General Elections. The candidates of INDIA alliance had won 40 out of 40 in Tamil Nadu. The credit of getting 100% success for INDIA alliance goes to our esteemed leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu. People of Tamil Nadu had acknowledged the three years rule of DMK-led State Government. Many Schemes are being implemented by the State Government of Tamil Nadu for the welfare of poor and downtrodden students, rural students etc. This election victory shows the support of the people of Tamil Nadu for our party DMK. I would like to point out one or two such schemes of the Government of Tamil Nadu in this House. Many poor students come to school with a hungry stomach. In order to address their sufferings, the State Government of Tamil Nadu had initiated a scheme to provide free breakfast to poor students studying at Government Schools. This scheme is called *'The Tamil Nadu Chief Minister's Breakfast Scheme'.* Under this scheme, in Government schools of Tamil Nadu, breakfast is provided to all primary school children studying from class 1st to class 5th on all working days. This scheme is unprecedented in the history of India. Other states are looking at Tamil Nadu with a sense of awe. State Government of Tamil Nadu is implementing this scheme very successfully.

The other scheme I would like to point out here is, "*Naan Mudhalvan*" scheme. It is a massive upskilling platform. We say that youth are the future of this country. This "*Naan Mudhalvan*" *scheme* is a scheme to provide scholarship to students to enhance their skill development. Under this scheme, financial assistance is given to students who prepare for competitive examinations. In the recently published UPSC exam results, 42 students from Tamil Nadu had cleared the examination. 45 students had cleared the Main examination of UPSC. Of these 45

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

students, 37 students have got financial assistance under the *"Naan Mudhalvan" scheme*. A student by name Ms.Vinodhini, who scored the second rank in the state had spoken about *"Naan Mudhalvan" scheme,* in an interview to the popular daily *'The Hindu'.* I quote: "The financial assistance given through *"Naan Mudhalvan" scheme* of Government of Tamil Nadu reduced my economic burden. It had helped me in the preparation for competitive exams."

Hon'ble Deputy Chairman Sir, this House knows that our party DMK, has been opposing NEET examination since its inception. Due to this examination, twenty-two students in Tamil Nadu had committed suicide. I can cite examples from Ms.Anita to Mr. Jagadeesh. Our primary aim is exemption of Tamil Nadu from NEET.

During last October, brother Udhayanidhi Stalin, Minister of Youth Affairs and Sports, State Government of Tamil Nadu, started a signature campaign against NEET examination. His aim was to get almost fifty lakh signatures in 50 days. But the movement had an overwhelming support from people. He was able to get more than one crore signatures against NEET examination. This shows the attitude of the people against NEET. That is why Tamil Nadu is opposing NEET examination since it is announced.

Sir, who is actually benefitting from NEET examination? The real beneficiaries are the coaching centres. They earn huge profits. You might have known that each and every student has to pay Rs.4-5 lakhs annually if he intends to attend a coaching class. Poor students studying at Government schools and rural students cannot afford coaching classes. It is difficult for them to prepare for such examinations. But they should also get access to higher education. That is why we are always opposing NEET examination. The struggle against NEET is happening in various parts of the country now.

In the recently held session of Legislative Assembly of Tamil Nadu, the resolution against NEET was passed unanimously. It was sent for the consideration of Union Government. The Union Government should exempt Tamil Nadu from NEET examination. Sir, I request, through you in this august House, that my demand may be considered.

Sir, the President's address had pointed out many schemes and projects of the Union Government. I would like to point out a project in Tamil Nadu which is not yet approved by the Union Government. The Union Government did not give its approval for the second phase of Chennai Metro Rail Project. It is delayed. On 21st November, 2020, hon. Union Minister of Home Affairs had laid the foundation stone for this project. In Budget 2021-22, financial outlays for this project were announced. The total estimate of this project is Rs.63,246 crore. The project will cover 119

kilometres having three routes. The total project cost would be shared on the basis of 50:50 per cent by both the Union Government and the State Government. Still, the project is yet to get the approval of Cabinet Committee on Economic Affairs. It has been already delayed for more than two years. I request that the approval may be given as expeditiously as possible. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. K.R.N. Rajeshkumar. Now, Shri Ryaga Krishnaiah; not present.

SHRI K.R.N. RAJESH KUMAR: Sir, please allow me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Priyanka Chaturvedi. ...*(Interruptions)*... No. It is not going on record. ...*(Interruptions)*... There are more than 105 speakers. Time is allocated and mentioned here. I have to follow that. Priyankaji, you have three minutes.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। समय कम है और मुझे समय कम दिया गया है, तो सबसे पहले मैं यह कहूंगी कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, वह लोक सभा चुनाव के बाद पहला अभिभाषण था। मैं यह कहूंगी कि जनता ने लोक सभा से एक बड़ा संदेश भेजा है, वह सराहनीय है और हमारे प्रजातंत्र की एक बड़ी जीत दिखाता है।

सर, एक और संदेश है जो चुनाव ने भेजा है। भगवान श्री राम कौशल्या पुत्र भी माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र भी कहे जाते हैं, उन कौशल्या पुत्र और देवकी पुत्र भी कहे जाते हैं, उन कौशल्या पुत्र और देवकी पुत्र ने मिलकर एक संदेश भेजा है और जो अपने आपको नॉन-बायोलॉजिकल कहते हैं, उनको एक फर्क दिखाया है और यह बताया है कि भगवान का अवतार भी अपनी माँ के नाम से भगवान माना जाता है। यह सबक जो सिखाया है,उसके लिए मैं इस देश की सारी जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। वे सारे बायोलॉजिकल वोटर्स, जिन्होंने आकर नॉन-बायोलॉजिकल को एक सबक सिखाया है, उससे ये कुछ सबक सीखेंगे। उसी कौशल्या पुत्र और देवकी पुत्र ने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, अयोध्या से लेकर नासिक तक भारतीय जनता पार्टी को हराया है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। एक और संदेश जो इस इलेक्शन ने हमें दिया है, देश की जनता को दिया है कि जो अहंकार से चलेगा, उसको अहंकार ही खत्म करेगा। यह जनता का मत था, जिसने आज विपक्ष को भी मजबूती से अपनी बात रखने का मौका दिया है। पर अभिभाषण में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि केन्द्र सरकार ने किसी तरीके का सबक सीखा है। केन्द्र सरकार ने यह समझा होगा कि जो biologically born होते हैं, वे महँगाई से जूझ रहे हैं; जो biologically born होते हैं, वे NEET की जो paper leaks हो रही हैं - इतने सालों में करीब 41 पेपर लीक्स हुई हैं, उसके ऊपर उनको दर्द होता है; ये जो biologically born हैं, वे बेरोजगारी से परेशान हैं; ये biologically born जो हैं, वे महिलाएँ, जो सम्मान ढूँढ़ती

हैं, उम्मीद करती हैं कि उनको सम्मान दिया जाएगा; ये जो biologically born हैं, ये हमारे युवा हैं, अग्निवीर जैसी जो पॉलिसी लाई जाती है, वे उससे जूझ रहे हैं, उसका शिकार हैं; जो biologically born हमारे किसान हैं, वे भी त्रस्त हैं, पर उनके अभिभाषण में केन्द्र सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, जो दिखाता है कि course correction होने वाला है। मैं तो बस यही कहूँगी, ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं बस wrap up ही कर रही हूँ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगी।

श्री उपसभापति: आप conclude करिए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: मैं बस यही कहूँगी कि आप अहंकार से चलते रहिए, ऐसे अभिभाषण उनके मुँह से बोलवाते रहिए और आने वाले समय में 240 से 40 के लिए आप तैयार रहिए। सर, जय महाराष्ट्र, जय हिन्द!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim, five minutes.

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, the Narendra Modi Government had only one fuel to come to power in 2014 and continue thereafter. It is divisive politics. In the last ten years, the problems faced by common people in India have never bothered them. They are still not ready to discuss the problems of common man in this country. Once revolutionary Chilean Poet Pablo Neruda wrote:

"And you will ask: why doesn't his poetry
speak of dreams and leaves
and the great volcanoes of his native land??
Come and see the blood in the streets,
come and see the blood in the streets,
come and see the blood in the streets!"

Sir, come, let's discuss the price hike in this country. Come, let's discuss unemployment in this country. Come on, let's discuss about *dalits* and minorities being attacked. Come, let's discuss about the bulldozer *raj*. Come, let's discuss about the political and social reality of this country. According to the latest N.C.R.B. data, in the last five years, one lakh people lost their lives in train accidents. Along with the accounts of the dead, I am reminding this august House of another account. According to the latest official figures, 2.5 lakh posts are lying vacant in the railways. Also, as of now, 18,999 vacancies of assistant loco pilots are lying vacant. All train tragedies in the country are result of the Union Government's anti-youth policies of

not making enough appointment and creating new posts. Sir, in the hon. President's Address, there is no mention of unemployment. Unemployment is mushrooming in the country like cancer. According to the figures given by the Minister, Dr. Jitendra Singh in the Rajya Sabha on 26th July, 2023, there are 9,64,359 vacancies in the Ministries, various institutions and agencies of the Union Government. The unemployment rate rose to 8.01 per cent in the April according to the data given by the Centre for Monitoring Indian Economy. In the 18th paragraph on the 14th page, the hon. President mentioned that the Government could make the Defence sector self-reliant but this Government weakened the Defence force by introducing Agnipath scheme. Contractualization of the Army reduced its efficiency. The Government has * lakhs of youth who wish to join the Army and serve the country. Even the JD(U), which is the backbone of this minority Government, has the same opinion. The Union Government should put aside the narrow politics and withdraw the Agnipath scheme immediately. The hon. President used the name of Gandhi*ji* only once in her speech. The 16th paragraph on the page number 14 of the hon. President's Speech says: "For the first time, toilets were built for crores of poor people in the country. These efforts give us the confidence that today the nation is following the ideals of Mahatma Gandhi in the true spirit." Since 2014, the Narendra Modi Government has been trying to rebrand Mahatma Gandhi as just an ambassador of this Swachh Bharat.

4.00 **P.M.**

Yes, Sir; Mahatma professed hygiene and wellness. But, ultimately, Mahatma Gandhi is an ambassador of Indian secularism, an ambassador of Indian pluralism. The true spirit of Gandhi is secularism, not the toilet. ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम was his *mantra*. Gandhi lived and was martyred for secular India. On the one side, the Narendra Modi Government build toilets in the name of Gandhi, and on the other side, you bulldoze Gandhi's dream of secular India. Even after the election results, the *Sangh Parivar* has unleashed several acts of violence against minorities in the country. Is this the true spirit of Mahatma Gandhi? ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम was Gandhi's *Mantra*, but काशी, मथुरा बाकी है is your *mantra*.

Sir, once again, I would like to repeat that ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम was Gandhi's *Mantra*, but काशी, मथुरा बाकी है is your *mantra*. Communalism and hate politics is the only fuel of this Government, and the policy is divide and rule. In short, the President's Address is extremely disappointing for me and my party.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. *(Time-bell rings.)* Your time is over.

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I am concluding. It is because the speech has no connection with the social and political reality of the country. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Shri Ryaga Krishnaiah.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH (Andhra Pradesh): *"Hon. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Sir, the President's Address mentioned all the points. The highest population in India, which is the Other Backward Class (OBC), comprises 56 per cent of the country's population. Even after 75 years of independence, they are not receiving proper justice. Injustice is being done to them in the sectors of education, employment, politics and in almost all the sectors. Even though India is on the edge of becoming a developed nation and paved its way to becoming an advanced country, fifty-six per cent of the people in the country, have not been given human rights, social rights and constitutional rights until now. Primarily, there are more than 2,600 different castes in the BC list. Among the OBC list are denotified tribes, semi-denotified tribes, nomadic tribes, extremely backward classes, dhobis, barbers, stone-cutters, fishermen and many more castes which are extremely backward. Even after seventy-six years of independence, the castes did not get equal rights. They did not receive the needed help in any sector. At this juncture, when we are claiming that India is a developed nation, BCs are lagging far behind in the education sector, employment sector, as well as in the political sector. For example, thirty-two per cent of the people are still illiterate. It is our constitutional responsibility to provide education to them. It is not a charity. It is their right. It is the share of the country. It is their democratic share.

After seventy-six years of independence, all Governments, be it the past Governments or the present Government, are lagging in providing education to the SC, ST and BC communities. What we are giving to OBCs is not charity. It is their Constitutional Right. But the governments have not thought about this. The Bharatiya Janata Party selected the Prime Minister from the OBC community. We are thankful for this. But it is not just enough to have a Prime Minister from the OBC community; measures should be brought for the development of the OBC community. People from the OBC community are surviving as beggars, and nomadic tribes and when we

* English translation of the original speech delivered in Telugu

pass through road, we can see small children working as bonded labour in the agricultural fields. Hence, there is a need for bringing reforms in the basic policy of the Governments to make fundamental change in the way of their lives. यदि उन लोगों को financial assistance दिया जाए, तभी वे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होने से वे कैसे पढ़ सकते हैं? In Andhra Pradesh, Shri Jagan Mohan Reddy's Government gave the highest priority to education. All the schools were converted to English medium and fee reimbursement was introduced at the college level too. Each student was given twenty thousand rupees as a scholarship. Students going abroad for studies were given fifty lakhs to one crore rupees as a stipend. In this way, education was given the highest priority and spending on education was considered as an investment. That is why, there is a need for Jaganmohan Reddy's policies to be taken as an example and adopted by all the State Governments and Central Government in the country. Investment in education is a capital investment. The entire family will be developed by investing in education. Even now there is a need to change policies in the Central Government. What we give to BC is not charity. It is their Right. It is their democratic right. Till date, the Central Government has not established a Ministry for the OBC. In the Budget too, when the total budget was around forty-five lakh crores, a mere amount of two thousand crores was allocated to them as alms. They can't even buy chocolates or biscuits with that money. For seventy-six crore BCs, only two thousand crore rupees was allocated in the Budget. The Mandal Commission made 40 recommendations but 38 recommendations have not been implemented till date. The department was not set-up. They are not even coming forward to initiate the census. Therefore, the Central Government should change its approach towards the BCs. The Bharatiya Janata Party made a person from Backward Class as the Prime Minister of the Country; it made a person from Scheduled Tribe as the President of this Country. We are only asking what it did for the people from the BC community. What are your plans? BC people should receive education. They need a share in power. For this to happen, there is a need to bring reforms in the education, employment and financial sectors. What is the culture of our country? "Sarve jana sukhino bhavantu". I question you all. Where is it now? Everyone should introspect and, necessary reforms should be made to provide Constitutional Rights and Democratic Rights to the 76 crore people of the OBC Community. They made the Prime Minister from the OBC Community and the President from the ST Community. We accept it. But where are the measures? What are the measures taken for educating the OBCs? Where is the share in power? Employment did not exceed 16 per cent till now. It has been more than 35 years since the Mandal Commission was implemented. The employees' percentage of BCs did not cross 16 per cent. In the Central Government, there are

nearly one hundred Principal Secretaries. They are policy-makers. But what is the number of OBCs in them? It is just three. I question, is it the procedure in this country? It is their democratic share. The Party and the Government should change its approach towards the OBC. In many countries in the world, exploitation, oppression and discrimination have caused rebellion. People are fighting for their rights. Look at China, Japan. Look at Russia. Look at France. People revolted for their rights, for their existence, for their self-respect. We are welcoming it.

Buddha was born in this country, Vivekananda was born in this country, and Shankaracharya was born in this country. So, we are talking about peace and harmony. Sarvejana Sukhino Bhavantu, means, may all people be happy. The happiness of capitalists and corporates does not count. People from the lower class should be happy. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, we respect him a lot. He is a yogi. He sacrificed everything for the nation. But what is the purpose of this dedication without the development of the weaker sections? In this country, Buddha, Vivekananda and great personalities were born. They strove for the betterment of the country and the upliftment of the living standards of the people in this country. However, the situation of the poor is miserable. They are sleeping with half-filled bellies. The majority of them are from SC, ST and BC. If reforms are not brought for the upliftment of their living standards, surely, there is a chance of the people to revolt. World history tells us this. The Central Government should recognize the matter and reserve all the rights that should come to OBC. Reservations based on population percentage should be introduced in the Parliament. A census should be conducted. A Ministry for the OBC should be established. Education should be promoted by building schools and hostels and also reimbursing school fees and distributing scholarships.

'Beti Bachao Beti Padao', but how will they study? They can study only when financial assistance is given to them. BCs across the country have started a movement. They are demanding for BC census. Give us what we deserve, give us our share.

Many people in the Central Government have said that India is a Vedic land and Karmabhumi. But in this Vedic land and Karmabhumi, 30 per cent of the population are half-starved people, ignorant and innocent. Irrespective of party affiliation, everyone who is born in the OBC Community should fight for their rights. In the budget, out of 45 lakh crores, only two thousand crores were allotted. What is lost if two lakh crores are allocated? To whom are you giving? You are giving it to the people of the country. The people of this country are children of Mother India. They are not enemies, they are not from China, and they are not immigrants from other

countries. They are the citizens of this country. They are the sons of the soil. The development of these people is the responsibility of the Indian Government. Sir, through you, I request the Central Government that we must think radically and take steps to bring changes on a large scale for the education, employment and economic development of the BCs.

In the private sector too, reservations should be made for the SC, ST and OBCs. Every sector is being privatized. Therefore, there are no government jobs. To get jobs in the private sector, SC, ST and OBCs should be given reservations by their population ratio. Similarly, there are no judges from SC, ST and OBCs in the Supreme Court and High Courts. A reservation system should be made in the higher judiciary because there is not a single judge in the Supreme Court from the OBC. Look at the court cases, the other day, they said that, for the upper castes to get a ten per cent reservation, a fifty per cent ceiling can be crossed. But, for Panchayati Raj reservations and political reservations, they said that it is unconstitutional. Do not exceed ten per cent increase and it is against the court rulings. Is it not injustice towards the OBCs? This is very unfair.

Is there such oppression anywhere else in the world? It used to be there in Africa and America, but people revolted there. In the land where Buddha was born, Vivekananda was born and Shankaracharya was born, OBCs who are the majority in the population, have created the wealth of the country but are in poverty, if injustice is done to them, they would definitely revolt. The upper castes were given ten per cent reservation. Did they ever ask for it? Did they ask for any representation anytime? Did they stage any dharna? Reservation was given to them without any demand. When it was mentioned three per cent, it was changed to ten per cent, whereas for BCs fifty-six was changed to twenty-six. Is this justice? In the last batch for IAS and IPS, those who secured fewer marks than SC and ST candidates got selected because of EWS reservation.

Sir, through you, I request the Central Government that, in the country, there are sixteen lakh jobs within government departments and public sector organizations. These vacancies are not being filled. If the vacancies are filled, all the people belonging to OBC, SC and ST communities will be securing jobs. So, a conspiracy is being hatched, by not filling these vacancies. Sir, these vacancies should be filled, similarly, reservation should be made in every private sector and a special Ministry for OBC should be set up. This is what we are asking.

In this country, with the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, in the Panchayati Raj, Reservation, for the 56 per cent BC population, the reservation was 34 per cent, It was further reduced to twenty per cent. In this country, Judges from

High Courts and Supreme Courts, MPs and MLAs are also from your communities. You are unable to accept when someone from our community becomes a Sarpanch. Is this the Justice in the country?

Sir, through you, I request the Central Government, to make amendments to the Bills, and to make reservations in the Panchayati Raj system in proportion to their population. In the same way, Bills should be introduced in the Parliament. Sir, discrimination is prevalent in this country. For discrimination towards women, you brought the Women's Reservation Bill and we welcome it. At the same time, there is caste discrimination. We do not have a share in the authority. Why are you hesitating to introduce the OBC Bill? If not today, you have to bring it tomorrow. It is inevitable. BC population is the maximum in this country. Caste census should be conducted and reservation should be provided as per the population ratio.

Similarly, Panchayati Raj reservations should also be provided with Constitutional provisions. I want to bring to your notice about the injustice in our country. After years of protest, reservation in IITs and IIMs was implemented. In these institutions, children of dhobis, stone cutters, shepherds and beggars are securing seats. But what is the fee collected there? It is around one lakh eighty thousand rupees. Can a person from the dhobi community or beggar community afford to pay that fee? Why is the Government not bearing the total fee for students coming from these poor communities? The Government should change its approach towards these communities. I am asking, if you give them seats in these institutions and not bear the fee, how will they pursue their education?

Sir, people from the BC community are subjected to discrimination. Therefore, the Central Government should take voluntary measures to deliver justice to the people from these communities. The BJP Party, which made the Prime Minister and President from OBC and ST communities, what is stopping them from fulfilling these small demands of ours?

So, do self-introspection and without taking it negatively, from a positive perspective, should consider us as your brethren and should strive for the upliftment of these communities. The talent and skills of these communities should be used for the development of the country.

Many intellectuals and talented people are migrating to America and other countries due to lack of opportunities in the country. If we keep aside the discrimination and use the talent of the people from these communities, India's growth rate will accelerate at a higher speed. The people from these communities should not be looked at from a negative perspective. But, think positively and give equal justice to them. We should be given equal opportunities in all sectors. We have

a share while voting. We have a share in the state's debts. We have a share in giving you the power. But we do not have a share in the wealth and authority. Were the loans of poor farmers or loans of self-employment schemes waived off? The Central Government should change its perspective. A separate Ministry should be established for OBCs, more budget should be allocated and schemes should be introduced and implemented.

Sir, without the development of the seventy-six crore people from these communities, India will never become a developed nation. India will become a developed nation only when everyone is empowered. The Central Government should think in this direction. I conclude by wishing that God would grant you all such thoughts. Jai Hind!

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदय, 18वीं लोक सभा गठित होने के बाद 27 जून को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अभिभाषण दिया और 28 जून को माननीय सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी ने Motion of Thanks की शुरुआत की है, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। सर, 2024 में जो इलैक्शन हुआ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण इलैक्शन था। 6 decade के बाद थर्ड टर्म में एक stable Government आई है। यह government NDA की है और pre-poll alliance एनडीए का था और यह बात सभी सदस्यों को पता है। 140 करोड़ जनता ने एनडीए के नेता हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर trust दिखाया और 2024 के इलैक्शन के रिजल्ट में यह stable Government है और trusted Government है, जिस पर 140 करोड़ जनता का ट्रस्ट है। यह trust in policy है, यह trust in intention है, trust in dedication है और trust in decisions है।

उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दस साल से government थी और इस Government में जो विकास हुआ है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। अगर 2014 से पहले देखें, तो हम जब भी अखबार खोलते थे, तब एक * यूपीए की गवर्नमेंट थी और बहुत सारे मंत्री जेल में गए थे। इतना ही नहीं, हरेक शहर में, बड़े-बड़े शहरों में आतंकवादी हमले होते थे और भारत की छवि पूरी दुनिया में एक गरीब देश की थी, जिससे पूरी दुनिया में भारत का सम्मान कम हुआ था, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में जो सरकार थी, उस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि एक भी बड़े शहर में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। भारत की जो fragile economy थी, वह बढ़ चुकी है और भारत का सम्मान बढ़ चुका है। सही मायने में देखें, तो 2014 से लेकर 2024 तक भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी fragile economy थी, वह अभी दसवें नंबर से पांचवें नंबर पर आ गई है। Per capita income के बारे में बहुत सारे सदस्य बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि per capita income भी 2014 में 86,000 थी, अभी 1,72,000 हो चुकी है। मैं

* Expunged as ordered by the Chair.

आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश का हरेक नागरिक मोदी जी का परिवार समझा जाता है। मोदी जी बोलते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है और इस परिवार के लिए ही प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। अभी मैं सभी सदस्यों को सुन रहा था - caste, religion और धर्म कोई नहीं है, 140 करोड़ जनता के लिए काम हो रहा है। उसमें मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें गरीब हो, गरीब का कल्याण कैसा हो, महिला का सशक्तिकरण कैसे हो, किसान का विकास कैसे हो और युवा का future कैसा बने, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम चालू है। भारत रत्न माननीय डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताया था कि भारत एक progressive राष्ट्र है। यदि society की progress होगी, तो ही lower strata की progress हो सकती है। वैसे ही भारतीय जनसंघ की संस्था पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह बताया था कि जब तक अंत्योदय, यानी गरीब से गरीब आदमी को मदद नहीं मिलेगी, गरीब से गरीब आदमी का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता है। यह ध्येय सामने रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों स्कीम्स निकाली हैं और इन स्कीम्स का फायदा जनता को हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि पीएम गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिलता है। अगर 80 करोड़ अनाज मिलता है, तो इसमें reform करके biometric system लाया गया है, जिसके माध्यम से लाखों-करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कम हो चुका है। इतना ही नहीं 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड और 10 हजार जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसके माध्यम सस्ती दवा मिलती है। मैं एक डाक्टर हूं और बताना चाहता हूं कि अगर angioplasty करनी है, तो जो stent मिलता है, अगर branded stent लें, तो 50 हजार रुपये से ज्यादा के मिलते हैं, लेकिन जन औषधि से लें, तो 7,000 में वह stent मिल जाता है। उतना ही नहीं चार करोड़ लोगों को आवास और free treatment इसमें दिया है। ...(**समय की घंटी**)... मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि महिला का सबलीकरण करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं और युवा के future के लिए बहुत सारे scope हैं। सर, election तो हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के माध्यम से प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है ...(**समय की घंटी**)...,तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि भारत देश का विकास कैसे हो। भारत विश्व बंधु कैसे बने और भारत विश्व गुरु कैसे बने। इसके लिए सभी को मिल-जुलकर काम करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करते हुए, इस प्रस्ताव को मैं सत्यापित करता हूं और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद अदा करता हूं।

श्री उपसभापति : प्रो. राम गोपाल यादव जी, आप बोलिए। आपका बोलने का समय तीन मिनट है।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** धन्यवाद श्रीमन्। समय तो है नहीं, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ बातें ऐसी हैं, जो होनी चाहिए थीं, लेकिन नहीं हैं। पूरे देश में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में और सेंटर में भी corruption rampant, कहीं पर भी करप्शन की चर्चा नहीं है। जो ये वोट देने के लिए लोगों को अन्न देते हैं, उसमें भी 30 परसेंट सम्पन्न लोग गरीबों की 18 से 28 परसेंट के आसपास सब्सिडी खा जाते हैं। मैंने देखा है जब

गांव में अन्न बांटने जाते हैं, तो वे लोग जो अपात्र हैं, जिनको मिल रहा है, उनसे खरीदने के लिए वहीं लोग खड़े होते हैं। वे अपना अन्न बेच देते हैं, nobody cares for it. देखिए, दिल्ली हवाई अड्डे पर canopy गिरी, जामनगर में गिरी due to corruption. राम जन्म भूमि पर वन गमन पथ 10 किलोमीटर तक नीचे धंस गया, लम्बाई में due to corruption. अब मैं नहीं कहूंगा कि भगवान श्रीराम के मंदिर में भी पानी टपका है। ये लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ है, but it happened.

हर घर में नल से पानी भेज रहे थे, अकेले जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपया दिया है। अभी तक पांच परसेंट घरों में पानी नहीं पहुंचा है, जाने कहां पर पैसा चला गया है ? मैंने यह बात पहले भी यहां पर कही थी। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के एम.पीज़ अपने गांव में जाएं और उत्तर प्रदेश में जाकर देखें कि कहां-कहां पर नल से पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है, तो जो पैसा आया, वह कहां चला गया ? सबसे बड़ा करप्शन है- कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनके माध्यम से चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, सबके पेपर्स आउट होते हैं। किसी भी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, everybody knows कि कौन-कौन से सेंटर्स हैं, जिनकी एप्रोच इतनी है कि वे पेपर लीक करा लेंगे। ऐसा लगातार हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि unemployment पर कहीं चर्चा नहीं है। अभी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आज तक के इतिहास में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह NCLT के जरिए से हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि 31 मार्च, 2023 तक 616 केस इसने रिज़ाल्व किए, इसमें बैंकों का उन पर 8.3 लाख करोड़ कर्जा था। बैंकों को समझौते के जरिए मिला 2.3 लाख करोड़ और वे कर्ज मुक्त हो गए और haircut में 5.67 लाख करोड़ ...(**समय की घंटी**)... मतलब 69 per cent haircut और इसमें सबसे ज्यादा हेयरकट मिलने वाला था, वह अडाणी साहब की एक कम्पनी है Good Homes जिस पर 96 परसेंट हेयरकट है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कितनी सम्पत्तियां बिकीं, उन पर कितना कर्ज था, उनकी एक्चुअल वैल्यु कितनी थी, जिनको वे सम्पत्तियां बेची गईं, वे कौन लोग थे ? ...(**समय की घंटी**)... एक-एक व्यक्ति को लाखों करोड़ का लाभ हुआ है। मैं तो कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं, दो-तीन लाख करोड़ से अधिक की बगल में सम्पत्ति है, केवल 40 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था, 30 हजार करोड़ रुपए में बिक गई, इससे haircut में जो चला गया, उससे बैंकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और individuals को लाखों करोड़ का लाभ हो रहा है। इससे बड़ा कोई करप्शन नहीं है। यह ऐसा मामला है, जिसकी जांच होनी चाहिए और करप्शन तो इसके सामने कुछ भी नहीं हैं। ...(**समय की घंटी**)...

सर, unemployment की स्थिति यह है कि अब आईआईटी के लोग भी unemployment के कारण हर साल बढ़ते जा रहे हैं और लोग तो सड़कों पर घूम ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां पर unemployment rate zero है। पुलिस में 50 हज़ार सिपाहियों की भर्ती निकली, 68 लाख लड़के-लड़कियों ने इम्तिहान दिया, लेकिन पेपर लीक हो गया और कई लड़के-लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि जो ओवर एज हो जाते हैं, वे जानते हैं कि अब उन्हें कहीं नौकरी तो मिलने वाली नहीं है ..(**समय की घंटी**)..

श्री उपसभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, एक मिनट और हमारी बात सुन लीजिए।

श्री उपसभापति: ऑलरेडी 5 मिनट हो गए हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: एक मिनट और दे दीजिए।

महोदय, जो आरक्षण है, ये लोग कैसे उसको खत्म कर रहे हैं। अगर सरकारी वैकेंसी निकलेंगी तो आरक्षण मिलेगा - पिछड़ों को 27 परसेंट और दलितों को 22.5 परसेंट। लेकिन आउटसोर्सिंग और कॉंट्रेक्ट बेसिस पर सारी नियुक्तियाँ होने लगीं और आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। ये जो तीन नये कानून आए हैं, जिनका डंका बज रहा है, इनमें 95 परसेंट वही धाराएं ज्यों की त्यों हैं, केवल ऊपर नाम बदल दिया गया है। ..(**समय की घंटी**)..

श्री उपसभापति: आपका समय समाप्त हो गया है।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, एक मिनट दे दीजिए। बहुत ही खतरनाक चीज़ें आ गईं।

श्री उपसभापति: आपके 6 मिनट हो गए हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, यह बताना जरूरी है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दो आदमियों से ज्यादा कोई काम करते हैं, तो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ थीं, वह एक्टिविटी संगठित गिरोह के अंतर्गत आ गई। अगर पोलिटिकल पार्टीज़ आंदोलन भी करेंगी और कोई सब इंस्पेक्टर यह लिख देता है कि यह संगठित गिरोह का काम है, तो 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। एक आंदोलन तो हम लोग करेंगे ही, इसलिए तीन साल की सजा करा दीजिए, विपक्ष आराम से खत्म और आप सत्ता चलाइए।

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव: सुधांशु जी नहीं हैं।

श्री उपसभापति: तीन मिनट सभी के लिए हैं। आप बोल चुके हैं, प्लीज़ दूसरों को भी समय दीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, आप एक सेकंड सुन लीजिए।

* से कोई काम चलता नहीं है और जब वह चीज़ प्रकट हो जाती है, तो नुकसान होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है,

'उघरहिं अंत न *होइ* निबाहू।
कालनेमि जिमि रावन राहू।'

---

* Expunged as ordered by the Chair.

सभी लोग यह समझ लें। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय रामचंद्र जांगडा; अनुपस्थित। श्री राघव चड्ढा, आप बोलिए, आपके पास 6 मिनट हैं।

श्री राघव चड्ढा (पंजाब)**:** सर, क्योंकि मैं सदन का सबसे युवा सदस्य हूं, मैं अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, अगर आज मैं इस देश के युवाओं का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसे न उठाऊं।

सर, इस देश में दो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। एक शिक्षा व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाए गए, बढ़िया करिकुलम, क्वालिटी एजुकेशन दी गई और एक शिक्षित भारत बनाने का सपना लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़े। महोदय, एक दूसरी शिक्षा व्यवस्था वह है, जिस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा शिक्षा माफिया जन्म लेता है, जिसके तहत आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार के कगार पर खड़ा है। महोदय, मैं बात कर रहा हूं नीट, यूजी और यूजीसी नेट की, जिसमें कुल मिलाकर करीब 35 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ। हमने देश भर में देखा कि कैसे उस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुए, उसमें माफियाओं का क्या राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार के कगार पर खड़ा हुआ है। वे 35 लाख बच्चे आज इस संसद टीवी को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद उनके अधिकारों की, उनके हकों की बात होगी।

महोदय, भारत देश एक बहुत युवा देश है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयु की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। जहाँ जापान की पॉप्युलेशन की औसत उम्र 50 साल है, इटली की 48 साल है, जर्मनी की 46 साल है, यूनाइटेड किंगडम की 40 साल है, चीन की 40 साल है। जहाँ विकसित देश बूढ़े होते जा रहे हैं, वहीं भारत देश जवान हो रहा है। आज भारत की औसत उम्र मात्र 29 साल है। लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकंड हाइएस्ट स्टूडेंट्स पॉप्युलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें, तो कुल मिलाकर भारत देश की 31 करोड़ आबादी स्टूडेंट्स कहलाती है। यानी कि इतने लोग पढ़ाई-लिखाई का काम करते हैं। लेकिन हमने उन युवाओं के लिए किया क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया है।

महोदय, इस देश में दो आईपीएल हैं। एक आईपीएल वह है, जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं। दूसरा आईपीएल, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, वह है इंडियन पेपर लीक। आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूँ कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बरबाद करने का काम किया गया है। मैं उस सूची के नाम पढ़कर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमने क्या-क्या अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला, Vyapam Scam, दूसरा UGC-NET paper leak, तीसरा Telangana Secondary School Certificate Examination, Hindi paper leak, Assam HSCLC, General Science paper leak; Uttar Pradesh Lekhpal Recruitment Exam paper leak; Rajasthan Forest Guard Recruitment Exam paper leak; Bihar Public Service Commission Exam

paper leak; Gujarat Head Clerk Exam paper leak; SSC, CGL, exam paper leak; UPTET exam paper leak; Rajasthan University paper leak; UPPSC paper leak; Maharashtra HSC Exam- Chemistry paper leak; UP Police Constable Qualifying Exam paper leak; REET, that is, Rajasthan Eligibility Examination for Teachers' paper leak; Haryana Police Constable Exam paper leak; Himachal Pradesh Police Constable Exam paper leak; Railway Recruitment Board Group 'D' Exam paper leak; Odisha Teacher Eligibility Test paper leak; Assam Police Recruitment Exam paper leak; बिहार बोर्ड का दसवीं कक्षा का एग्जामिनेशन का भी पेपर लीक, Telangana SSC Exam paper leak; Karnataka SSLC Exam paper leak; Delhi University Law Entrance Exam paper leak; Jamia Milia Islamia Entrance Exam paper leak; UP Board Exam, Mathematics and Bio का paper leak. Rajasthan Teachers' Recruitment Exam paper leak और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय राघव चड्ढा जी, आप इसे ऑथेंटिकेट करके यहाँ पर रखना।

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं सारी रिपोर्ट्स दूँगा।

सर, आज हम अपने देश के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, नौकरियाँ नहीं दे पाए। बेरोजगारी चरम पर है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बेरोजगारी चरम पर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़ों की क्या ही बात की जाए। सर, मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ। इस देश का वन ऑफ दि मोस्ट कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन - चार्टर्ड एकाउंटेंसी को क्लीयर करके यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है, जब आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि एक पेपर लीक हो जाता है। तब सिर्फ दिल नहीं टूटता है, बल्कि विद्यार्थी, एक इन्सान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। आज हम सबको मिलकर उस मनेबल को एड्रेस करने की आवश्यकता है। आज मैं उन युवाओं की ओर से, नीट से संबंधित उन 35 लाख स्टूडेंट्स की ओर से सरकार से पाँच सवाल पूछना चाहूँगा और पूछने से पहले यह बताना चाहूँगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम देकर जिसका गठन किया गया था कि वह युवाओं के भविष्य के लिए कुछ कारगर कदम उठाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ामिनेशन कराएगी, उस एनटीए की फुलफॉर्म आज नो ट्रस्ट एनिमोर हो गयी है। कोई भी विद्यार्थी आज इस एनटीए पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैं विद्यार्थियों की ओर ये पाँच सवाल सरकार से पूछना चाहूँगा। ये नीट से संबंधित सटीक सवाल हैं। पहला सवाल, नीट का पेपर, जिसमें मात्र एक, दो और बहुत हुआ तो तीन, चार स्टूडेट्स की रैंक वन आती है, जैसे 2023 में मात्र दो लोगों की रैंक वन आई, 2022 में मात्र चार लोगों की आई, 2021 में मात्र तीन लोगों की आई...

श्री उपसभापति: प्लीज़ कन्क्लूड करिए।

श्री राघव चड्ढा: जब इतने कम स्टूडेंट्स की रैंक वन आती है, तो इस साल 2024 के नीट के पेपर में 67 बच्चों की रैंक वन कैसे आ गई, जबकि फैकल्टी और टीचर्स यह मानते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर था।

श्री उपसभापति: कन्क्लूड, कन्क्लूड।

श्री राघव चड्ढा: सर, मेरी पार्टी का समय बचा हुआ है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, मुझे दो-तीन मिनट दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ कन्क्लूड। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा: सर, पाँच मिनट भी नहीं हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, वक्त दे दीजिए ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will move to the next speaker. Please conclude within one minute. Otherwise, I will move to the next speaker.

श्री राघव चड्ढा: सर, वक्त ऐसे मत दीजिए कि भीख लगे। ...(**व्यवधान**)... सर, वक्त ऐसे मत दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। ...(**व्यवधान**)...

सर, मेरा दूसरा सवाल है कि स्टूडेंट्स के mathematically impossible numbers आते हैं? इस एग्जाम में या तो 720 नंबर्स आएंगे, जिसके सारे जवाब सही हैं और अगर एक भी गलत हो गया, तो आप 715 नंबरो पर आ जाएंगे। इस 715 और 720 के बीच में किसी के नंबर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस बार ग्रेस मार्क्स देकर 717, 718 और 719... ...(**समय की घंटी**)... ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

श्री राघव चड्ढा: सर, मेरा आखिरी सवाल है। मैं समाप्त कर रहा हूँ। सर, इस नीट एग्जाम के नतीजे 14 जून को आने थे, उसे दस दिन पहले कर दिया गया। हम देखते हैं कि नतीजों में देरी अकसर होती है, लेकिन दस दिन पहले चुनावों के नतीजों के शोर में चार जून को नीट एग्जाम के नतीजे लाए गए। ...(**समय की घंटी**)... इसका क्या मकसद था?

श्री उपसभापति: माननीय रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव जी। राघव जी, अब रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

रेल मंत्री; **सूचना और प्रसारण मंत्री**; **तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** (**श्री अश्विनी वैष्णव**): उपसभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने जो Group 'D' Exam of Railway के बारे में

कहा है, वह factually incorrect कहा है। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता देता हूँ। सर, ग्रुप डी एग्जाम 191 सिटीज़, 551 सेंटर्स, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज़, 15 लैंग्वेजेज़ में हुआ, 1,11,00,000 एप्लीकेंट्स ने एग्जाम दिया। बिना किसी भी सिंगल शिकायत के रेलवे ने टोटल डेढ़ लाख लोगों को अप्वाइंटमेंट दी है। कृपया ये अपना वक्तव्य withdraw करें अथवा इसे expunge किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair has already directed **कि** authenticate **करके देंगे।** *...(Interruptions)...* Please. आप ऑथेंटिकेट करके देंगे। ...(**व्यवधान**)... You have raised the point, and the Minister has replied. *...(Interruptions)...* No. *...(Interruptions)...* It is not a debate, Sir. No debate. *...(Interruptions)...* You have raised the point, he has clarified it. *...(Interruptions)...* आप राइटिंग में दे दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... I have already said it; authenticate it. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* No. *...(Interruptions)...* माननीय रामजी लाल सुमन जी। *...(Interruptions)...* Not present. *...(Interruptions)...* माननीय श्री लहर सिंह सिरोया ...(**व्यवधान**)... माननीय सुमन जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, माननीय रामजी लाल सुमन जी। ...(**व्यवधान**)... You have no unlimited time, Madam. *...(Interruptions)...* उन्होंने सवाल उठाया और मंत्री जी ने क्लैरिफाई कर दिया। ...(व्यवधान)... Please. *...(Interruptions)...* रामजी लाल सुमन जी ...(**व्यवधान**)... Madam, please. *...(Interruptions)...* Time is limited. I have already given him more time. *...(Interruptions...* पहले उन्होंने रेल मंत्रालय के बारे में कहा और फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया। ...(**व्यवधान**)... It is not a debate. *...(Interruptions)...* Mr. Raghav Chadha, please speak. *...(Interruptions)...* Mr. Raghav Chadha, प्लीज़ आप अपनी बात कहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा: सर, जितनी मेरी जानकारी है, मंत्री जी वर्ष 2023-24 की परीक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उससे करीब 6 साल पहले जो रेलवे का पेपर लीक हुआ था, उस साल की परीक्षा की बात कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं सारे कागज पटल पर रख दूंगा और आपको दे दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः थैंक यू। माननीय रामजी लाल सुमन जी। ...(**व्यवधान**)... Please. *...(Interruptions)...* आपका तीन मिनट का समय है। ...(**व्यवधान**)... माननीय रामजी लाल सुमन जी ...(**व्यवधान**)... Now, no cross-talking, please. *...(Interruptions)...* तीन मिनट का समय है, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पूरी तरह से पढ़ा है। उपसभापति महोदय, सरकार की तमाम उपलब्धियों का उसमें जिक्र किया गया है। मैं आपके मार्फत बहुत ही विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा। सरकार कितने दिन चली है, यह

महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार किस दिशा में चली है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिशा में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार चली है, वह दिशा ठीक नहीं है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है, सरकार इश्तिहार से भी नहीं चलती है, बल्कि सरकार जनता के भरोसे से चलती है, विश्वास से चलती है। उपसभापति महोदय, सरकार तो बोलती है। जब कोई सरकार अच्छा काम करती है, तो लोग उसका जिक्र करते हैं। आम लोगों में उसकी चर्चा होती है और उसके चलते मैं कह सकता हूं कि आम आदमी का कोई रिश्ता नरेन्द्र मोदी जी की सरकार से नहीं है।

उपसभापति महोदय, कहा गया कि सरकार अगले पांच साल तक 81 करोड़ यानी 57 फीसदी लोगों को प्रतिमाह 5 किलो राशन देगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, लोगों के पास रोजी-रोटी का कोई जरिया नहीं है। उपसभापति महोदय, सबसे अहम सवाल यह है कि जब आप यह स्वीकार करते हैं कि इतने लोग भूखे हैं, तो आप उनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? उस दिशा में यह सरकार कोई सार्थक काम नहीं कर रही है। * आँकड़े कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के नीचे से बाहर कर दिया है, इसमें कोई सही बात नहीं है।

सभी लोगों ने ज़िक्र किया कि सरकार ने कहा कि हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। संसद के एक लिखित जवाब में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी महकमों में 9,64,359 पद खाली हैं। सरकार को कौन मना कर रहा है, वह इन पदों को क्यों नहीं भर रही है? उपसभापति महोदय, सरकार के जो रिक्त पद हैं, वे पद भरे नहीं जा रहे हैं। रेलवे ने पिछले 8 साल में 32 हजार से अधिक पद खत्म किए हैं और तय किया है कि भविष्य में इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय ने Military Engineering Service की 9,300 से अधिक नौकरियाँ खत्म की हैं।

उपसभापति महोदय, जहाँ तक कृषि का सवाल है, कृषि के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार किस गलतफहमी की शिकार है? क्या यह सही नहीं है कि उत्पादन लागत बढ़ रही है? खाद की कीमतें दो बार बढ़ी हैं, कालाबाजारी बढ़ी है। उपसभापति महोदय, यूरिया की जो 50 किलो की बोरी आती थी, वह 45 किलो की आई है, अब यह 40 किलो की हो गई है। कृषि यंत्रों पर GST लगा है। उपसभापति महोदय, लाखों की संख्या में किसानों ने आंदोलन किया, सैकड़ों किसान मारे गए। उनकी प्रमुख माँग यह थी कि MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। आपने MSP को कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी? किसान जो उत्पादन करता है, उसके उत्पाद का सही लाभ उसको मिलता नहीं है। आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप कानून नहीं बनाना चाहते हैं।

उपसभापति महोदय, 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने 121 से अधिक सरकारी उपक्रमों को बेचा है। मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक इस देश में जितने भी प्रधान मंत्री हुए, सब प्रधान मंत्रियों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया है। ये अकेले ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जो मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को भी बेच रहे हैं। महोदय, बहुत सीधा सवाल है कि आरक्षण सरकारी

* Expunged as ordered by the Chair.

सेवा में होता है। जब ये सरकारी उपक्रम बिक जाएँगे, तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने BHEL बेच दिया, आपने NTPC बेच दिया, आपने NHPC बेच दिया, आपने पवन हंस बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आपने LIC बेच दिया। उपसभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि व्यवस्थित रूप से डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसे विशेष अवसर का सिद्धांत कहते हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, यह सरकार उस आरक्षण को खत्म करने पर तुली है।

उपसभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा। 2019 के Public Enterprises Survey के मुताबिक सरकारी कंपनियों में कुल 15 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 10,40,000 स्थाई और 4,60,000 अस्थाई कर्मचारी हैं। इसमें एससी के लिए 15 परसेंट का आरक्षण है, एसटी के लिए 7.5 परसेंट का आरक्षण है और ओबीसी के लिए 27 परसेंट का आरक्षण है। कंपनियों के निजी हाथों में जाने से ये 49 परसेंट भर्तियाँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। 7 लाख लोगों के ऊपर तलवार लटकी है और जो ओबीसी के लोग हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उनकी नौकरियाँ समाप्त हो जाएँगी।

उपसभापति महोदय, मुझे माफ करिएगा, मुझे लोक सभा की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं कभी-कभी भूल जाता हूँ। उपसभापति महोदय, 14 प्रधान मंत्रियों ने कुल मिला कर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस सरकार ने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। आज देश के प्रत्येक नागरिक पर 1 लाख 40 हजार रुपए का कर्ज है।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

सरकारी कर्ज इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्च कितना है। अगर हम इसका खयाल नहीं रखेंगे, तो इसका सीधा असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा।

सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से एक और बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 'गांधी' फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। इससे ज्यादा अपमानजनक बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग महात्मा गांधी को कम जानते हैं, गोडसे को ज्यादा जानते हैं। मैं यह बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि यह लड़ाई दो धाराओं के बीच में है। एक गांधी को मानने वाले लोग हैं, दूसरे गोडसे को मानने वाले लोग हैं। मैं विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूँगा कि ये लोग गांधी को नहीं जानते। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गोडसे बनना बहुत आसान काम है, लेकिन गांधी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाएँगे, यह बात इन लोगों की समझ में आनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक गांधी का सवाल है, तो गांधी के निधन के बाद सोवियत रूस को छोड़ कर दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था, जो महात्मा गांधी के सम्मान में नहीं झुका हो। महोदय, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल काम है, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है, पद से नहीं होता। कितने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति आए, इस धरती में समा गए, कोई उनका सम्मान के साथ नाम नहीं लेता। लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी जब हिन्दुस्तान में आता है, तो वह किसी राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री की समाधि पर नहीं

जाता, उसका सिर अगर कहीं झुकता है, तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर झुकता है। गांधी से बड़ा कोई आदमी न तो दुनिया में पैदा हुआ और न हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इनको गाय बहुत प्रिय है, हमें भी गाय बहुत प्रिय है। गौ मांस या बीफ का जो निर्यात है, वह अप्रत्याशित रूप से हमारे देश में बढ़ा है। इस मामले में हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष 2024 की जो रिपोर्ट है * ...(**व्यवधान**)... महोदय, इन कम्पनियों के नाम हैं - Frigorifico Allana Ltd., Frigerio Conserva Allana, etc.

सभापति महोदय, National Testing Agency (NTA) ने नीट की परीक्षा कराई। जो सज्जन इसके चेयरमैन हैं, ये पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे और संघीय लोक सेवा आयोग के भी कर्ता-धर्ता रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक * सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दो महीने बाद, जाँच के बाद कार्रवाई होगी। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि NTA के चेयरमैन को बरखास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये परीक्षाएँ रद्द होनी चाहिए। पिछले 7 वर्षों में पेपर लीक के 70 से अधिक मामले हुए हैं, जिनसे 1 करोड़ 70 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।

सभापति महोदय, अभी हमारे मित्रों ने जिक्र किया कि अयोध्या में 'राम पथ' बैठ गया, टूट गया, जो 844 करोड़ रुपये की लागत से बना था। आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूँगा कि हम बड़े जोर-शोर से हल्ला करते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। महोदय, जब संसद भवन के नए भवन का उद्घाटन हुआ, उस समय राष्ट्रपति महोदया कहाँ थीं? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय राष्ट्रपति महोदया कहाँ थीं? इस देश में पहले जो राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, इनको भी मंदिर में घुसने में तकलीफ हुई। अगर राष्ट्रपति महोदया से राम मंदिर का उद्घाटन कराया जाता, तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता।*

सभापति महोदय, आज अजीब तमाशा है। इनके लिए 'राम' कोई श्रद्धात्म वाली चीज नहीं थी। इनके लिए 'राम' वोट का इंतजाम था। जब 'राम' वोट में मदद नहीं कर पाए, तो उन्होंने कर्णाटक में 'जय बजरंगवली' कहना शुरू कर दिया। जब उससे भी काम नहीं चला, तो 'जय जगन्नाथ' कहना शुरू कर दिया। अब ये लोग क्या-क्या कहेंगे?

''पीते पीते ज़हर-ए-ग़म, अब जिस्म नीला पड़ गया,
कुछ दिनों में देखना हम आसमां होने को हैं।''

इन लोगों की यह हालत है।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: The concluding one!

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री रामजी लाल सुमनः सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, यह सरकार बनी है और सरकार लाइक माइंडेड लोगों से बनती है, एक मिजाज़ लोगों से बनती है। इनमें एक मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने फरमाया कि 'राम' तो काल्पनिक है और 'राम' से ज्यादा श्रेष्ठ 'रावण' है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामजी लाल सुमन : सर, मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू जी कहते हैं कि चार परसेंट मुसलमानों को आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि जो मौलवी हैं, उनको पेंशन देंगे। सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। कुल मिला कर यह विरोधाभास है। आपको तो मुसलमानों के नाम से बुखार आ जाता है। आप चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस ले लीजिए। आप हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर दीजिए कि आपके मिजाज़ और हमारे मिजाज़ में तो बड़ा फर्क है, लिहाज़ा हम आपका समर्थन नहीं चाहते। लेकिन आपको तो सरकार चलानी है और सरकार चलाने के लिए संख्या चाहिए,चाहे वैचारिक दृष्टिकोण कोई भी हो।

सभापति महोदय, इस सरकार का 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। इस संबंध में मैं आपके मार्फत यह जरूर जानना चाहूँगा कि इसका समयबद्ध कार्यक्रम क्या है? कितने दिनों में ये मकान बन जाएँगे? आपने 2019 में अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि हम प्रत्येक परिवार को 2022 तक पक्का मकान दे देंगे। वह वादा पूरा नहीं हुआ।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामजी लाल सुमनः सभापति महोदय, यह दिशाहीन सरकार है और मुझे यह कहने में फ़ख्र है कि चाहे जो कुछ भी हुआ और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता ने इंडिया गठबंधन को इतना समर्थन जरूर दे दिया कि अब आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप * नहीं कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति महोदय, आज जो सरकार है, वह गठबंधन की सरकार है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति महोदय, मोदी जी कहते थे कि अकेला मोदी सब पर भारी, लेकिन अब तो रोज एनडीए की चर्चा करते हैं।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति महोदय, यह दिशाहीन सरकार है और इन्हें कुछ पता नहीं है। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ :-

"अपनी हालत का ख़ुद एहसास नहीं है मुझ को,
मैं ने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं।"

बहुत-बहुत धन्यवाद!

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, who has just spoken, is a very senior Member of the House. He was my senior Minister in 1990.

PANEL OF VICE-CHAIRPERSONS

MR. CHAIRMAN: I have to inform the hon. Members that the following Members have been nominated to the existing Panel of Vice-Chairpersons for this Session:

1. Shri Tiruchi Siva (DMK)
2. Shri Rajeev Shukla (INC)

5.00 P.M.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS — *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Lahar Singh Siroya to speak.

श्री लहर सिंह सिरोया (कर्नाटक): माननीय सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला**) *पीठासीन हुए।*]

महोदय, मेरे बोलते समय आप पधारे, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और आभार मानता हूँ। मैं इस गरिमामयी सदन में खड़े होकर खुद को सौभाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे अपनी बात रखने का अवसर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मिला है।